खडकी शिक्षण संस्थेचे
टिकाराम जगन्नाथ
कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय

प्राचार्य
डॉ. संजय चाकणे
एम.एस्सी., एम.बी.ए., पीएच.डी.

Criteria 5 Student Support And Progression

Q_nM 5.1.4 Redressal of Students grievances including sexual harassment & ragging cases

Sr. No	Document Description	Page No
1	Redressal Of Grievance Of Student Regulation 2023	1-13
2	Ant ragging Act	14-97
3	Policy Document On Grievance Redressal Mechanism For Employee And Student	98-99
4	Internal Complaint Committee	100
5	IIC Committee Details	101-109
6	Anti Ragging Committee Details	110-117
7	Student Grievance Redressal Cell	118-130

Tikaram Jagannath Arts, Com. & Science College KHADKI PUNE-3

Rajendraa
PRINCIPAL
Tikaram Jagannath Arts Commerce & Science College,Khadki,Pune-411003.

४९१, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मार्ग, खडकी, पुणे - ४११ ००३.
(सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ संलग्न-ID / PU / PN / 0146 /1983)
☎ कार्यालय : (020) 25811491 प्राचार्य : 9890171857 / 7020674545
वेबसाईट : www.tjcollege.org ई-मेल : admin@tjcollege.org / schakane@gmail.com

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11042023-245095
CG-DL-E-11042023-245095

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 233] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 11, 2023/चैत्र 21, 1945
No. 233] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 11, 2023/CHAITRA 21, 1945

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2023

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023

F.1-13/2022(CPP-II).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 26 की उप-धारा (1) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2019 के अधिक्रमण में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाता है, नामत:-

1. **संक्षिप्त नाम, विनियोग और प्रारंभ:**

(क) इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023 कहा जाएगा।

(ख) वे ऐसे सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों पर लागू होंगे, जिन्हें किसी केंद्रीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम के तहत स्थापित या निगमित गया हो और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) के तहत मान्यता-प्राप्त सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों तथा ऐसे सभी सम विश्वविद्यालय संस्थानों पर लागू होंगे जिन्हें तत्संबंध की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो।

(ग) वे शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **उद्देश्य:**

किसी संस्थान में पहले से ही नामांकित छात्रों और साथ ही ऐसे संस्थानों में प्रवेश के इच्छुक छात्रोंकी कतिपय शिकायतों के निवारण के लिए अवसर प्रदान करना और उसके लिए एक तंत्र स्थापित करना।

3. **परिभाषा:**

(1) जब तक कि इन विनियमों केसंदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) "अधिनियम" का अभिप्राय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) से है;

(ख) "पीड़ित छात्र" से अभिप्राय किसी ऐसे छात्र से है जिसे इन विनियमों के तहत परिभाषित शिकायतों के संबंध में किसी मामले अथवा तत्संबंधी किसी मामले में कोई शिकायत हो।

(ग) "महाविद्यालय" से अभिप्राय अधिनियम की धारा 12ए की उपधारा (1) के खंड (ख) में इस प्रकार से परिभाषित किसी संस्थान से है।

(घ) "आयोग" से अभिप्राय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 4 के तहत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से है।

(ङ) "घोषित प्रवेश नीति" का अभिप्राय संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे किसी पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश के लिए संस्थान की विवरणिका में प्रकाशित की गई किसी ऐसी नीति से है, जिसमें उसके अंतर्गत आने वाली प्रक्रियाएं भी शामिल हैं।

(च) "शिकायत" का अभिप्राय, और इसमें निम्नवत् के संबंध में किसी पीड़ितछात्र द्वारा की गई शिकायत (शिकायतें) शामिल हैं, नामत:

i. संस्थान की घोषित प्रवेश नीति के अनुरूप निर्धारित की गई योग्यता के विपरीत प्रवेश दिया जाना;

ii. संस्थान की घोषित प्रवेश नीति के तहत प्रक्रिया में अनियमितताएं;

iii. संस्थान की घोषित प्रवेश नीति के अनुरूप प्रवेश देने से इंकार किया जाना;

iv. इन विनियमों के उपबंधों के अनुरूप, संस्थान द्वारा विवरणिका का प्रकाशन न किया जाना;

v. संस्थान द्वारा विवरणिका में ऐसी कोई जानकारी देना जोकि झूठी या भ्रामक होऔर तथ्यों पर आधारित न हो;

vi. किसी छात्र द्वारा ऐसे संस्थान में प्रवेश लेने के प्रयोजन से जमा किए गए किसी दस्तावेज जोकि उपाधि, डिप्लोमा या किसी अन्य पुरस्कार के रूप में हो,उसको अपने पास रख लेना या वापस करने से इंकार करना ताकि ऐसे किसी पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम के संबंध में छात्र को किसी शुल्क अथवा शुल्कों का भुगतान करने हेतु तैयार किया जा सके अथवा मजबूर किया जा सकें जिसमें छात्र अध्ययन नहीं करना चाहता हो;

vii. संस्थान की घोषित प्रवेश नीति में निर्धारित राशि से अधिक धनराशि की मांग करना।

viii. छात्रों की विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रवेश में सीटों के आरक्षण के संबंध में वर्तमान में लागू किसी कानून का संस्थान द्वारा उल्लघंन किया जाना;

ix. ऐसे किसी संस्थान की घोषित प्रवेश नीति के तहतअथवा आयोग द्वारा विहित किन्हीं शर्तों, यदि कोई हो तो, के तहत किसी भी छात्र हेतु ग्राह्य छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता का भुगतान नहीं किया जाना अथवा विलम्ब से भुगतान किया जाना;

x. संस्थान के शैक्षणिक कैलेंडर मेंअथवा आयोग द्वारा विहित ऐसे किसी कैलेंडर में विनिर्दिष्ट अनुसूची से इतर परीक्षाओं के आयोजन मेंअथवा परीक्षा के परिणामों की घोषणा में विलम्ब करना;

xi. विवरणिका में यथा उल्लिखितअथवा संस्थान द्वारा लागू किसी कानून के किसी उपबंध के तहत यथा अपेक्षित छात्रोंकी सुविधा प्रदान करने में संस्थान द्वारा विफल रहना;

xii. छात्रोंके मूल्यांकन के लिए संस्थान द्वारा अपनाई गई गैर-पारदर्शी अथवा अनुचित पद्धतियां;

xiii. ऐसे किसी छात्र को शुल्क के प्रतिदाय में विलंब करना, अथवा इंकार करना जो कि विवरणिका में उल्लिखित समय के भीतर, बशर्ते यह समय समय पर आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अधीन हो, नामांकन वापस लेता है;

xiv. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक अथवा दिव्यांग श्रेणियों के छात्रोंसे कथित भेदभाव की शिकायत;

xv. प्रवेश दिए जाने के समय जैसा भरोसा दिलाया गया था अथवा प्रदान किया जाना अपेक्षित था के अनुरुप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं किया जाना;

xvi. छात्र के उत्पीड़न के अन्य मामलों के अलावा जिन पर वर्तमान में लागू किसी कानून के दंडात्मक उपबंधो के तहत कार्रवाई की जानी हो, छात्र का उत्पीड़न किया जाना अथवा उसे निशाना बनाया जाना।

xvii. संस्थान के कानूनों, अध्यादेशों,नियमों, विनियमों, या दिशा -निर्देशों के विपरीत कोई कार्रवाई किया जाना अथवा शुरू किया जाना; तथा

xviii. आयोग और/अथवा संबंधित नियामक निकाय द्वारा बनाए गए/जारी किए गए नियमों और/या दिशा -निर्देशों के विपरीत कोई भी कार्रवाई किया जाना अथवा शुरू किया जाना।

(छ) "संस्थान" से तात्पर्य विश्वविद्यालय से है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम कीधारा 2 की उप-धारा (एफ)में परिभाषित है, एक संस्थान जिसे अधिनियम3 के तहत विश्वविद्यालय माना गया हैऔर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 कीधारा12ए (1) (बी) में परिभाषित एक महाविद्यालय से है।

(ज) "लोकपाल" का अभिप्राय इन विनियमों के तहत नियुक्त लोकपाल से है।

(झ) "विवरणिका" का अभिप्राय और इसमें ऐसा कोई प्रकाशन शामिल है, चाहे वह मुद्रित स्वरूप में अथवा अन्यथा हो, जिसे जनसाधारण (जिसमें ऐसे संस्थान में प्रवेश पाने के इच्छुकों सहित) को एक संस्था से संबंधित निष्पक्ष और पारदर्शी जानकारी प्रदान करने के लिए ऐसे संस्थान अथवा किसी प्राधिकरण अथवा ऐसे संस्थान द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति द्वारा जारी किया गया हो;

(ञ) "छात्र"से अभिप्राय किसी ऐसे संस्थान जिसमें यह विनियम लागू होते हैं,में किसी भी माध्यम से अर्थात औपचारिक/मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल)/ऑनलाइन से नामांकित किसी व्यक्ति अथवा नामांकित होने के लिए प्रवेश प्राप्ति के इच्छुक से हैं;

(ट) "छात्र शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी)" का अभिप्राय एक संस्थान के स्तर पर इन विनियमों के तहत गठित एक समिति से है; तथा

(ठ) "विश्वविद्यालय" से अभिप्राय अधिनियम की धारा 2 की खंड (च) में यथा परिभाषित किसी विश्वविद्यालय से हैअथवा जहां संदर्भ के अनुसार,तत्संबंध की धारा 3 के तहत इस प्रकार घोषित कोई सम विश्वविद्यालय संस्थान से है।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः अधिनियम में उनके लिए निर्धारित किए गए हैं।

4. विवरणिका का अनिवार्य प्रकाशन, इसकी विषयवस्तु तथा मूल्य निर्धारण

(1) प्रत्येक संस्थान, अपने पाठ्यक्रम या अध्ययन के किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश आरंभ करने की तिथि से कम से कम साठ दिन की समाप्ति से पूर्व अपनी वेबसाइट पर एक विवरणिका प्रकाशित और/अथवा अपलोड करेगा, जिसमें इस तरह के संस्थान में प्रवेश लेने के इच्छुक व्यक्तियों और आम जनता की जानकारी के लिए निम्नवत् जानकारी अंतर्विष्ट होगी, यथा;

(क) प्रत्येक पाठ्यक्रम अथवा अध्ययन के कार्यक्रम के लिए, शिक्षण के घंटों, व्यावहारिक सत्रों और अन्य कार्य के साथ-साथ अध्ययन के कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों की सूची सहित उपयुक्त सांविधिक प्राधिकरण अथवा संस्थान, जैसा भी मामला हो, द्वारा विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम की व्यापक रूपरेखा:

(ख) जिस शिक्षा वर्ष हेतु प्रवेश दिए जाने का प्रस्ताव हो, उसके प्रत्येक पाठ्यक्रम अथवा अध्ययन के कार्यक्रम के संबंध मेंउपयुक्त सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित सीटों की संख्या;

(ग) संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट किसी विशेष पाठ्यक्रम अथवा अध्ययन कार्यक्रम में छात्र के रूप में प्रवेश के लिए व्यक्तियों की न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा सहित शैक्षिक योग्यता और पात्रता की शर्तें:

(घ) इस प्रकार के प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले योग्य उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया, जिसमें प्रत्येक पाठ्यक्रम अथवा अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश के लिए ऐसे अभ्यर्थियों के चयन के लिए परीक्षा या इम्तहान के विवरण के संबंध में सभी संगत जानकारी और प्रवेश परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क की राशि शामिल है;

(ङ) किसी पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम में अध्ययन करने के लिए ऐसे संस्थान में भर्ती किए गए छात्रों द्वारा देय शुल्क, जमा राशियों और अन्य प्रभारों के प्रत्येक घटक और ऐसे भुगतानों की अन्य निबंधन और शर्तें:

(च) शास्ति लगाए जाने और संग्रहण किए जाने हेतु नियम/विनियम, विनिर्दिष्ट शीर्ष अथवा श्रेणियां, लगाए जाने वाली शास्ति की न्यूनतम और अधिकतम राशि;

(छ) ऐसे संस्थानों में दाखिला लेने वाले छात्रों द्वारा यदि पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम के पूरा होने से पहले अथवा के बाद दाखिला छोड़ दिया जाता है तो छात्रोंको प्रतिदाय किए जाने वाले शिक्षण शुल्क और अन्य प्रभारों का प्रतिशत तथा समय सीमा जिसके भीतर तथा पद्धति जिससे छात्रोंको ऐसा प्रतिदाय किया जाएगा;

(ज) उनकी शैक्षिक योग्यता शिक्षण संकाय का विवरण, उनकी नियुक्ति का स्वरूप (नियमित/अभ्यागत/अतिथि) और उसके प्रत्येक सदस्य के शिक्षण अनुभव के साथ;

(झ) भौतिक और शैक्षणिक बुनियादी ढांचे और छात्रावास तथा इसके शुल्क, पुस्तकालय, चिकित्सालय अथवा उद्योग, जहां छात्रोंको व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाना हो, सहित अन्य सुविधाओं के संबंध में जानकारी और विशेषरूप से छात्रों द्वारा संस्थान में प्रवेश प्राप्त करने पर प्राप्त होने वाली सुविधाओं का ब्यौरा अंतर्विष्ट हो;

(ञ) संस्थान के परिसर के भीतर अथवा बाहर छात्रोंद्वारा अनुशासन बनाए रखने के संबंध में सभी संगत निदेशऔर विशेषरूप से किसी छात्र अथवा छात्रों की रैगिंग निषिद्ध करने संबंधी ऐसेअनुशासन को बनाए रखने और उनका उल्लघंन किए जाने के परिणामों और संगत सांविधिक विनियामक प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में तैयार किए गए किसी विनियम के उपबंधों का उल्लघंन किए जाने के परिणामों का ब्योरा अंतर्विष्ट होगा; तथा

(ट) आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य जानकारी:

बशर्ते प्रत्येक संस्थान इस विनियम के खंड (क) से (ट) में उल्लिखित जानकारी को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित/अपलोड करेगाऔर विभिन्न समाचार -पत्रों और अन्य मीडिया के माध्यम से प्रमुखता से प्रदर्शित करते हुए विज्ञापनों के माध्यम से इच्छुक छात्रों और आम जनता का ध्यान वेबसाइट पर इस तरह के प्रकाशन की ओर दिलाया जाएगा।

2. प्रत्येक संस्थान अपनी विवरणिका की प्रत्येक मुद्रित प्रति का मूल्य निर्धारित करेगा, जोकि विवरणिका के प्रकाशन और वितरण की उचित लागत से अधिक नहीं होगी और विवरणिका के प्रकाशन, वितरण या बिक्री से कोई लाभ अर्जित नहीं किया जायेगा।

5. छात्र शिकायत निवारण समितियां (एसजीआरसी)

(i) संस्थान से संबंधित किसी पीड़ित छात्र की किसी भी शिकायत छात्र शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी) के अध्यक्ष को संबोधित की जाएगी।

(ii) प्रत्येक संस्थान छात्रोंकी शिकायतों पर विचार करने के लिए निम्नलिखित संरचना के साथ उतनी संख्या में छात्रों की शिकायत निवारण समितियों (एसजीआरसी) का गठन करेगा, जितने किआवश्यकता हो सकती है, नमात;

क) एक प्रोफेसर – अध्यक्ष

ख) संस्थान के चार प्रोफेसर/वरिष्ठ संकाय सदस्य- सदस्य के रूप में।

ग) शैक्षिक योग्यता/खेल -कूद में उत्कृष्टता/सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों में प्रदर्शन के आधार पर नामित किए जाने वाले छात्रोंमें से एक प्रतिनिधि- विशेष आमंत्रित।

घ) अध्यक्ष अथवा कम से कम एक सदस्य का महिला होना चाहिए तथा कम से कम एक सदस्य अथवा अध्यक्ष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से होना चाहिए।

ङ) अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

च) विशेष आमंत्रित सदस्य का कार्यकाल एक वर्ष का होगा।

छ) बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित लेकिन विशेष आमंत्रित व्यक्ति को छोड़ कर तीन का होगा।

ज) एसजीआरसी अपने समक्ष आने वाली शिकायतों पर विचार करते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेगा।

झ) एसजीआरसी अपनी रिपोर्ट सिफारिशों के साथ, यदि कोई हो, संबंधित संस्था के सक्षम प्राधिकारी को भेजेगा और उसकी एक प्रति पीड़ित छात्र को, अधिमानतः शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 15 कार्य दिवसों की अवधि के अंदर भेजेगा।

ञ) छात्रों की शिकायत निवारण समिति के निर्णय से पीड़ित कोई भी छात्र इस प्रकार के निर्णय की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर लोकपाल के समक्ष अपील कर सकता है।

6. लोकपाल की नियुक्ति, सेवाकाल, पद से हटाया जाना और सेवा की शर्तें:

(i) प्रत्येक विश्वविद्यालय इन विनियमों के तहत विश्वविद्यालय के छात्रों और महाविद्यालय /विश्वविद्यालय से जुड़े संस्थानों के छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए लोकपाल की नियुक्ति करेगा।

(ii) एसजीआरसी के निर्णयों के विरुद्ध की गई अपीलों को सुनने और उन पर निर्णय लेने के लिए लोकपाल के रूप में नामित एक या अधिक अंशकालिक पदाधिकारी होंगे।

(iii) लोकपाल सेवानिवृत्त कुलपति या सेवानिवृत्त प्रोफेसर (जिन्होंने अधिष्ठाता (डीन)/विभाग प्रमुख के रूप में काम किया हो) होंगे और उनके पास राज्य/केंद्रीय विश्वविद्यालयों/राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों/सम विश्वविद्यालयों या पूर्व जिले में न्यायाधीश के रूप में 10 वर्ष का अनुभव रहा हो।

(iv) लोकपालनियुक्ति के समय, नियुक्ति से पहले एक वर्ष के दौरानया लोकपाल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, संस्थान के साथ हितों के टकराव में नहीं होंगे जहाँ उनके व्यक्तिगत संबंध, पेशेवर संबद्धता या वित्तीय हित समझौता कर सकते हैं या उचित रूप से संस्थान के प्रति निर्णय की स्वतंत्रता से समझौता करने के लिए प्रतीत हो सकते हैं।

(v) लोकपाल को पद ग्रहण करने की तिथि सेतीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाएगाऔर एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(vi) सुनवाई का संचालन करने के लिएलोकपाल को संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्रति दिनप्रति बैठक के अधार पर शुल्क का भुगतान किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, वे यात्रा पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे।

(vii) कदाचार या दुर्व्यवहार के सिद्ध आरोपों पर विश्वविद्यालय लोकपाल को पद से हटा सकता है।

(viii) लोकपाल को हटाने का कोई भी आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि इस संबंध में किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जांच नहीं कर ली जाती है, जो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के पद से नीचे के पद का व्यक्ति ना हो, और जिसमें लोकपाल को सुनवाई का उचित अवसर दिया गया हो।

7. लोकपाल के कार्यकरण:

(i) लोकपाल, छात्र द्वारा इन विनियमों के तहत उपबंधित सभी विकल्पों को अपनाने के पश्चात् ही पीड़ितछात्र की अपील की सुनवाई करेंगे।

(ii) यद्यपि, परीक्षा के संचालन में अथवा मूल्यांकन की प्रक्रिया में गड़बड़ी के मुददों को लोकपाल को संदर्भित किया जा सकता है, तथापि, लोकपाल द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के पुर्नमूल्यांकन अथवा अंको को पुनः योग करने हेतु कोई अपील अथवा आवेदन पर लोकपाल द्वारा सुनवाई नहीं की जाएगी, जब तक कि भेदभाव की किसी विशिष्ट घटना के परिणामों को प्रभावित करने वाली किसी विशिष्ट अनियमितता को इंगित नहीं किया जाता है।

(iii) लोकपाल, कथित रूप से किए गए भेदभाव की शिकायतों की सुनवाई करने के लिएन्याय मित्र के रूप में किसी भी व्यक्ति की सहायता प्राप्त कर सकता है।

(iv) लोकपाल पीड़ितछात्र (छात्रों)से अपील प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर शिकायतों का समाधान करनेके लिए सभी प्रयास करेंगे।

8. लोकपाल तथा छात्र शिकायत निवारण समितियों द्वारा शिकायतों के निवारण हेतु प्रक्रिया

(i) प्रत्येक संस्थान,इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर एक ऑनलाइनपोर्टल तैयार करेगा, जहां कोई भी पीड़ितछात्र अपनी शिकायत के निवारण के लिए आवेदन कर सकता है।

(ii) ऑनलाइन शिकायत प्राप्त होने पर संस्थान, ऑनलाइन शिकायत की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतरअपनी टिप्पणियों सहित शिकायत को उपर्युक्त छात्र शिकायत निवारण समिति को भेजेगा।

(iii) छात्र शिकायत समिति, जैसा भी मामला हो, शिकायत की सुनवाई के लिए एक तिथि निर्धारित करेगी जिसकी जानकारी संस्थान और पीड़ितछात्र को दी जाएगी।

(iv) पीड़ित छात्र या तो व्यक्तिगत रूप से पेश हो सकता है अथवा अपना पक्ष रखने के लिए अपने किसीप्रतिनिधि को अधिकृत कर सकता है।

(v) छात्र शिकायत निवारण समिति द्वारा समाधान नहीं की गई शिकायतों को इन विनियमों में उपबंधित समयावधि के भीतर लोकपाल को भेजा जाएगा।

(vi) संस्थान, शिकायतों के शीघ्र निपटान हेतुलोकपाल अथवा छात्र शिकायत निवारण समिति (समितियों), जैसा भी मामला हो, कासहयोग करेगें।

(vii) लोकपाल, संबंधित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, कार्यवाही के समापन पर, तत्संबंधी कारणों के साथ, इस प्रकार का आदेश पारित करेगा, जैसा कि शिकायत के निवारण के लिए उपयुक्त समझा जा सकता है और ऐसी राहत प्रदान कर सकता है जो पीड़ित छात्र के लिए उपयुक्त हो सकती है।

(viii) संस्थान के साथ ही साथ पीड़ितछात्र को लोकपाल के हस्ताक्षर के तहत जारी की गई आदेश की प्रतियां उपलब्ध कराई जाएंगी।

(ix) संस्थान, लोकपाल की सिफारिशों का अनुपालन करेगा।

(x) जहां शिकायत झूठी या तुच्छ पाई जाती है उस स्थिति में लोकपाल शिकायतकर्ता के विरूद्ध उपर्युक्त कार्रवाई किए जाने की सिफारिश कर सकता है।

9. लोकपाल और छात्र शिकायत निवारण समितियों के संबंध में जानकारी:

संस्थान अपनी वेबसाइट और अपनी विवरणिका में स्पष्ट रूप से इसके क्षेत्राधिकार में आने वाली छात्र शिकायत निवारण समिति(समितियों) तथा अपील किए जाने के प्रयोजनार्थ लोकपाल के संबंध में सभी संगत जानकारियां उपलब्ध कराएगा।

10. अनुपालन नहीं किए जाने के परिणाम

आयोग, किसी भी सस्थान के सबध में, जो जानबूझकर इन विनियमों का उल्लंघन करते हैं अथवा बार-बार लोकपाल या छात्र शिकायत निवारण समितियों की सिफारिश का पालन करने में विफल रहते हैं, जैसा भी मामला हो, जब तक संस्थान आयोग की संतुष्टि तक इन विनियमों का अनुपालन नहीं करता है, तब तक संस्थान के विरूद्ध निम्नवत् एक या एक से अधिक कार्यवाहियां की जा सकती हैं,

क) अधिनियम की धारा 12बी के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए उपयुक्तता की घोषणा को वापस लेना;

ख) संस्थान को आवंटित किसी अनुदान को रोका जा सकता है;

ग) आयोग के किसी भी सामान्य अथवा विशेष सहायता कार्यक्रम के तहत किसी भी सहायता को प्राप्त करने हेतु विचार किए जाने के लिए संस्थान को अयोग्य घोषित करना;

घ) संस्थान को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए ऑनलाइन/मुक्त ओर दूरस्थ शिक्षा माध्यम से पाठ्यक्रम की पेशकश करने के लिए अयोग्य घोषित करना;

ङ) ऑनलाइन/ मुक्त ओर दूरस्थ शिक्षा माध्यम से पाठ्यक्रमों की पेशकश करने की स्वीकृति को वापस लेना/रोकना/निलंबित करना;

च) उपयुक्त मीडिया में प्रमुखता से प्रदर्शित कर और आयोग की वेबसाइट पर पोस्ट कर प्रवेश हेतु संभावित अभ्यर्थियों सहित जनसाधारण को सूचित करनातथा इस बाबत घोषणा करना कि संस्थान में शिकायतों के निवारण के लिए न्यूनतम मानक मौजूद नहीं हैं।;

छ) महाविद्यालय के मामले में, संबद्धता को वापस लेने के लिए संबद्ध विश्वविद्यालय को सिफारिश करना;

ज) सम विश्वविद्यालय संस्थान के मामले में ऐसी कार्रवाई करना, जो आवश्यक, उचित एवं उपयुक्त हो;

झ) सम विश्वविद्यालय संस्थान के मामले में सम विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषणा को वापस लिए जाने के लिए, यदि आवश्यक हो तो, केंद्र सरकार को सिफारिश करना;

ञ) राज्य अधिनियम के अंतर्गत स्थापित अथवा निगमित विश्वविद्यालय के मामले में राज्य सरकार को आवश्यक एवं उचित कार्रवाई करने की सिफारिश करना;

ट) गैर अनुपालना के लिए संस्थान के प्रति ऐसी कार्रवाई करना जो आवश्यक एवं उपयुक्त समझी जाए।

बशर्ते इन विनियमों के अंतर्गत आयोग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब तक कि संस्थान को अपनी स्थिति को स्पष्ट करने एवं उसके पक्ष को सुने जाने का अवसर नहीं दिया गया हो।

11. इन विनियमों में उल्लिखित कोई भी शर्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रोंकी शिकायत निवारण) विनियम, 2019 के प्रावधानोंके अंतर्गत नियुक्त किसी पदधारी लोकपाल के कार्यकाल की अवधि के दौरान उसके पद पर बने रहने को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगी; कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् लोकपाल की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) के विनियम, 2023 के अनुरूप की जाएगी।

प्रा. मनिष र. जोशी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./13/2023-24]

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2023

University Grants Commission (Redressal of Grievances of Students) Regulations, 2023

F.1-13/2022 (CPP-II).— In exercise of the powers conferred under clause (g) of sub-section (1) of Section 26 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), and in supersession of the University Grants Commission (Redress of Grievances of Students) Regulations, 2019, the University Grants Commission hereby makes the following regulations, namely -

1. SHORT TITLE, APPLICATION,AND COMMENCEMENT:

(a) These regulations shall be called as the University Grants Commission (Redressal of Grievances of Students) Regulations, 2023.

(b) They shall apply to all higher education institutions, whether established or incorporated by or under a Central Act or a State Act, and every institution recognized by the University Grants Commission under clause (f) of Section 2 of the University Grants Commission Act, 1956 and to all institutions deemed to be a University declared as such under Section 3 therein and to all higher education institutions affiliated to a University.

(c) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. OBJECTIVE

To provide opportunities for redressal of certain grievances of students already enrolled in any institution, as well as those seeking admission to such institutions, and a mechanism thereto.

3. DEFINITION:

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires-

(a) "Act" means the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956);

(b) "aggrieved student" means a student, who has any complaint in the matters relating to or connected with the grievances defined under these regulations.

(c) "college" means any institution, so defined in clause (b) of sub-section (1) of section 12A of the Act.

(d) "Commission" means the University Grants Commission established under section 4 of the UGC Act, 1956.

(e) "declared admission policy" means such policy, including the process there under, for admission to a course or program of study as may be offered by the institution by publication in the prospectus of the institution.

(f) "grievance" means, and includes, complaint(s) made by an aggrieved student in respect of the following, namely:

i. admission contrary to merit determined in accordance with the declared admission policy of the institution;

ii. irregularity in the process under the declared admission policy of the institution;

iii. refusal to admit in accordance with the declared admission policy of the institution;

iv. non-publication of a prospectus by the institution, in accordance with the provisions of these regulations;

v. publication by the institution of any information in the prospectus, which is false or misleading, and not based on facts;

vi. withholding of, or refusal to return, any document in the form of certificates of degree, diploma or any other award or other document deposited by a student for the purpose of seeking admission in such institution, with a view to induce or compel such student to pay any fee or fees in respect of any course or program of study which such student does not intend to pursue;

vii. demand of money in excess of that specified to be charged in the declared admission policy of the institution;

viii. violation, by the institution, of any law for the time being in force in regard to reservation of seats in admission to different category of students;

ix. non-payment or delay in payment of scholarships or financial aid admissible to any student under the declared admission policy of such institution, or under the conditions, if any, prescribed by the Commission;

x. delay by the institution in the conduct of examinations, or declaration of results, beyond the schedule specified in the academic calendar of the institution, or in such calendar prescribed by the Commission;

xi. failure by the institution to provide student amenities as set out in the prospectus, or is required to be extended by the institution under any provisions of law for the time being in force;

xii. non-transparent or unfair practices adopted by the institution for the evaluation of students;

xiii. delay in, or denial of, the refund of fees due to a student who withdraws admission within the time mentioned in the prospectus, subject to guidelines, if any, issued by the Commission, from time to time;

xiv. complaints of alleged discrimination of students from the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Women, Minorities or persons with disabilities categories;

xv. denial of quality education as promised at the time of admission or required to be provided;

xvi. harassment or victimization of a student, other than cases of harassment, which are to be proceeded against under the penal provisions of any law for the time being in force;

xvii. any action initiated/taken contrary to the statutes, ordinances, rules, regulations, or guidelines of the institution; and,

xviii. any action initiated/taken contrary to the regulations and/or guidelines made/issued by the Commission and/or the regulatory body concerned.

(g) "Institution" means a university as defined in sub-section (f) of Section 2 of the UGC Act, an institution declared as institution deemed to be university under Section 3 of the Act, and a college as defined under section 12A (1) (b) of the University Grants Commission Act, 1956.

(h) "Ombudsperson" means the Ombudsperson appointed under these regulations;

(i) "Prospectus" means and includes any publication, whether in print or otherwise, issued for providing fair and transparent information, relating to an institution, to the general public (including to those seeking admission in such institution) by such institution or any authority or person authorized by such institution to do so;

(j) "Student" means a person enrolled, or seeking admission to be enrolled, in any institution, to which these regulations apply, through any mode i.e., Formal / Open and Distance Learning (ODL) / Online;

(k) "Students' Grievance Redressal Committee (SGRC)" means a committee constituted under these regulations, at the level of an institution; and

(l) "University" means a University so defined in clause (f) of section 2 of the Act or, where the context may be, an institution deemed to be University declared as such under Section 3 thereof.

(2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the University Grants Commission Act, 1956 shall have the same meanings as respectively assigned to them in the Act.

4. MANDATORY PUBLICATION OF PROSPECTUS, ITS CONTENTS, AND PRICING:

(1) Every institution, shall publish and/or upload on its website, before expiry of at least sixty days prior to the date of the commencement of the admission to any of its courses or programs of study, a prospectus containing the following for the information of persons intending to seek admission to such institution and the general public, namely:

(a) the list of programs of study and courses offered along with the broad outlines of the syllabus specified by the appropriate statutory authority or by the institution, as the case may be, for every course or program of study, including teaching hours, practical sessions and other assignments;

(b) the number of seats approved by the appropriate statutory authority in respect of each course or program of study for the academic year for which admission is proposed to be made;

(c) the conditions of educational qualifications and eligibility including the minimum and maximum age limit of persons for admission as a student in a particular course or program of study, specified by the institution;

(d) the process of selection of eligible candidates applying for such admission, including all relevant information in regard to the details of test or examination for selecting such candidates for admission to each course or program of study and the amount of fee prescribed for the admission test;

(e) each component of the fee, deposits and other charges payable by the students admitted to such institution for pursuing a course or program of study, and the other terms and conditions of such payment;

(f) rules/regulations for imposition and collection of any fines in specified heads or categories, minimum and maximum fines may be imposed;

(g) the percentage of tuition fee and other charges refundable to a student admitted in such institution in case such student withdraws from such institution before or after completion of course or program of study and the time within and the manner in which such refund shall be made to that student;

(h) details of the teaching faculty, including their educational qualifications, along with their type of appointment (Regular/visiting/guest) and teaching experience of every member thereof;

(i) information with regard to physical and academic infrastructure and other facilities including hostel accommodation and its fee, library, hospital, or industry wherein the practical training is to be imparted to the students and in particular the amenities accessible by students on being admitted to the institution;

(j) all relevant instructions in regard to maintaining the discipline by students within or outside the campus of the institution, and, in particular such discipline relating to the prohibition of ragging of any student or students and the consequences thereof and for violating the provisions of any regulation in this behalf made by the relevant statutory regulatory authority; and

(k) Any other information as may be specified by the Commission.

Provided that an institution shall publish/upload information referred to in clauses *(a)* to (k) of this regulation, on its website, and the attention of prospective students and the general public shall be drawn to such publication being on the website through advertisements displayed prominently indifferent newspapers and through other media.

(2) Every institution shall fix the price of each printed copy of the prospectus, being not more than the reasonable cost of its publication and distribution and no profit be made out of the publication, distribution, or sale of prospectus.

5. STUDENT GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEES (SGRC):

(i) A complaint from an aggrieved student relating to the institution shall be addressed to the Chairperson, Students' Grievance Redressal Committee (SGRC).

(ii) Every Institution shall constitute such number of Students' Grievance Redressal Committees (SGRC), as may be required to consider grievances of the students, with the following composition, namely:

a) A Professor - Chairperson

b) Four Professors/Senior Faculty Members of the Institution as Members.

c) A representative from among students to be nominated on academic merit/excellence in sports/performance in co-curricular activities-Special Invitee.

(iii) Atleast one member or the Chairperson shall be a woman and atleast one member or the Chairperson shall be from SC/ST/OBC category.

(iv) The term of the chairperson and members shall be for a period of two years.

(v) The term of the special invitee shall be one year.

(vi) The quorum for the meeting including the Chairperson, but excluding the special invitee, shall be three.

(vii) In considering the grievances before it, the SGRC shall follow principles of natural justice.

(viii) The SGRC shall send its report with recommendations, if any, to the competent authority of the institution concerned and a copy thereof to the aggrieved student, preferably within a period of 15 working days from the date of receipt of the complaint.

(ix) Any student aggrieved by the decision of the Students' Grievance Redressal Committee may prefer an appeal to the Ombudsperson, within a period of fifteen days from the date of receipt of such decision.

6. APPOINTMENT, TENURE, REMOVAL AND CONDITIONS OF SERVICES OF OMBUDSPERSON:

(i) Each University shall appoint Ombudsperson for redressal of grievances of students of the university and colleges/institutions affiliated with the university under these regulations.

(ii) There shall be one or more part-time functionaries designated as Ombudspersons to hear, and decide on, appeals preferred against the decisions of the SGRCs.

(iii) The Ombudsperson shall be a retiredVice-Chancellor or a retired Professor (who has worked as Dean/HOD) and has 10 years' experience as a Professor at State/Central Universities/Institutions of National Importance/Deemed to be Universities or aformer District Judge.

(iv) The Ombudsperson shall not, at the time of appointment, during one year before appointment, or in the course of his/her tenure as Ombudsperson, be in conflict of interest with the Institution where his/her personal relationship, professional affiliations or financial interest may compromise or reasonably appear to compromise, the independence of judgment towards the Institution.

(v) The Ombudsperson shall be appointed for a period of three years or until he/she attains the age of 70 years, whichever is earlier, from the date of assuming office, and shall be eligible for reappointment for another one term.

(vi) For conducting the hearings, the Ombudsperson shall be paid a sitting fee, per diem, in accordance with the norms fixed by the respective university and shall, in addition, be eligible for reimbursement of the expenditure incurred on conveyance.

(vii) The University may remove the Ombudsperson from office, on charges of proven misconduct or misbehaviour.

(viii) No order of removal of Ombudsperson shall be made except after an inquiry made in this regard by a person, not below the rank of a retired judge of the High Court in which a reasonable opportunity of being heard is given to the Ombudsperson.

7. FUNCTIONS OF OMBUDSPERSON:

(i) The Ombudsperson shall hear appeals from an aggrieved student, only after the student has availed all other remedies provided under these regulations.

(ii) While issues of malpractices in the conduct of examination or in the process of evaluation may be referred to the Ombudsperson, no appeal or application for revaluation or re-totalling of answer sheets from an examination, shall be entertained by the Ombudsperson unless specific irregularity materially affecting the outcome or specific instance of discrimination is indicated.

(iii) The Ombudsperson may avail assistance of any person, as amicus curiae, for hearing complaints of alleged discrimination.

(iv) The Ombudsperson shall make all efforts to resolve the grievances within a period of 30 days of receiving the appeal from the aggrieved student(s).

8. PROCEDURE FOR REDRESSAL OF GRIEVANCES BY OMBUDSPERSONS AND STUDENT GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEES:

(i) Each institution shall, within a period of three months from the date of issue of this notification, have an online portal where any aggrieved student may submit an application seeking redressal of grievance.

(ii) On receipt of an online complaint, the institution shall refer the complaint to the appropriate Students' Grievance Redressal Committee, along with its comments within 15 days of receipt of complaint on the online portal.

(iii) The Students' Grievance Redressal Committee, as the case may be, shall fix a date for hearing the complaint which shall be communicated to the institution and the aggrieved student.

(iv) An aggrieved student may appear either in person or authorize a representative to present the case.

(v) Grievances not resolved by the Students' Grievance Redressal Committee within the time period provided in these regulations may be referred to the Ombudsperson by the university.

(vi) Institutions shall extend co-operation to the Ombudsperson or the Student Grievance Redressal Committee(s), in early redressal of grievances.

(vii) The Ombudsperson shall, after giving reasonable opportunities of being heard to the parties concerned, on the conclusion of proceedings, pass such order, with reasons thereof, as may be deemed fit to redress the grievance and provide such relief as may be appropriate to the aggrieved student

(viii) The institution, as well as the aggrieved student, shall be provided with copies of the order under the signature of the Ombudsperson.

(ix) The institution shall comply with the recommendations of the Ombudsperson.

(x) The Ombudsperson may recommend appropriate action against the complainant, where a complaint is found to be false or frivolous.

9. INFORMATION REGARDING OMBUDSPERSONS AND STUDENT GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEES:

An institution shall furnish, prominently, on its website and in its prospectus, all relevant information in respect of the Students' Grievance Redressal Committee(s) coming in its purview, and the Ombudsperson for the purpose of appeals.

10. CONSEQUENCES OF NON-COMPLIANCE:

The Commission shall in respect of any institution, which wilfully contravenes these regulations or repeatedly fails to comply with the recommendation of the Ombudsperson or the Students' Grievance Redressal Committee, as the case may be, proceed to take one or more of the following actions till the institution complies with these Regulations to the satisfaction of the Commission, namely:

(a) withdrawal of declaration of fitness to receive grants under section 12B of the Act;

(b) withholding any grant allocated to the Institution;

(c) declaring the institution ineligible for consideration for any assistance under any of the general or special assistance programs of the Commission;

(d) declaring the institution ineligible to offer courses through Online/ODL mode for a specified period;

(e) withdrawing / withholding / suspending the approval for offering courses through Online/ODL mode;

(f) informing the general public, including potential candidates for admission, through a notice displayed prominently in suitable media and posted on the website of the Commission, declaring that the institution does not possess the minimum standards for redressal of grievances;

(g) recommend to the affiliating University for withdrawal of affiliation, in case of a college;

(h) take such action as it may deem necessary, appropriate and fit, in case of an institution deemed to be University;

(i) recommend to the Central Government, if required, for withdrawal of declaration as institution deemed to be a University, in case of an institution deemed to be University;

(j) recommend to the State Government to take necessary and appropriate action, in case of a University established or incorporated under a State Act;

(k) such other action as may be deemed necessary and appropriate against an institution for non-compliance

Provided that no action shall be taken by the Commission under this regulation, unless the institution has been provided an opportunity of being heard to explain its position.

11. Nothing mentioned herein above in these regulations shall affect the continuance in office, during the currency of the term, of an incumbent Ombudsperson appointed under the provisions of the UGC (Redress of Grievances of Students) Regulations, 2019; where after, the appointment of Ombudsperson shall be made as per University Grants Commission (Redressal of Grievances of Students) Regulations, 2023.

Prof. MANISH R. JOSHI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./13/2023-24]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA

SAVITRIBAI PHULE PUNE UNIVERSITY

(formerly University of Pune)

Anti-Ragging
Guidelines

Foreword By :

Hon'ble Dr. Wasudeo Gade

Vice Chancellor

Savitribai Phule Pune University

(formerly University of Pune)

SAVITRIBAI PHULE PUNE UNIVERSITY

BOARD OF STUDENTS' WELFARE

Ganeshkhind, Pune 411 007

Join Hands to Make Your Campus RAGGING Free

National Anti-Ragging Helpline
24x7 Toll Free Number* 1800-180-5522
Email-helpline@antiragging.in
https://antiragging.in

FOR ANTI RAGGING Undertaking BY STUDENTS AND PARENTS/GUARDIANS - https://antiragging.in

For Any Details/Complaints :

Savitribai Phule Pune University
Anti-Ragging Monitoring Cell
Contact : 020-25601160, 25601154
Email : bsw@unipune.ac.in

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ

(पूर्वीचे पुणे विद्यापीठ)

: प्रस्तावना :

महामहीम राष्ट्रपती, मा. राज्यपाल तथा कुलपती आणि महाराष्ट्र शासन उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या वेळोवेळी प्राप्त झालेल्या आदेशांन्वये महाविद्यालये, मान्यताप्राप्त संस्था व विद्यापीठांमध्ये रॅगिंगच्या घटनांना प्रतिबंध करण्यासाठी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात वेळोवेळी दिलेल्या निकालांचे तंतोतंत पालन करणे अनिवार्य आहे. तसेच आपल्या महाविद्यालयाने याबाबत केलेल्या उपाययोजनांचा अहवाल मा. कुलपती यांच्या आदेशान्वये स्थापन करण्यात आलेल्या विद्यापीठस्तरीय रॅगिंग संनियंत्रण कक्षास पाठविणे आवश्यक आहे. सदर कक्ष मा. कुलसचिव यांचे अध्यक्षतेखाली विद्यापीठात कार्यरत राहील.

विद्यापीठ अनुदान आयोग, नवी दिल्ली यांचेद्वारा मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अनुषंगाने तयार करण्यात आलेली नियमावली तसेच भारतीय राजपत्रात दि. ४ जुलै, २००९ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या UGC Regulation on Curbing the Menace of Ragging in Higher Education Institutions, 2009, अधिनियमांचे पालन करणे आपणा सर्वांचे कर्तव्य आहे. तसेच राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठे व शैक्षणिक संस्थांमध्ये रॅगिंगच्या प्रकारांना प्रतिबंध करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने महाराष्ट्र रॅगिंग प्रतिबंधक कायदा, १९९९ लागू केला आहे. या सर्वांची एकत्रित माहिती असलेली पुस्तिका सोबत पाठवत आहे. त्यानुसार आपल्या महाविद्यालय/मान्यताप्राप्त संस्थेने रॅगिंगविरोधी उपाययोजनांची काळजीपूर्वक अंमलबजावणी करावी.

डॉ. वासुदेव गाडे
कुलगुरू

देव स्वरूप
Dr. Dev Swarup

संयुक्त सचिव
Joint Secretary

ज्ञान-विज्ञानं विमुक्तये

दूरभाष PHONE कार्यालय OFF : 011-23231273
फैक्स FAX : 011-23231291
E-mail : dev@ugc.ac.in
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुर शाह ज़फर मार्ग,
नई दिल्ली-110 002 (भारत)
UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
BAHADUR SHAH ZAFAR MARG
NEW DELHI-110 002 (INDIA)

No.F.1-16/ 2009(CPP-II)

September, 2009

Registrar
All Universities

12 OCT 2009

Subject: UGC Regulations on curbing the menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009.

Sir,

In continuation to this office letter of even no. dated 7th July, 2009 on the above subject, I am enclosing a copy of the UGC Regulations on curbing the menace of ragging in educational institutions, 2009 published in the Gazette of India dt.4th July,2009 in (i) English and (ii) Hindi) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रेगिंग निषेध से सम्बन्धित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम, 2009 for your information and necessary action.

The above regulations are mandatory and shall apply to all Universities established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State/Union Territory Act and all Institutions recognised by or affiliated to such Universities and all Institutions deemed to be Universities under Section (3) of the UGC Act, 1956 with effect from 4th July, 2009 i.e. the date of its Publication in the official Gazette.

It is requested that these regulations may please be brought to the notice of the Colleges affiliated to your Universities/Institution.

Yours faithfully,

(**Dev Swarup**)
Joint Secretary

Encl: As above

o/c

Copy to:-

1. All States/ U.Ts Higher. Education Secretaries (List attached).
2. The Secretary, Govt. of IndiaMinistry of Human Resource Development, Department of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi-110001
3. Shri V. Umashankar, Director, Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi-110001
4. The Secretary. Association of Indian Universities (AIU), 16, Comrade Inderjit Gupta Marg (Kotla), New Delhi-110002
5. All Professional Councils.
6. Ps to Chairman/Ps to Vcm/Ps to Secretary, UGC, New Delhi
7. JS (Web site) UGC for posting on UGC website.
8. All Regional Offices, UGC.
9. Guard file

वि. जायसवाल

(V.K. Jaiswal)
Deputy Secretary
20.10.200

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
BAHADURSHAH ZAFAR MARG
NEW DELHI – 110 002

UGC REGULATIONS ON CURBING THE MENACE OF RAGGING IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS, 2009.

(under Section 26 (1)(g) of the University Grants Commission Act, 1956)

(PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART III, SECTION-4, DATED 4th JULY 2009)

F.1-16/2007(CPP-II) **Dated 17th June, 2009.**

PREAMBLE.

In view of the directions of the Hon'ble Supreme Court in the matter of "University of Kerala v/s. Council, Principals, Colleges and others" in SLP no. 24295 of 2006 dated 16.05.2007 and that dated 8.05.2009 in Civil Appeal number 887 of 2009, and in consideration of the determination of the Central Government and the University Grants Commission to prohibit, prevent and eliminate the scourge of ragging including any conduct by any student or students whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness a fresher or any other student, or indulging in rowdy or indisciplined activities by any student or students which causes or is likely to cause annoyance, hardship or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in any fresher or any other student or asking any student to do any act which such student will not in the ordinary course do and which has the effect of causing or generating a sense of shame, or torment or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of such fresher or any other student, with or without an intent to derive a sadistic pleasure or showing off power, authority or superiority by a student over any fresher or any other student, in all higher education institutions in the country, and thereby, to provide for the healthy development, physically and psychologically, of all students, the University Grants Commission, in consultation with the Councils, brings forth this Regulation.

In exercise of the powers conferred by Clause (g) of sub-section (1) of Section 26 of the University Grants Commission Act, 1956, the University Grants Commission hereby makes the following Regulations, namely;

1. Title, commencement and applicability.-

1.1 These regulations shall be called the "UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009".

1.2 They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

1.3 They shall apply to all the institutions coming within the definition of an University under sub-section (f) of section (2) of the University Grants Commission Act, 1956, and to all institutions deemed to be a university under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956, to all other higher educational institutions, or elements of such universities or institutions, including its departments, constituent units and all the premises, whether being academic, residential, playgrounds, canteen, or other such premises of such universities, deemed universities and higher educational institutions, whether located within the campus or outside, and to all means of transportation of students, whether public or private, accessed by students for the pursuit of studies in such universities, deemed universities and higher educational institutions.

2. Objectives.-

To prohibit any conduct by any student or students whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness a fresher or any other student, or indulging in rowdy or indisciplined activities by any student or students which causes or is likely to cause annoyance, hardship or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in any fresher or any other student or asking any student to do any act which such student will not in the ordinary course do and which has the effect of causing or generating a sense of shame, or torment or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of such fresher or any other student, with or without an intent to derive a sadistic pleasure or showing off power, authority or superiority by a student over any fresher or any other student; and thereby, to eliminate ragging in all its forms from universities, deemed universities and other higher educational institutions in the country by prohibiting it

under these Regulations, preventing its occurrence and punishing those who indulge in ragging as provided for in these Regulations and the appropriate law in force.

3. What constitutes Ragging.- Ragging constitutes one or more of any of the following acts:

a. any conduct by any student or students whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness a fresher or any other student;
b. indulging in rowdy or indisciplined activities by any student or students which causes or is likely to cause annoyance, hardship, physical or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in any fresher or any other student;
c. asking any student to do any act which such student will not in the ordinary course do and which has the effect of causing or generating a sense of shame, or torment or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of such fresher or any other student;
d. any act by a senior student that prevents, disrupts or disturbs the regular academic activity of any other student or a fresher;
e. exploiting the services of a fresher or any other student for completing the academic tasks assigned to an individual or a group of students.
f. any act of financial extortion or forceful expenditure burden put on a fresher or any other student by students;
g. any act of physical abuse including all variants of it: sexual abuse, homosexual assaults, stripping, forcing obscene and lewd acts, gestures, causing bodily harm or any other danger to health or person;
h. any act or abuse by spoken words, emails, post, public insults which would also include deriving perverted pleasure, vicarious or sadistic thrill from actively or passively participating in the discomfiture to fresher or any other student ;
i. any act that affects the mental health and self-confidence of a fresher or any other student

with or without an intent to derive a sadistic pleasure or showing off power, authority or superiority by a student over any fresher or any other student.

4. Definitions.-

1) In these regulations unless the context otherwise requires,-

a) "Act" means, the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956);

b) "Academic year" means the period from the commencement of admission of students in any course of study in the institution up to the completion of academic requirements for that particular year.

c) "Anti-Ragging Helpline" means the Helpline established under clause (a) of Regulation 8.1 of these Regulations.

d) "Commission" means the University Grants Commission;

e) "Council" means a body so constituted by an Act of Parliament or an Act of any State Legislature for setting, or co-ordinating or maintaining standards in the relevant areas of higher education, such as the All India Council for Technical Education (AICTE), the Bar Council of India (BCI), the Dental Council of India (DCI), the Distance Education Council (DEC), the Indian Council of Agricultural Research (ICAR), the Indian Nursing Council (INC), the Medical Council of India (MCI), the National Council for Teacher Education (NCTE), the Pharmacy Council of India (PCI), etc. and the State Higher Education Councils.

f) "District Level Anti-Ragging Committee" means the Committee, headed by the District Magistrate, constituted by the State Government, for the control and elimination of ragging in institutions within the jurisdiction of the district.

g) "Head of the institution" means the Vice-Chancellor in case of a university or a deemed to be university, the Principal or the Director or such other designation as the executive head of the institution or the college is referred.

h) "Fresher" means a student who has been admitted to an institution and who is undergoing his/her first year of study in such institution.

i) "Institution" means a higher educational institution including, but not limited to an university, a deemed to be university, a college, an institute, an institution of national importance set up by an Act of Parliament or a constituent unit of such institution, imparting higher education beyond 12 years of schooling leading to, but not necessarily culminating in, a degree (graduate, postgraduate and/or higher level) and/or to a university diploma.

j) "NAAC" means the National Academic and Accreditation Council established by the Commission under section 12(ccc) of the Act;

k) "State Level Monitoring Cell" means the body constituted by the State Government for the control and elimination of ragging in institutions within the jurisdiction of the State, established under a State Law or on the advice of the Central Government, as the case may be.

(2) Words and expressions used and not defined herein but defined in the Act or in the General Clauses Act, 1897, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or in the General Clauses Act, 1897, as the case may be.

5. Measures for prohibition of ragging at the institution level:-

a) No Institution or any part of it thereof, including its elements, including, but not limited to, the departments, constituent units, colleges, centres of studies and all its premises, whether academic, residential, playgrounds, or canteen, whether located within the campus or outside, and in all means of transportation of students, whether public or private, accessed by students for the pursuit of studies in such institutions, shall permit or condone any reported incident of ragging in any form; and all institutions shall take all necessary and required measures, including but not limited to the provisions of these Regulations, to achieve the objective of eliminating ragging, within the institution or outside,

b) All institutions shall take action in accordance with these Regulations against those found guilty of ragging and/or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.

6 Measures for prevention of ragging at the institution level.-

6.1 An institution shall take the following steps in regard to admission or registration of students; namely,

a) Every public declaration of intent by any institution, in any electronic, audio-visual or print or any other media, for admission of students to any course of study shall expressly provide that ragging is totally prohibited in the institution,

and anyone found guilty of ragging and/or abetting ragging, whether actively or passively, or being a part of a conspiracy to promote ragging, is liable to be punished in accordance with these Regulations as well as under the provisions of any penal law for the time being in force.

b) The brochure of admission/instruction booklet or the prospectus, whether in print or electronic format, shall prominently print these Regulations in full.

Provided that the institution shall also draw attention to any law concerning ragging and its consequences, as may be applicable to the institution publishing such brochure of admission/instruction booklet or the prospectus.

Provided further that the telephone numbers of the Anti-Ragging Helpline and all the important functionaries in the institution, including but not limited to the Head of the institution, faculty members, members of the Anti-Ragging Committees and Anti-Ragging Squads, District and Sub-Divisional authorities, Wardens of hostels, and other functionaries or authorities where relevant, shall be published in the brochure of admission/instruction booklet or the prospectus.

c) Where an institution is affiliated to a University and publishes a brochure of admission/instruction booklet or a prospectus, the affiliating university shall ensure that the affiliated institution shall comply with the provisions of clause (a) and clause (b) of Regulation 6.1 of these Regulations.

d) The application form for admission, enrolment or registration shall contain an affidavit, mandatorily in English and in Hindi and/or in one of the regional languages known to the applicant, as provided in the English language in Annexure I to these Regulations, to be filled up and signed by the applicant to the effect that he/she has read and understood the provisions of these Regulations as well as the provisions of any other law for the time being in force, and is aware of the prohibition of ragging and the punishments prescribed, both under penal laws as well as under these Regulations and also affirm to the effect that he/she has not been expelled and/or debarred by any institution and further aver that he/she would not indulge, actively or passively, in the act or abet the act of ragging and if found guilty of ragging and/or abetting ragging, is liable to be proceeded against under these Regulations or under any penal law or any

other law for the time being in force and such action would include but is not limited to debarment or expulsion of such student.

e) The application form for admission, enrolment or registration shall contain an affidavit, mandatorily in English and in Hindi and/or in one of the regional languages known to the parents/guardians of the applicant, as provided in the English language in Annexure I to these Regulations, to be filled up and signed by the parents/guardians of the applicant to the effect that he/she has read and understood the provisions of these Regulations as well as the provisions of any other law for the time being in force, and is aware of the prohibition of ragging and the punishments prescribed, both under penal laws as well as under these Regulations and also affirm to the effect that his/her ward has not been expelled and/or debarred by any institution and further aver that his/her ward would not indulge, actively or passively, in the act or abet the act of ragging and if found guilty of ragging and/or abetting ragging, his/her ward is liable to be proceeded against under these Regulations or under any penal law or any other law for the time being in force and such action would include but is not limited to debarment or expulsion of his/her ward.

f) The application for admission shall be accompanied by a document in the form of, or annexed to, the School Leaving Certificate/Transfer Certificate/Migration Certificate/Character Certificate reporting on the inter-personal/social behavioural pattern of the applicant, to be issued by the school or institution last attended by the applicant, so that the institution can thereafter keep watch on the applicant, if admitted, whose behaviour has been commented in such document.

g) A student seeking admission to a hostel forming part of the institution, or seeking to reside in any temporary premises not forming part of the institution, including a private commercially managed lodge or hostel, shall have to submit additional affidavits countersigned by his/her parents/guardians in the form prescribed in Annexure I and Annexure II to these Regulations respectively along with his/her application.

h) Before the commencement of the academic session in any institution, the Head of the Institution shall convene and address a meeting of various functionaries/agencies, such as Hostel Wardens, representatives of students,

parents/ guardians, faculty, district administration including the police, to discuss the measures to be taken to prevent ragging in the institution and steps to be taken to identify those indulging in or abetting ragging and punish them.

i) The institution shall, to make the community at large and the students in particular aware of the dehumanizing effect of ragging, and the approach of the institution towards those indulging in ragging, prominently display posters depicting the provisions of penal law applicable to incidents of ragging, and the provisions of these Regulations and also any other law for the time being in force, and the punishments thereof, shall be prominently displayed on Notice Boards of all departments, hostels and other buildings as well as at places, where students normally gather and at places, known to be vulnerable to occurrences of ragging incidents.

j) The institution shall request the media to give adequate publicity to the law prohibiting ragging and the negative aspects of ragging and the institution's resolve to ban ragging and punish those found guilty without fear or favour.

k) The institution shall identify, properly illuminate and keep a close watch on all locations known to be vulnerable to occurrences of ragging incidents.

l) The institution shall tighten security in its premises, especially at vulnerable places and intense policing by Anti-Ragging Squad, referred to in these Regulations and volunteers, if any, shall be resorted to at such points at odd hours during the first few months of the academic session.

m) The institution shall utilize the vacation period before the start of the new academic year to launch a publicity campaign against ragging through posters, leaflets and such other means, as may be desirable or required, to promote the objectives of these Regulations.

n) The faculties/departments/units of the institution shall have induction arrangements, including those which anticipate, identify and plan to meet any special needs of any specific section of students, in place well in advance of the beginning of the academic year with an aim to promote the objectives of this Regulation.

o) Every institution shall engage or seek the assistance of professional counsellors before the commencement of the academic session, to be available

when required by the institution, for the purposes of offering counselling to freshers and to other students after the commencement of the academic year.

p) The head of the institution shall provide information to the local police and local authorities, the details of every privately commercially managed hostels or lodges used for residential purposes by students enrolled in the institution and the head of the institution shall also ensure that the Anti-Ragging Squad shall ensure vigil in such locations to prevent the occurrence of ragging therein.

5.2 An institution shall, on admission or enrolment or registration of students, take the following steps, namely;

a) Every fresh student admitted to the institution shall be given a printed leaflet detailing to whom he/she has to turn to for help and guidance for various purposes including addresses and telephone numbers, so as to enable the student to contact the concerned person at any time, if and when required, of the Anti-Ragging Helpline referred to in these Regulations, Wardens, Head of the institution, all members of the anti-ragging squads and committees, relevant district and police authorities.

b) The institution, through the leaflet specified in clause (a) of Regulation 6.2 of these Regulations shall explain to the freshers, the arrangements made for their induction and orientation which promote efficient and effective means of integrating them fully as students with those already admitted o the institution in earlier years.

c) The leaflet specified in clause (a) of Regulation 6.2 of these Regulations shall inform the freshers about their rights as bona fide students of the institution and clearly instructing them that they should desist from doing anything, with or against their will, even if ordered to by the seniors students, and that any attempt of ragging shall be promptly reported to the Anti-ragging Squad or to the Warden or to the Head of the institution, as the case may be.

d) The leaflet specified in clause (a) of Regulation 6.2 of these Regulations shall contain a calendar of events and activities laid down by the institution to facilitate and complement familiarization of freshers with the academic environment of the institution.

e) The institution shall, on the arrival of senior students after the first week or after the second week, as the case may be, schedule orientation programmes as follows, namely; (i) joint sensitization programme and counselling of both freshers and senior students by a professional counsellor, referred to in clause (o) of Regulation 6.1 of these Regulations; (ii) joint orientation programme of freshers and seniors to be addressed by the Head of the institution and the anti -ragging committee;(iii) organization on a large scale of cultural, sports and other activities to provide a platform for the freshers and seniors to interact in the presence of faculty members ; (iv) in the hostel, the warden should address all students; and may request two junior colleagues from the college faculty to assist the warden by becoming resident tutors for a temporary duration.(v) as far as possible faculty members should dine with the hostel residents in their respective hostels to instil a feeling of confidence among the freshers.

f) The institution shall set up appropriate committees, including the course-in-charge, student advisor, Wardens and some senior students as its members, to actively monitor, promote and regulate healthy interaction between the freshers, junior students and senior students.

g) Freshers or any other student(s), whether being victims, or witnesses, in any incident of ragging, shall be encouraged to report such occurrence, and the identity of such informants shall be protected and shall not be subject to any adverse consequence only for the reason for having reported such incidents.

h) Each batch of freshers, on arrival at the institution, shall be divided into small groups and each such group shall be assigned to a member of the faculty, who shall interact individually with each member of the group every day for ascertaining the problems or difficulties, if any, faced by the fresher in the institution and shall extend necessary help to the fresher in overcoming the same.

i) It shall be the responsibility of the member of the faculty assigned to the group of freshers, to coordinate with the Wardens of the hostels and to make surprise visits to the rooms in such hostels, where a member or members of the group are lodged; and such member of faculty shall maintain a diary of his/her interaction with the freshers under his/her charge.

j) Freshers shall be lodged, as far as may be, in a separate hostel block, and where such facilities are not available, the institution shall ensure that access of seniors to accommodation allotted to freshers is strictly monitored by wardens, security guards and other staff of the institution.

k) A round the clock vigil against ragging in the hostel premises, in order to prevent ragging in the hostels after the classes are over, shall be ensured by the institution.

l) It shall be the responsibility of the parents/guardians of freshers to promptly bring any instance of ragging to the notice of the Head of the Institution.

m) Every student studying in the institution and his/her parents/guardians shall provide the specific affidavits required under clauses (d), (e) and (g) of Regulation 6.1 of these Regulations at the time of admission or registration, as the case may be, during each academic year.

n) Every institution shall obtain the affidavit from every student as referred to above in clause (m) of Regulation 6.2 and maintain a proper record of the same and to ensure its safe upkeep thereof, including maintaining the copies of the affidavit in an electronic form, to be accessed easily when required either by the Commission or any of the Councils or by the institution or by the affiliating University or by any other person or organisation authorised to do so.

o) Every student at the time of his/her registration shall inform the institution about his/her place of residence while pursuing the course of study, and in case the student has not decided his/her place of residence or intends to change the same, the details of his place of residence shall be provided immediately on deciding the same; and specifically in regard to a private commercially managed lodge or hostel where he/she has taken up residence.

p) The Head of the institution shall, on the basis of the information provided by the student under clause (o) of Regulation 6.2, apportion sectors to be assigned to members of the faculty, so that such member of faculty can maintain vigil and report any incident of ragging outside the campus or en route while commuting to the institution using any means of transportation of students, whether public or private.

q) The Head of the institution shall, at the end of each academic year, send a letter to the parents/guardians of the students who are completing their first year in the institution, informing them about these Regulations and any law for the time being in force prohibiting ragging and the punishments thereof as well as punishments prescribed under the penal laws, and appealing to them to impress upon their wards to desist from indulging in ragging on their return to the institution at the beginning of the academic session next.

6.3 Every institution shall constitute the following bodies; namely,

a) Every institution shall constitute a Committee to be known as the Anti-Ragging Committee to be nominated and headed by the Head of the institution, and consisting of representatives of civil and police administration, local media, Non Government Organizations involved in youth activities, representatives of faculty members, representatives of parents, representatives of students belonging to the freshers' category as well as senior students, non-teaching staff; and shall have a diverse mix of membership in terms of levels as well as gender.

b) It shall be the duty of the Anti-Ragging Committee to ensure compliance with the provisions of these Regulations as well as the provisions of any law for the time being in force concerning ragging; and also to monitor and oversee the performance of the Anti-Ragging Squad in prevention of ragging in the institution.

c) Every institution shall also constitute a smaller body to be known as the Anti-Ragging Squad to be nominated by the Head of the Institution with such representation as may be considered necessary for maintaining vigil, oversight and patrolling functions and shall remain mobile, alert and active at all times.

Provided that the Anti-Ragging Squad shall have representation of various members of the campus community and shall have no outside representation.

d) It shall be the duty of the Anti-Ragging Squad to be called upon to make surprise raids on hostels, and other places vulnerable to incidents of, and having the potential of, ragging and shall be empowered to inspect such places.

e) It shall also be the duty of the Anti-Ragging Squad to conduct an on-the-spot enquiry into any incident of ragging referred to it by the Head of the institution

or any member of the faculty or any member of the staff or any student or any parent or guardian or any employee of a service provider or by any other person, as the case may be; and the enquiry report along with recommendations shall be submitted to the Anti-Ragging Committee for action under clause (a) of Regulation 9.1.

Provided that the Anti-Ragging Squad shall conduct such enquiry observing a fair and transparent procedure and the principles of natural justice and after giving adequate opportunity to the student or students accused of ragging and other witnesses to place before it the facts, documents and views concerning the incident of ragging, and considering such other relevant information as may be required.

f) Every institution shall, at the end of each academic year, in order to promote the objectives of these Regulations, constitute a Mentoring Cell consisting of students volunteering to be Mentors for freshers, in the succeeding academic year; and there shall be as many levels or tiers of Mentors as the number of batches in the institution, at the rate of one Mentor for six freshers and one Mentor of a higher level for six Mentors of the lower level.

g) Every University shall constitute a body to be known as Monitoring Cell on Ragging, which shall coordinate with the affiliated colleges and institutions under the domain of the University to achieve the objectives of these Regulations; and the Monitoring Cell shall call for reports from the Heads of institutions in regard to the activities of the Anti-Ragging Committees, Anti - Ragging Squads, and the Mentoring Cells at the institutions, and it shall also keep itself abreast of the decisions of the District level Anti-Ragging Committee headed by the District Magistrate.

h) The Monitoring Cell shall also review the efforts made by institutions to publicize anti-ragging measures, soliciting of affidavits from parents/guardians and from students, each academic year, to abstain from ragging activities or willingness to be penalized for violations; and shall function as the prime mover for initiating action on the part of the appropriate authorities of the university for amending the Statutes or Ordinances or Bye-laws to facilitate the implementation of anti-ragging measures at the level of the institution.

6.4 Every institution shall take the following other measures, namely;

a) Each hostel or a place where groups of students reside, forming part of the institution, shall have a full-time Warden, to be appointed by the institution as per the eligibility criteria laid down for the post reflecting both the command and control aspects of maintaining discipline and preventing incidents of ragging within the hostel, as well as the softer skills of counselling and communicating with the youth outside the class-room situation; and who shall reside within the hostel, or at the very least, in the close vicinity thereof.

b) The Warden shall be accessible at all hours and be available on telephone and other modes of communication, and for the purpose the Warden shall be provided with a mobile phone by the institution, the number of which shall be publicised among all students residing in the hostel.

c) The institution shall review and suitably enhance the powers of Wardens; and the security personnel posted in hostels shall be under the direct control of the Warden and their performance shall be assessed by them.

d) The professional counsellors referred to under clause (o) of Regulation 6.1 of these Regulations shall, at the time of admission, counsel freshers and/or any other student(s) desiring counselling, in order to prepare them for the life ahead, particularly in regard to the life in hostels and to the extent possible, also involve parents and teachers in the counselling sessions.

e) The institution shall undertake measures for extensive publicity against ragging by means of audio-visual aids, counselling sessions, workshops, painting and design competitions among students and such other measures, as it may deem fit.

f) In order to enable a student or any person to communicate with the Anti-Ragging Helpline, every institution shall permit unrestricted access to mobile phones and public phones in hostels and campuses, other than in class-rooms, seminar halls, library, and in such other places that the institution may deem it necessary to restrict the use of phones.

g) The faculty of the institution and its non-teaching staff, which includes but is not limited to the administrative staff, contract employees, security guards

and employees of service providers providing services within the institution, shall be sensitized towards the ills of ragging, its prevention and the consequences thereof.

h) The institution shall obtain an undertaking from every employee of the institution including all teaching and non-teaching members of staff, contract labour employed in the premises either for running canteen or as watch and ward staff or for cleaning or maintenance of the buildings/lawns and employees of service providers providing services within the institution, that he/she would report promptly any case of ragging which comes to his/her notice.

i) The institution shall make a provision in the service rules of its employees for issuing certificates of appreciation to such members of the staff who report incidents of ragging, which will form part of their service record.

j) The institution shall give necessary instructions to the employees of the canteens and messing, whether that of the institution or that of a service provider providing this service, or their employers, as the case may be, to keep a strict vigil in the area of their work and to report the incidents of ragging to the Head of the institution or members of the Anti-Ragging Squad or members of the Anti-Ragging Committee or the Wardens, as may be required.

k) All Universities awarding a degree in education at any level, shall be required to ensure that institutions imparting instruction in such courses or conducting training programme for teachers include inputs relating to anti-ragging and the appreciation of the relevant human rights, as well as inputs on topics regarding sensitization against corporal punishments and checking of bullying amongst students, so that every teacher is equipped to handle at least the rudiments of the counselling approach.

l) Discreet random surveys shall be conducted amongst the freshers every fortnight during the first three months of the academic year to verify and cross-check whether the institution is indeed free of ragging or not and for the purpose the institution may design its own methodology of conducting such surveys.

m) The institution shall cause to have an entry, apart from those relating to general conduct and behaviour, made in the Migration/Transfer Certificate issued to the student while leaving the institution, as to whether the student has been

punished for committing or abetting an act of ragging, as also whether the student has displayed persistent violent or aggressive behaviour or any inclination to harm others, during his course of study in the institution.

n) Notwithstanding anything contained in these Regulations with regard to obligations and responsibilities pertaining to the authorities or members of bodies prescribed above, it shall be the general collective responsibility of all levels and sections of authorities or functionaries including members of the faculty and employees of the institution, whether regular or temporary, and employees of service providers providing service within the institution, to prevent or to act promptly against the occurrence of ragging or any incident of ragging which comes to their notice.

o) The Heads of institutions affiliated to a University or a constituent of the University, as the case may be, shall, during the first three months of an academic year, submit a weekly report on the status of compliance with Anti-Ragging measures under these Regulations, and a monthly report on such status thereafter, to the Vice-Chancellor of the University to which the institution is affiliated to or recognized by.

p) The Vice Chancellor of each University, shall submit fortnightly reports of the University, including those of the Monitoring Cell on Ragging in case of an affiliating university, to the State Level Monitoring Cell.

7. Action to be taken by the Head of the institution.- On receipt of the recommendation of the Anti Ragging Squad or on receipt of any information concerning any reported incident of ragging, the Head of institution shall immediately determine if a case under the penal laws is made out and if so, either on his own or through a member of the Anti-Ragging Committee authorised by him in this behalf, proceed to file a First Information Report (FIR), within twenty four hours of receipt of such information or recommendation, with the police and local authorities, under the appropriate penal provisions relating to one or more of the following, namely;

i. Abetment to ragging;
ii. Criminal conspiracy to rag;
iii. Unlawful assembly and rioting while ragging;

iv. Public nuisance created during ragging;

v. Violation of decency and morals through ragging;

vi. Injury to body, causing hurt or grievous hurt;

vii. Wrongful restraint;

viii. Wrongful confinement;

ix. Use of criminal force;

x. Assault as well as sexual offences or unnatural offences;

xi. Extortion;

xii. Criminal trespass;

xiii. Offences against property;

xiv. Criminal intimidation;

xv. Attempts to commit any or all of the above mentioned offences against the victim(s);

xvi. Threat to commit any or all of the above mentioned offences against the victim(s);

xvii. Physical or psychological humiliation;

xviii. All other offences following from the definition of "Ragging".

Provided that the Head of the institution shall forthwith report the occurrence of the incident of ragging to the District Level Anti-Ragging Committee and the Nodal officer of the affiliating University, if the institution is an affiliated institution.

Provided further that the institution shall also continue with its own enquiry initiated under clause 9 of these Regulations and other measures without waiting for action on the part of the police/local authorities and such remedial action shall be initiated and completed immediately and in no case later than a period of seven days of the reported occurrence of the incident of ragging.

8. Duties and Responsibilities of the Commission and the Councils.-

8.1 The Commission shall, with regard to providing facilitating communication of information regarding incidents of ragging in any institution, take the following steps, namely;

a) The Commission shall establish, fund and operate, a toll-free Anti-Ragging Helpline, operational round the clock, which could be accessed by students in distress owing to ragging related incidents.

b) Any distress message received at the Anti-Ragging Helpline shall be simultaneously relayed to the Head of the Institution, the Warden of the Hostels, the Nodal Officer of the affiliating University, if the incident reported has taken place in an institution affiliated to a University, the concerned District authorities and if so required, the District Magistrate, and the Superintendent of Police, and shall also be web enabled so as to be in the public domain simultaneously for the media and citizens to access it.

c) The Head of the Institution shall be obliged to act immediately in response to the information received from the Anti-Ragging Helpline as at sub-clause (b) of this clause.

d) The telephone numbers of the Anti-Ragging Helpline and all the important functionaries in every institution, Heads of Institutions, faculty members, members of the anti-ragging committees and anti ragging squads, district and sub-divisional authorities and state authorities, Wardens of hostels, and other functionaries or authorities where relevant, shall be widely disseminated for access or to seek help in emergencies.

e) The Commission shall maintain an appropriate data base to be created out of affidavits, affirmed by each student and his/her parents/guardians and stored electronically by the institution, either on its or through an agency to be designated by it; and such database shall also function as a record of ragging complaints received, and the status of the action taken thereon.

f) The Commission shall make available the database to a non-governmental agency to be nominated by the Central Government, to build confidence in the public and also to provide information of non compliance with these Regulations to the Councils and to such bodies as may be authorised by the Commission or by the Central Government.

8.2 The Commission shall take the following regulatory steps, namely;

a) The Commission shall make it mandatory for the institutions to incorporate in their prospectus, the directions of the Central Government or the State Level Monitoring Committee with regard to prohibition and consequences of ragging, and that non-compliance with these Regulations and directions so provided, shall be considered as lowering of academic standards by the institution, therefore making it liable for appropriate action.

b) The Commission shall verify that the institutions strictly comply with the requirement of getting the affidavits from the students and their parents/guardians as envisaged under these Regulations.

c) The Commission shall include a specific condition in the Utilization Certificate, in respect of any financial assistance or grants-in-aid to any institution under any of the general or special schemes of the Commission, that the institution has complied with the anti-ragging measures.

d) Any incident of ragging in an institution shall adversely affect its accreditation, ranking or grading by NAAC or by any other authorised accreditation agencies while assessing the institution for accreditation, ranking or grading purposes.

e) The Commission may accord priority in financial grants-in-aid to those institutions, otherwise eligible to receive grants under section 12B of the Act, which report a blemishless record in terms of there being no reported incident of ragging.

f) The Commission shall constitute an Inter-Council Committee, consisting of representatives of the various Councils, the Non-Governmental agency responsible for monitoring the database maintained by the Commission under clause (g) of Regulation 8.1 and such other bodies in higher education, to coordinate and monitor the anti-ragging measures in institutions across the country and to make recommendations from time to time; and shall meet at least once in six months each year.

g) The Commission shall institute an Anti-Ragging Cell within the Commission as an institutional mechanism to provide secretarial support for collection of information and monitoring, and to coordinate with the State Level Monitoring Cell and University level Committees for effective implementation of anti-ragging measures, and the Cell shall also coordinate with the Non-Governmental agency

responsible for monitoring the database maintained by the Commission appointed under clause (g) of Regulation 8.1.

9. Administrative action in the event of ragging.-

9.1 The institution shall punish a student found guilty of ragging after following the procedure and in the manner prescribed hereinunder:

a) The Anti-Ragging Committee of the institution shall take an appropriate decision, in regard to punishment or otherwise, depending on the facts of each incident of ragging and nature and gravity of the incident of ragging established in the recommendations of the Anti-Ragging Squad.

b) The Anti-Ragging Committee may, depending on the nature and gravity of the guilt established by the Anti-Ragging Squad, award, to those found guilty, one or more of the following punishments, namely;

i. Suspension from attending classes and academic privileges.
ii. Withholding/ withdrawing scholarship/ fellowship and other benefits.
iii. Debarring from appearing in any test/ examination or other evaluation process.
iv. Withholding results.
v. Debarring from representing the institution in any regional, national or international meet, tournament, youth festival, etc.
vi. Suspension/ expulsion from the hostel.
vii. Cancellation of admission.
viii. Rustication from the institution for period ranging from one to four semesters.
ix. Expulsion from the institution and consequent debarring from admission to any other institution for a specified period.

Provided that where the persons committing or abetting the act of ragging are not identified, the institution shall resort to collective punishment.

c) An appeal against the order of punishment by the Anti-Ragging Committee shall lie,

i. in case of an order of an institution, affiliated to or constituent part, of a University, to the Vice-Chancellor of the University;

ii. In case of an order of a University, to its Chancellor.

iii. in case of an institution of national importance created by an Act of Parliament, to the Chairman or Chancellor of the institution, as the case may be.

9.2 Where an institution, being constituent of, affiliated to or recognized by a University, fails to comply with any of the provisions of these Regulations or fails to curb ragging effectively, such University may take any one or more of the following actions, namely;

i. Withdrawal of affiliation/recognition or other privileges conferred.

ii. Prohibiting such institution from presenting any student or students then undergoing any programme of study therein for the award of any degree/diploma of the University.

Provided that where an institution is prohibited from presenting its student or students, the Commission shall make suitable arrangements for the other students so as to ensure that such students are able to pursue their academic studies.

iii. Withholding grants allocated to it by the university, if any

iv. Withholding any grants chanellised through the university to the institution.

v. Any other appropriate penalty within the powers of the university.

9.3 Where in the opinion of the appointing authority, a lapse is attributable to any member of the faulty or staff of the institution, in the matter of reporting or taking prompt action to prevent an incident of ragging or who display an apathetic or insensitive attitude towards complaints of ragging, or who fail to take timely steps, whether required under these Regulations or otherwise, to prevent an Incident or incidents of ragging, then such authority shall initiate departmental disciplinary action, in accordance with the prescribed procedure of the institution, against such member of the faulty or staff.

Provided that where such lapse is attributable to the Head of the institution, the authority designated to appoint such Head shall take such departmental disciplinary

action; and such action shall be without prejudice to any action that may be taken under the penal laws for abetment of ragging for failure to take timely steps in the prevention of ragging or punishing any student found guilty of ragging.

9.4 The Commission shall, in respect of any institution that fails to take adequate steps to prevent ragging or fails to act in accordance with these Regulations or fails to punish perpetrators or incidents of ragging suitably, take one of more of the following measures, namely;

i. Withdrawal of declaration of fitness to receive grants under section 12B of the Act.
ii. Withholding any grant allocated.
iii. Declaring the institution ineligible for consideration for any assistance under any of the general or special assistance programmes of the Commission.
iv. Informing the general public, including potential candidates for admission, through a notice displayed prominently in the newspapers or other suitable media and posted on the website of the Commission, declaring that the institution does not possess the minimum academic standards.
v. Taking such other action within its powers as it may deem fit and impose such other penalties as may be provided in the Act for such duration of time as the institution complies with the provisions of these Regulations.

Provided that the action taken under this clause by the Commission against any institution shall be shared with all Councils.

(Dr. R.K. Chauhan)
Secretary

To,

The Assistant Controller,
Publication Division, Govt. of India,
Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation,
Civil Lines Delhi -110 054

ANNEXURE I
AFFIDAVIT BY THE STUDENT

I, _____*(full name of student with admission/registration/enrolment number)* s/o d/o Mr./Mrs./Ms. _____ , having been admitted to _____*(name of the institution)*_____, have received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter called the "Regulations") carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.

2) I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.

3) I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.

4) I hereby solemnly aver and undertake that

a) I will not indulge in any behaviour or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

b) I will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

5) I hereby affirm that, if found guilty of ragging, I am liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law or any law for the time being in force.

6) I hereby declare that I have not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, I am aware that my admission is liable to be cancelled.

Declared this ___day of _____ month of _____year.

_____

Signature of deponent

Name:

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at *(place)* on this the *(day)* of *(month)* , *(year)* .

_____

Signature of deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the *(day)* of *(month)* , *(year)* after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER

ANNEXURE II
AFFIDAVIT BY PARENT/GUARDIAN

I, Mr./Mrs./Ms. _____ *(full name of parent/guardian)* father/mother/guardian of , *(full name of student with admission/registration/enrolment number)* , having been admitted to *(name of the institution)*, have received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter called the "Regulations"), carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.

2) I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.

3) I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against my ward in case he/she is found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.

4) I hereby solemnly aver and undertake that

a) My ward will not indulge in any behaviour or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

b) My ward will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

5) I hereby affirm that, if found guilty of ragging, my ward is liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against my ward under any penal law or any law for the time being in force.

6) I hereby declare that my ward has not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, the admission of my ward is liable to be cancelled.

Declared this ___day of _____ month of _____year.

_____
Signature of deponent
Name:
Address:
Telephone/ Mobile No.:

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.
Verified at *(place)* on this the *(day)* of *(month)*, *(year)*.

_____
Signature of deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the *(day)* of *(month)*, *(year)* after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

Proforma for monitoring the directions of Hon'ble Supreme Court of India on measures against Ragging in educational institutions.

Sr. No.	Name of the institution, city		
	Action		
1	Whether Anti ragging Squads were Constituted?	Yes/No	
2	Whether Anti ragging Committees were Constituted?	Yes/No	
3	Whether prospectus mention possible actions against Ragging?	Give brief details	
4	Whether names, telephone nos. of authorities to be contacted have been publicized/made available to Freshers	-Do-	
5	Whether students are allowed free access to phone (Cell & Landline) in hostel(s) for timely reporting	-Do-	
6	Whether Seniors counseled	-Do-	
7	Whether Freshers counseled	-Do-	
8	Whether orientation courses for Freshers conducted	-Do-	
9	Anti Ragging Squads	9(a) Date of formation 9(b) No. of members 9(c) No. of raids 9(d) Frequency of raids 9(e)Surprise raids 9(f)Others measures taken by the squad 9(g)No. of cases detected 9(h)Action taken as follow up.	
10	AntiRagging Committee.	10(a) Date of formation 10(b) No. of members 10(c) No. of raids 10(d) Frequency of raids 10(e)Surprise raids 10(f)Others measures taken by the squad 10(g)No. of cases detected 10(h)Action taken as follow up.	
11	Inquiry(ies) Conducted		
12	Punishment meted out.	12(a) Suspension 12(b)Rustication 12(c) Expulsion	
13	No.of F.I.R.(s) lodged by Institution with deatils		

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह जफर मार्ग
नई दिल्ली– 110002

उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग निषेध से सम्बन्धित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम, 2009

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 धारा 26 (1) (जी) के अन्तर्गत)

(भारत के राजपत्र भाग III खण्ड 4 में प्रकाशन हेतु)

मि0सं0 1–16/2007(सी.पी.पी.–II) दिनांक 17 जून, 2009

<u>उद्देशिका</u>

माननीय उच्चतम न्यायालय के केरल विश्वविद्यालय बनाम काउंसिल प्रिसिंपल कॉलेज तथा अन्य, एस0एल.पी0 सं0 24295 , 2006 के 16–5–2007 तथा दिनांक 08–5–2009, सिविल अपील नं. 887 से प्राप्त निर्देशों तथा केन्द्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रैगिंग निषेध तथा रैगिंग रोकने के संकल्प को ध्यान में रखते हुए । छात्र अथवा छात्रों द्वारा मौखिक शब्दों अथवा लिखित कार्य द्वारा नए अथवा अन्य छात्र को उत्पीड़न, दुर्व्यवहार, छात्र को उत्पात अथवा अनुशासनहीनता की गतिविधियों में संलिप्त करना जिससे नए अथवा किसी अन्य छात्र को कष्ट, परेशानी, कठिनाई अथवा मनोवैज्ञानिक हानि हो अथवा उसमें भय की भावना उत्पन्न हो अथवा नए या अन्य किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना जो वह सामान्य स्थिति में करे तथा जिससे उसमें लज्जा की भावना उत्पन्न हो अथवा घबराहट हो जिससे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से किसी छात्र पर दुष्प्रभाव पड़े अथवा कोई छात्र नए अथवा अन्य छात्र पर शक्ति प्रदर्शन करें। देश के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में समुचित विकास हेतु शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अन्य समितियों से विचार विमर्श के पश्चात् ये अधिनियम बनाता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम 1956 धारा 26 उप खण्ड (जी) उपखंड (1) के अधिकारों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निम्नलिखित अधिनियम बनाता है, जिसका नाम है–

1. **शीर्षक, प्रारम्भ और प्रयोज्यता**

1.1 ये अधिनियम "विश्वविद्यालय अनुदान के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के खतरे को रोकने के अधिनियम, 2009" कहे जाएँगे।

1.2 ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। विश्वविद्यालय अनदान आयोग की धारा (2) उपखंड (एफ) के अनुसार /विश्वविद्यालय की परिभाषा के अन्तर्गत आनेवाली सभी संस्थाओं तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम 1956 धारा 3 के अनुसार सभी डीम्ड विश्वविद्यालयों तथा अन्य सभी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं तथा इस प्रकार के विश्वविद्यालय के सम्बन्धित तत्वों से युक्त संस्थाओं, विभागों, इकाइयों तथा अन्य सभी शैक्षिक, आवासीय, खेल के मैदान, जलपान गृह तथा विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं चाहे वे परिसर के भीतर हों अथवा बहार तथा छात्रों के सभी प्रकार के परिवहन चाहे वे सरकारी हों अथवा निजी छात्रों द्वारा इस प्रकार के विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यायों तथा उच्चतर शिक्षण संस्थनों पर लागू होंगे।

2. **उद्देश्य**

किसी छात्र अथवा छात्रों के द्वारा दूसरों को मौखिक अथवा लिखित शब्दों द्वारा प्रताड़ित करना, उसे छेड़ना किसी नए छात्र के साथ दुर्व्यवहार करना अथवा उसे अनुशासनहीन गतिविधियों में लगाना जिससे आक्रोश, कठिनाई, मनोवैज्ञानिक हानि हो अथवा किसी नए अथवा अन्य किसी छात्र में भय की भावना उत्पन्न हो अथवा किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना जो वह सामान्य स्थिति में नहीं करे अथवा ऐसा कार्य कराना जिससे उसमें लज्जा की भावना उत्पन्न हो, पीड़ा हो घबराहट हो अथवा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से दुष्प्रभाव पड़े अथवा शक्ति प्रदर्शन करना अथवा किसी छात्र का वरिष्ठ होने के कारण शोषण करना। अतः सभी विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों तथा देश के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में इन अधिनियम के अन्तर्गत रैगिंग रोकना। इस तरह की घटनाओं में संलिप्त व्यक्तियों को इन अधिनियम तथा विधि के अनुसार दण्डित करना।

रैगिंग कैसे होती है–

निम्नलिखित कोई एक अथवा अनेंक कार्य रैगिंग के अन्तर्गत आएँगे–

क किसी छात्र अथवा छात्रों द्वारा नए आनेवाले छात्र का मौखिक शब्दों अथवा लिखित वाणी द्वारा उत्पीड़न अथवा दुर्व्यवहार करना।

ख छात्र अथवा छात्रों द्वारा उत्पात करना अथवा अनुशासनहीनता का वातावरण बनाना जिससे नए छात्र को कष्ट, आक्रोश , कठिनाई, शारीरिक अथवा मानसिक पीड़ा हो।

ग किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना जो वह सामान्य स्थिति में न करे तथा जिससे नए छात्र में लज्जा, पीड़ा, अथवा भय की भावना उत्पन्न हो।

घ वरिष्ठ छात्र द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य जो किसी अन्य अथवा नए छात्र के चलते हुए शैक्षिक कार्य में बाधा पहुँचाएं।

ड़ नए अथवा किसी अन्य छात्र का दूसरों को दिए गए शैक्षिक कार्य को करने हेतु बाध्य कर शोषण करना।

च नए छात्र का किसी भी प्रकार से आर्थिक शोषण करना।

छ शारीरिक शोषण का कोई भी कार्य/किसी भी प्रकार का यौन शोषण, समलैंगिक प्रहार, नगा करना, अश्लील तथा काम सम्बन्धी कार्य हेतु विवश करना, अंग चालन द्वारा बुरे भावों की अभिव्यक्ति करना, किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट जिससे किसी व्यक्ति अथवा उसके स्वास्थ्य को हानि पहुँचे।

ज मौखिक शब्दों द्वारा किसी को गाली देना, ई–मेल, डाक, पब्लिकली किसी को अपमानित करना, किसी को कुमार्ग मार्ग पर ले जाना, स्थानापन्न अथवा कष्टदाय देना या सनसनी पैदा करना जिससे नए छात्र को घबराहट हो।

झ कोई कार्य जिससे नए छात्र के मन मस्तिष्क अथवा आत्मविश्वास पर दुष्प्रभाव पड़े । नए अथवा किसी छात्र को कुमार्ग पर ले लाना तथा उस पर किसी प्रकार की प्रभुता दिखाना।

4. **परिभाषाएँ**

1 इन अधिनियमों में जब तक कि कोई अन्य संदर्भ न हो।

क अधिनियम का तात्पर्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956/3) है।

ख शैक्षिक वर्ष का तात्पर्य किसी संस्था में किसी छात्र का किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश तथा उस वर्ष की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति है।

ग रैंगिंग विरोधी हैल्पलाईन का तात्पर्य इन अधिनियमों के अधिनियम 8.1 की धारा (ए) है।

घ आयोग का तात्पर्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है।

ड़ समिति (कौंसिल) का तात्पर्य संसद अथवा राज्य के विधानमंडल द्वारा नियमित उच्चतर शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में सहयोग तथा स्तर बनाए रखने हेतु गठित समिति है। यथा आल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्नीकल एजुकेशन (ए.आई.सी.टी.ई.) बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बी.सी.आई.) डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (डी.सी.आई.) डेन्टिस एजुकेशन काउंसिल (डी.ई.सी.) दी इंडिया काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च (आइ.सी.ए.आर.) इंडियन नर्सिंग काउंसिल (आई.एन.सी.) मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एम.सी.आई.) नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एन.सी.टी.ई.) प्राइमरी काउंसिल ऑफ इंडिया (पी.सी. आई.) इत्यादि तथा राज्यों के उच्चतर शिक्षा काउंसिल इत्यादि ।

च जिला स्तरीय रैगिंग विरोधी समिति का तात्पर्य जिलाधिकारी की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा रैगिंग रोकने के लिए जिले की परिसीमा में गठित समिति है।

छ संस्थाध्यक्ष का तात्पर्य विश्वविद्यालय अथवा डीम्ड विश्वविद्यालयों हेतु कुलपति अथवा किसी संस्था का निदेशक, कॉलेज का प्राचार्य सम्बन्धित का कार्यकारी अध्यक्ष है।

ज "फ्रेशर" से तात्पर्य वह छात्र है जिसका प्रवेश किसी संस्था में हो गया है तथा उस संस्था में उसकी पढ़ाई का प्रथम वर्ष चल रहा है।

झ संस्था का तात्पर्य वह उच्चतर शिक्षण संस्था है जो चाहे विश्वविद्यालय हो डीम्ड विश्वविद्यालय हो, कॉलेज अथवा राष्ट्रीय महत्व की कोई संस्थान हो जिसकी रचना संसद के अधिनियम के अनुसार की गई हो। इसमें 12 वर्ष स्कूल की शिक्षा के बाद की शिक्षा दी जाती हो कोई आवश्यक नही है कि उसमें चरम सीमा तक उपाधि दी जाती हो । स्नातक/स्नातकोत्तर तथा उच्चतर स्तर अथवा विश्वविद्यालय प्रमाण पत्र की ।

ञ एन.ए.ए.सी. का तात्पर्य आयोग द्वारा अधिनियम की 12(सी.सी.सी.) के अनुसार स्थापित नेशनल एकेडमिक एंड ऐक्रिडिटेशन काउंसिल है।

ट राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग सेल का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा विधि के अनुसार अथवा केन्द्र सरकार की सलाह पर रैगिंग रोकने के लिए बनाया गया निकाय है । जिसका कार्यक्षेत्र राज्य तक होगा।

2 शब्द तथा अभिव्यक्ति को यहाँ स्पष्ट नही किया गया है किन्तु अधिनियम अथवा अधिनियम के सामान्य खण्ड 1887 वही अर्थ होगा जो उसमें दिया गया है।

5. **संस्था स्तर पर रैगिंग निषेध के उपाय–**

क कोई भी संस्था अथवा उसका कोई भाग, उसके तत्वों सहित केवल विभागों तक नहीं उसकी संघ तक ईकाई, कॉलेज, शिक्षण केन्द्र, उसके भू–गृह चाहे वे शैक्षिक, आवासीय खेल के मैदान अथवा जलपान गृह आदि चाहे वे विश्वविद्यालय परिसर में हो अथवा बाहर, सभी प्रकार के परिवहन, या निजी सभी में रैगिंग रोकने हेतु इन विनियमों के अनुसार तथा अन्य सभी आवश्यक उपाय करेंगे। रिपोर्ट होने पर रैगिंग की किसी भी घटना को दबाया नहीं जाएगा।

ख सभी संस्थाएं रैगिंग के प्रचार, रैगिंग में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध इन विनियम के अनुसार कार्रवाई करेंगे।

6. **संस्था स्तर पर रैगिंग रोकने के उपाय**

6.1 छात्रों के प्रवेश अथवा पंजीकरण के संदर्भ में संस्था निम्नलिखित कदम उठाए।

क संस्था द्वारा जारी इलेक्ट्रानिक दृश्य, श्रव्य अथवा प्रिन्ट मीडिया के छात्र को

प्रवेश संबंधी घोषणा में यही बताया जाए कि संस्था में रैगिंग पूर्णतः निषेध है। यदि कोई रैगिंग करने अथवा उसके प्रचार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दोषी पाया गया अथवा रैगिंग प्रचार के षड़यंत्र में दोषी पाया गया तो उसे इन विनियम तथा देश के कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा।

ख प्रवेश की पुस्तिका के निर्देश पुस्तक तथा विवरण पत्रिका चाहे वे इलेक्ट्रानिक हो अथवा मुद्रित उनमें ये विनियम विस्तार से छापें जाएँ। प्रवेश पुस्तिका का निर्देश पुस्तिका विविरण पत्रिका में यह भी मुद्रित किया जाए कि रैगिंग होने या संस्था के अध्यक्ष इसके साथ संस्थाध्यक्ष , संकाय सदस्य रैगिंग विरोधी समिति के सदस्यों, रैगिंग विरोधी दस्तों के सदस्यों अथवा जिले के अधिकारियों, वार्डनों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों के दूरभाष नम्बर प्रवेश पुस्तिका, निर्देश पुस्तिका अथवा विवरण पत्रिका में विस्तार से छापे जाएँ।

ग जहाँ कोई संस्था किसी विश्वविद्यालय से संबंध है वहां विश्वविद्यालय यह निश्चित कर ले कि प्रवेश पुस्तिका, निर्देश पुस्तिका यह विवरण पत्रिका प्रकाशित करें तो यह विनियम के विनियम 6.1 के खण्ड (ए) और खण्ड (बी) का अनुपालन करें।

घ प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र, नामांकन अथवा पंजीकरण में एक शपथ पत्र आवश्यक रूप से अंग्रेजी और हिन्दी/ अभ्यर्थी की ज्ञात किसी एक प्रादेशिक भाषा में इन विनियम के संलग्नक 1 के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए तथा हस्ताक्षर किया जाए कि उसने किसी अधिनियम के नियमों के पढ़ लिया है तथा इन विनियम के नियमों तथा विनियम के नियमों तथा विधि को समझ लिया है तथा वह रैगिंग निषेध तथा इसके लिए निर्धारित दंड को जानता/जानती है। वह यह घोषण करता/करती है कि उसे किसी संस्था द्वारा निष्कासित/निकाला नही गया है । साथ ही वह रैगिंग संबंधी किसी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा/होगी और यदि वह रैगिंग करने अथवा रैगिंग के दुष्प्रेरण का दोषी पाया/पायी गई तो उसे इन विनियम तथा विधि के अनुसार दंडित किया जा सकता है और वह दंड केवल निष्कासन तक सीमिति नही होगा।

ड़ प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र , नामांकन अथवा पंजीकरण में एक शपथ पत्र अंग्रेजी

और हिन्दी तथा किसी एक प्रादेशिक भाषा या हिन्दी भाषा में इन विनियमों के साथ संलग्नक है । अभ्यर्थी के माता–पिता अभिभावक की ओर से दिया जाए कि उन्होंने रैगिंग के अधिनियम को पढ़ लिया है तथा समझ लिया है तथा रैगिंग रोकने संबंधित अन्य कानून को वो जानते हैं तथा इसके लिए निर्धारित दंड को जानते हैं। वे घोषणा करते हैं कि उनका वार्ड किसी संस्था द्वारा निष्कासित नही किया गया है और न ही निकाला गया है तथा उनका वार्ड रैगिंग से सम्बन्धित किसी कार्य में प्रत्यक्ष/परोक्ष अथवा रैगिंग के दुष्प्रेरण में भाग नही लेगा और यदि वह इसका दोषी पाया गया तो उनको इन विनियम तथा कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। यह दंड केवल निष्कासन तक सीमित नहीं होगा।

च प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र के साथ स्कूल लीविंग/स्थानांतरण प्रमाण–पत्र/प्रवास प्रमाण–पत्र/चरित्र प्रमाण पत्र हो जिसमें छात्र के व्यक्तिगत तथा समाजिक व्यवहार की जानकारी दी गई हो ताकि संस्था इसके बाद उस पर नजर रख सके।

छ संस्था के/संस्था द्वारा व्यवस्थित व्यवस्था किए गए छात्रावास की प्रार्थना करने वाले छात्र को प्रार्थना पत्र के साथ एक अतिरिक्त शपथ पत्र देना होगा। शपथ पत्र पर उसके माता/पिता/अभिभावक के भी हस्ताक्षर होंगे।

ज किसी भी संस्था में शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व संस्था अध्यक्ष विभिन्न अधिकारियों/अभिकरणों जैसे छात्रपाल (वार्डेन) छात्र प्रतिनिधि, छात्रों के माता–पिता अभिभावक, जिला प्रशासन पुलिस आदि की मीटिंग आयोजित करे तथा रैगिंग रोकने के उपयों और उसमें संलिप्त अथवा उसका दुष्परिणाम करने वालों को चिन्हित कर दण्डित करने पर विचार–विमर्श हेतु उसे सम्बोधित करें।

झ समुदाय, विशेष रूप से छात्रों को रैगिंग के अमानवीय प्रभाव के संदर्भ में जागृत करने हेतु तथा संस्था उसके प्रति रवैये से अवगत कराने हेतु बड़े पोस्टर (वरीयता से बाहुरंगी) नियम विधि तथा दंड हेतु छात्रावास, विभागों तथा अन्य भवनों के सूचना पट्ट पर लगाया जाए। उनमें से कुछ पोस्टर स्थायी रूप के हों जिन स्थानों पर छात्र एकत्र होते हैं वहां रैगिंग का आघात किए

जाने योग्य स्थानों पर विशेष रूप से ऐसे पोस्टर लागाए जाएँ।

त्र संस्था मीडिया से यह अनुरोध करे कि वह रैगिंग रोकने के नियमों का प्रचार–प्रसार करे। संस्था के रोकने और उसमें लिप्त पाए जाने पर बिना भेद–भाव एवं भय के दण्डित करने के नियम प्रचार करें।

ट संस्था द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों को समझाया जाए तथा असुरक्षित स्थानों पर दृष्टि रखी जाए। संस्था द्वारा परिसर में विषम समय तथा शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए तथा रैगिंग किए जाने योग्य स्थानों पर दृष्टि रखी जाए। पुलिस, रैगिंग विरोधी सचल दल तथा स्वयं सेवी (यदि कोई हो) व्यक्तियों से इसमें सहायता ली जाए।

ठ संस्था अवकाश के समय को नए शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ से पूर्व रैगिंग के विरुद्ध संगोष्ठी, पोस्टर, पत्रिका, नुक्कड़ नाटक आदि के द्वारा प्रचार करें।

ड संस्था के विभिन्न तंत्र संकाय/विभाग/इकाई आदि।

ढ संस्था के संकाय/विभाग/इकाई आदि छात्रों की विशेष आवश्यकताओं का पूर्वानुमान कर निवारण करें तथा शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व रैगिंग निषेध संबंधी अधिनियम के लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विधिवत् प्रबन्ध करें।

ण प्रत्येक संस्था अकादमिक सत्र प्रारम्भ होने से पहले पेशेवर काउंसिलरों की सेवा अथवा सहायता ले और वे शैक्षिक वर्ष प्रारम्भ होने के बाद भी नए तथा अन्य छात्रों की काउंसिलिंग के लिए उपलब्ध हों।

त संस्थाध्यक्ष स्थानीय पुलिस तथा अधिकारियों को वित्तीय आधार पर प्रबन्ध किए गए छात्रावास तथा निवास हेतु प्रयोग किये जा रहे भवन के संबन्ध में विस्तृत जानकारी दें। संस्थाध्यक्ष यह भी सुनिश्चित करें कि रैगिंग विरोधी दल ऐसे स्थानों पर रैगिंग रोकने हेतु चौकसी रखें।

6.2 **छात्रों का प्रवेश, नामांकन अथवा पंजीकरण होने पर निम्नलिखित कदम उठाए, जिसका नाम इस प्रकार है–**

क संस्था में प्रवेश दिए गए प्रत्येक छात्र को एक मुद्रित पर्णिका दी जाए जिसमें यह बताया गया हो कि उसे विभिन्न उद्देश्यों हेतु किससे निर्देशन प्राप्त करना

है। इसमें विभिन्न अधिकारियों के दूरभाष नं0 तथा पते भी दिए जाएँ ताकि आवश्यकता पड़ने पर छात्र किसी भी संबंधित व्यक्ति से तुरन्त संपर्क करें। इन विनियम में संदर्भित रैगिंग विरोधी हैल्पलाईन, वार्डन, संस्थाध्यक्ष तथा रैगिंग विरोधी समिति तथा दल के सदस्यों तथा संबंधित जिले तथा पुलिस के अधिकारियों के पते और दूरभाष नं0 विशेष रूप से समाहित किए जाएँ।

ख संस्था इन विनियम के विनियम 6.2 खण्ड (ए) में निर्देश दिए गयें हैं। प्रबंधक को नए छात्रों को दी जानेवाली पर्णिका द्वारा स्पष्ट करें तथा उन्हें अन्य छात्रों से भलीभाँति परिचित कराने हेतु कार्य करें।

ग इन विनियमों के विनियम 6.2 खण्ड (ए) में निर्देशित पर्णिका द्वारा नए छात्रों को संस्था के बोनाफाइड स्टूडेंट के रूप में उनके अधिकार भी बताएं जाएं। उन्हें यह भी बताया जाए कि वे अपनी इच्छा के बिना किसी का कोई कार्य न करें चाहे उनके लिए उनके वरिष्ठ छात्रों ने कहा हो तथा रैगिंग के प्रयास के सूचना तुरन्त रैगिंग विरोधी दल, वार्डन अथवा संस्थाध्यक्ष को दे दें।

घ इन विनियमों के विनियम 6.2 खण्ड (ए) में निर्देशित पर्णिका में संस्था में मनाएं जानेवाले विभिन्न कार्यक्रमों तथा गतिविधियों की तिथि दी हो ताकि नए छात्र संस्था के शैक्षिक परिवेश एवं वातावरण से परिचित हो सकें।

ड़ वरिष्ठ छात्रों के आने पर संस्थान प्रथम अथवा द्वितीय सप्ताह के बाद जैसा भी हो अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करें जिनका नाम – (i) संयुक्त सैंसेटाइजेशन प्रोग्राम और वरिष्ठ और कनिष्ठ छात्रों की काउंसिलिंग व्यावसायिक काउन्सर के साथ खण्ड – 6.1 नियम के विनियम के अनुसार करे (ii) नये और पुराने छात्रों को संयुक्त अभिविन्यास कार्यक्रम को संस्था तथा रैगिंग विरोधी समिति सम्बोधित करे (iii) संकाय सदस्यों की उपस्थिति में नये और पुराने छात्रों के परिचय हेतु अधिकाधिक, सांस्कृतिक खेल तथा अन्य प्रकार की गतिविधिया आयोजित की जाये (iv) छात्रावास में वार्डन सभी छात्रों को सम्बोधित करे तथा अपने दो (2) कनिष्ठ सहयोगियों से कुछ समय तक सहयोग देने हेतु निवेदन करे (v) जहाँ तक संभव हो संकाय--सदस्य हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के साथ भोजन भी करे ताकि नये छात्रों में आत्मविश्वास

का भाव उत्पन्न हो।

च संस्था समुचित समितियों का गठन करे । कोर्स इंचार्ज, वार्डन तथा कुछ वरिष्ठ छात्र इन समितियों के सदस्य हों। यह समिति नये और पुराने छात्रों के बीच सम्बंध सुदृढ़ बनाने में सहयोग दे।

छ नये अथवा अन्य छात्र चाहे वे रैगिंग के भोगी हों अथवा रैगिंग होते हुए उन्होंने दोषी को देखा हो उन्हें ऐसी घटनाओं की सूचना देने हेतु उत्साहित किया जाए ताकि उनकी पहचान सुरक्षित रखी जाए और ऐसी घटनाओं की सूचना देने वालों को किसी दुष्परिणाम से बचाया जाए।

ज संस्था में आने पर नये छात्रों के प्रत्येक बैच को छोटे–छोटे वर्गों में बांट दिया जाए और ऐसा प्रत्येक वर्ग किसी एक संकाय सदस्य को दे दिया जाए जो स्वयं वर्ग ग्रुप के सभी सदस्यों से परिचित हो और यह देखे कि नये छात्रों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो यदि हो तो उसका समाधान करने में उचित सहायता करे।

झ इस प्रकार की समिति के संकाय सदस्य का यह दायित्व होगा कि वार्डनों को सहयोग दे तथा छात्रावास में औचक निरीक्षण करते रहें । जहाँ संकाय सदस्य की अपने अधीन छात्रों की डायरी मेन्टेन करें।

ञ नये छात्रों को अलग छात्रावास में रखा जाये और जहाँ इस प्रकार की सुविधायें न हों वहाँ संस्था यह सुनिश्चित करें कि नये छात्रों को दिये गये निवास स्थानों पर वार्डन तथा सुरक्षा गार्ड और कर्मचारी कड़ी निगरानी रखें।

ट संस्था 24 घंटे छात्रावास परिसर में रैगिंग रोकने के लिए कड़ी नजर रखने का प्रबन्ध करें ।

ठ नये छात्रों के माता–पिता/अभिभावकों का यह दायित्व होगा कि रैगिंग से सम्बन्धित सूचना संस्था–अध्यक्ष को प्रदान करें।

ड प्रवेश के समय प्रत्येक छात्र जो संस्था में पढ़ रहा हो । वह और उसके माता–पिता/अभिभावक प्रवेश के समय निर्देशित शपथ पत्र दे जैसा कि विनियम के विनियम 6.1 खण्ड (डी) (ई) और (जी) के अनुसार दिया जाना । प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में चाहिए।

ढ प्रत्येक संस्था विनियम (6.2) खण्ड -- एल के सन्दर्भ अनुसार प्रत्येक छात्र से शपथ पत्र ले और उनका उचित रिकार्ड रखे। प्रतिलिपियों को इलेक्ट्रानिक रूप में सुरक्षित रखे ताकि जब आवश्यकता हो कमीशन अथवा कोई संकलित अथवा संस्था अथवा सम्बन्धित विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य सक्षम व्यक्ति अथवा/संघटन द्वारा उन्हें प्राप्त किया जा सके।

ण प्रत्येक छात्र/छात्रा अपने पंजीकरण के समय संस्था को अपनी पढ़ाई करते समय निवास स्थान की सूचना दे यदि उसका निवास स्थान तय नही किया है या वह अपने निवास बदलना चाहता/चाहती है तो उसका निश्चम होती ही विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी जाए और विशेष रूप से निजी खर्च पर व्यक्ति किये गये भवनों अथवा छात्रावासों की जहां वह रह रहा है/रही है।

ण आयोग शपथ पत्रों के आधार पर एक उचित आंकड़ा बनाये रखे जो प्रत्येक छात्र और उसके माता/पिता/अभिभावक द्वारा संस्था को उपलब्ध कराया गया हो। इस प्रकार का आंकड़ा रैगिंग की शिकायतों तथा उसके बाद की गयी कार्यवाही का रिकार्ड भी रखे।

त आयोग द्वारा आंकड़ा गैर सरकारी निकाय जिसे केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया गया हो को उपलब्ध कराया जाये इससे आम जनता में विश्वास तथा समिति के आदेश का अनुपालन न करने की सूचना दी जा सके।

थ प्रत्येक शैक्षिक वर्ष पूर्ण होने पर संस्थाध्यक्ष प्रथम वर्ष पूर्ण करनेवाले छात्रों के माता–पिता/अभिभावकों को रैगिंग से सम्बन्धित विधि और जानकारी से सम्बन्धित पत्र भेजें तथा उनसे अनुरोध करें कि नए शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ में वापस आने पर उनके स्वयं बालक रैगिंग से सम्बन्धित किसी गतिविधि में भाग न लें।

6.3 **प्रत्येक संस्था निम्नलिखित नामों से समितियाँ गठित करें।**

क प्रत्येक संस्था एक समिति बनाए जिसे रैगिंग विरोधी समिति (एंटी रैगिंग कमेटी) कहा जाए। समिति की अध्यक्षता संस्थाध्यक्ष करें तथा समिति के सदस्यों को वे ही नामांकित करें। इसमें पुलिस तथा नागरिक प्रशासन के प्रतिनिधि भी हो। स्थानीय मीडिया युवा गतिविधियों से जुड़े गैर सरकारी संघटक संकाय सदस्यों के प्रतिनिधि, माता–पिता में से प्रतिनिधि, नए तथा पुराने छात्रों के प्रतिनिधि, शिक्षणेतर कर्मचारी तथा विभिन्न वर्गों से प्रतिनिधि समिति में से लिंग के आधार पर इस समिति में स्त्री पुरूष दोनों हों।

ख रैगिंग विरोधी समिति का कर्तव्य होगा कि वह इन विनियम प्रावधान तथा रैगिंग से सम्बनिधत कानून का अनुपालन कराए तथा रैगिंग विरोधी दल के रैगिंग रोकने सम्बन्धी कार्यों को भी देखे।

ग प्रत्येक संस्था एक छोटी समिति का भी गठन करे जिसे रैगिंग विरोधी (एंटी रैगिंग स्क्वैड) नाम से जाना जाए। इसे भी संस्थाध्यक्ष द्वारा नामित किया जाए। यह समिति नजर रखे तथा हर समय पैटरॉलिंग और गतिशील बनी रहने हेतु तत्पर रहे।

रैगिंग विरोधी दल/स्क्वैड में कैम्पस के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। इसमें परिसर से बाहर के व्यक्ति नही होंगे।

घ रैगिंग विरोधी दल का यह दायित्व होगा कि वह छात्रावास तथा रैगिंग की दृष्टि से संवेदनशील अन्य स्थानों का घटना की औचक निरीक्षण करें।

ड़ रैगिंक विरोधी दल का यह दायित्व होगा कि वह संस्थाध्यक्ष अथवा अन्य किसी संकाय सदस्य अथवा किसी कर्मचारी अथवा किसी छात्र अथवा किसी माता–पिता अथवा अभिभावक द्वारा सूचित की गई रैगिंग की घटना की जाँच घटना स्थल पर जाकर करे तथा जाँच की रिपोर्ट संस्तुति सहित रैगिंग विरोधी समिति को विनियम 9.1 उपखण्ड (ए) के अनुसार कार्रवाई हेतु सौंपे।

रैगिंग विरोधी दल इस प्रकार की जाँच निष्पक्ष एवं पारदर्शी विधि से करे तथा सामान्य न्याय का पालन किया जाए। रैगिंग के दोषी पाए जानेवाले

छात्र/छात्रों तथा गवाहों को पूरा अवसर देने तथा तथ्य एवं प्रमाण आदि देखने के बाद इसकी सूचना प्रेषित की जाए।

6.3 प्रत्येक संस्था शैक्षिक वर्ष पूर्ण होने पर इन विनियम के उद्देश्य प्राप्त करने हेतु एक मॉनिटरिंग सेल बनाए जिसमें नए छात्रों को मॉनेटर करनेवाले स्वयंसेवी छात्र हों। नए छात्रों पर एक मॉनेटर होना चाहिए।

छ प्रत्येक विश्वविद्यालय, एक समिति का गठन करे जिसे रैगिंग के मॉनिटरिंग सेल के रूप में जाना जाए, जो उस संस्था अथवा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कॉलेजों में इन विनियम के उद्देश्य प्राप्त करने हेतु सहयोग दें। मॉनिटरिंग सेल संस्थाध्यक्षों रैगिंग विरोधी समिति रैगिंग विरोधी दल से रैगिंग गतिविधियों की सूचना प्राप्त कर सकता है। वह जिलाधिकारी को अध्यक्षता में गठित/जनपद स्तरीय रैगिंग विरोधी समिति के सम्पर्क में रहे।

ज मॉनिटरिंग सेल; संस्था द्वारा किए जा रहे रैगिंग विरोधी उपायों का भी मूल्यांकन करेगी । माता–पिता/अभिभावकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में दिए गए शपथ पत्र तथा रैगिंग के नियम तोड़ने पर दण्डित किए जाने हेतु उनकी सहमति की भी जांच करेगा। यह दोषियों को दण्डित किए जाने हेतु उसकी मुख्य भूमिका होगी । रैगिंग विरोधी उपायों के कार्यान्वयन में भी इसकी मुख्य भूमिका होगी।

6.4 प्रत्येक संस्था निम्नलिखित उपाय भी करे, जिनका नाम हो–

क प्रत्येक छात्रावास अथवा स्थान जहाँ छात्र रहते है। संस्था के उस भाग में पूर्णकालिक वार्डन हों जिसकी नियुक्ति संस्था द्वारा अर्हता के नियमानुसार की जाय जो अनुशासन बनाये रखें तथा छात्रावास में रैगिंग की घटनाओं को रोकने के साथ ही युवाओं से कक्षा के बाहर काउंसलिंग और सम्बंध बनाये रखे। वह छात्रावास में रहे या छात्रावास के अत्यन्त निकट रहे।

ख वार्डन हर समय उपलब्ध हो। दूरभाष तथा संचार के अन्य साधनों से हर समय सम्पर्क किया जा सके। वार्डन को संस्था द्वारा मोबाइल फोन उपलब्ध कराया जाये जिसके नम्बर की जानकारी छात्रावास में रह रहे सभी छात्रों को हो।

ग संस्था द्वारा वार्डन तथा रैगिंग रोकरने से सम्बन्धित अन्य अधिकारियों के अधिकार बढ़ाने का विचार किया जा सकता है। छात्रावास में नियुक्त सुरक्षाकर्मी सीधे वार्डनों के नियंत्रण में हों तथा वार्डन द्वारा उनके कार्य का मूल्यांकन किया जाए

घ इन विनियमों के विनियम 6.1 उपखण्ड (ओ) के अनुसार प्रवेश के समय पेशेवर काउंसिलर रखे जायें जो नये और अन्य छात्र जो अपने आने वाले जीवन की तैयारी हेतु विशेष रूप छात्रावास में रहने से सम्बन्धित काउन्सिलिंग चाहते हो उनहें कॉउसिंलिंग करें। ऐसे काउन्सिलिंग सत्रों से माता–पिता तथा शिक्षकों को भी जोड़ा जाये।

ड़ संस्था रैगिंग विरोधी उपायों का व्यापक काउन्सिलिंग सत्र, कार्यशाला, पेंटिग द्वारा यह कार्य किया जा सकता है।

च संस्था के संकाय सदस्य उसका शिक्षणेतर कर्मचारी, जो केवल प्रशासनिक पद तक सीमित नहीं है, सुरक्षा गार्डस तथा संस्था के अन्दर सेवा करनेवाले कर्मचारियों को रैगिंग तथा उसके दुष्परिणाम के प्रति संवेदनशील बनाया जाए।

छ संस्था/शिक्षण एवं शिक्षणेतर प्रत्येक कर्मचारी से संविदा पर रखे गए प्रत्येक श्रमिक से चाहे वे कैंटीन के कर्मचारी हों अथवा सुरक्षा गार्ड हों या सफाई वाले कर्मचारी हों सबसे एक अनुबन्ध ले कि वे अपनी जानकारी में आनेवाले रैगिंग की घटना की जानकारी तुरन्त सक्षम अधिकारियों को देंगे।

ज संस्था द्वारा सेवा कार्य की नियमावली में रैगिंग की सूचना देनेवाले कर्मचारियों को अनुशंसा पत्र देने का नियम बनाए तथा उसे उनके सेवा रिकॉर्ड में रखा जाए।

झ संस्था द्वारा कैंटीन और मैस के कर्मचारियों, चाहे वे संस्था के कर्मचारी हों अथवा निजी सेवा देने वाले हो को निर्देशित किया जाए कि वे अपने क्षेत्र में कड़ी नजर रखें तथा रैगिंग की कोई भी घटना होने पर उसको जानकारी तुरन्त संस्थाध्यक्ष रैगिंग विरोधी समिति के सदस्यों अथवा वार्डन को दें।

ञ शिक्षा की किसी भी स्तर की उपाधि देनेवाली संस्था यह देख ले कि उसके पाठ्यक्रम में रैगिंग विरोधी कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाए। मानव अधिकारों की रक्षा पर बल दिया जाए। विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम में रैगिंग की संवेदनशीलता पर प्रकाश डाला जाए। प्रत्येक शिक्षक काउन्सिलिंग के स्थिति से निबटने का ढंग आना चाहिए।

ट प्रथम वर्ष नए विद्यार्थियों की ओर हर पन्द्रह दिन में गुमनाम बेतरतीब सर्वेक्षण कि जाएँ । यह देखने के लिए कि संस्था में रैगिंग नहीं हो रही है। सर्वेक्षण की रूपरेखा संस्था स्वयं निश्चित करे। संस्था द्वारा छात्र को दिए जानेवाले विश्वविद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र में छात्र के सामान्य चरित्र और व्यवहार के अतिरिक्त यह भी दिया जाए कि क्या छात्र कभी रैगिंग सम्बन्धी अपराध में संलिप्त रहा है। क्या छात्र ने कोई हिंसक अथवा दूसरे को हानि पहुँचाने वाला अपराध किया है।

ठ इन विनियमों विभिन्न अधिकारियों सदस्यों तथा समितियों के अधिकार बताए गए हैं। इसके साथ ही सभी वर्गों के अधिकारियों संकाय के सदस्यों तथा कर्मचारियों सहित चाहे वह स्थायी हो अथवा अस्थायी जो भी संस्था की सेवा कर रहा है उसका यह सामूहिक दायित्व होगा कि वह रैगिंग की घटनाओं को रोके।

ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थाध्यक्ष अथवा अन्य संस्था का अध्यक्ष सत्र के प्रारम्भिक तीन महीने तक रैगिंग के आदेश के अनुपालन तथा रैगिंग विरोधी उपायों की जानकारी से सम्बन्धित इन विनियम के अधीन साप्ताहिक रिपोर्ट उस विश्वविद्यालय के कुलपति अथवा जिसके द्वारा वह संस्था रिकॉग्नाइज की गई हैं। उसे दें।

ढ प्रत्येक विश्वविद्यालय को कुलपति महोदय विश्वविद्यालय तथा रैगिंग की देखरेख करनेवाले सेल की रिपोर्ट प्रत्येक पन्द्रह दिन बाद राज्य स्तरीय देख रेख करने

वाले सेल को दें।

7 **संस्थाध्यक्ष द्वारा की जानेवाली कार्रवाई–**

I. रैगिंग विरोधी दल अथवा सम्बन्धित किसी के भी द्वारा रैगिंग की सूचना प्राप्त होने पर संस्थाध्यक्ष तुरन्त सुनिश्चित करें कि क्या कोई अवैध घटना हुई है और यदि हुई है तो वह स्वयं अथवा उसके द्वारा अधिकृत रैगिंग विरोधी समिति से सूचना प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज कराए अथवा रैगिंग से सम्बन्धित विधि के अनुसार संस्तुति दे। रैगिंग के अंतर्गत निम्नलिखित अपराध आते हैं।

II. रैगिंग हेतु उकसाना

III. रैगिंग का आपराधिक षड्यंत्र

IV. रैगिंग के समय अवैध ढंग से एकत्र होना तथा उत्पात करना

V. रैगिंग के समय जनता को बाधित करना

VI. रैगिंग के द्वारा शालीनता और नैतिकता भंग करना

VII. शरीर को चोट पहुँचाना

VIII. गलत ढंग से रोकना

IX. आपराधिक बल प्रयोग

X. प्रहार करना, मौन सम्बन्धी अपराध अथवा अप्राकृतिक अपराध

XI. बलात् ग्रहण

XII. आपराधिक ढंग से बिना अधिकार दूसरे के स्थान में प्रवेश करना

XIII. सम्पत्ति से सम्बन्धित अपराध

XIV. आपराधिक धमकी

XV. मुसीबत में फँसे व्यक्तियों के प्रति उपर्युक्त में से कोई अथवा सभी अपराध करना

XVI. उपर्युक्त में से कोई एक अथवा सभी अपराध पीड़ित के विरुद्ध करने हेतु धमकाना

XVII. शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अपमानित करना

XVIII. रैगिंग की परिभाषा से सम्बन्धित सभी अपराध

रैगिंग की परिभाषा से सम्बन्धित सभी अपराध यह भी उल्लेख किया जाता है ।

संस्थाध्यक्ष रैगिंग की घटना की सूचना तुरन्त जिला स्तरीय रैगिंग विरोधी समिति तथा सम्बद्ध विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी को दें।

यह भी उल्लेख किया जाता कि संस्था इन विनियम के खण्ड 9 के अधीन अपनी जाँच और उपाय पुलिस तथा स्थानीय अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कारवाई की प्रतीक्षा किए बिना प्रारम्भ कर दे और घटना के एक सप्ताह के भीतर औपचारिक कारवाई पूरी कर ली जाए।

8 आयोग और परिषद के कर्तव्य एवं दायित्व

8.1 आयोग रैगिंग से सम्बन्धित घटनाओं की शीघ्र सूचना हेतु निम्नलिखित कार्य करेगा--

क आयोग धन निर्धारित करेगा तथा एक टॉल फ्री रैगिंग विरोधी सहायता लाइन बनाएगा जो 24 घंटे खुली रहेगी जिसका छात्र रैगिंग से सम्बन्धित घटनाओं के निवारण हेतु प्रयोग कर सकते हैं।

ख रैगिंग विरोधी हेल्पलाइन पर प्राप्त किया गया संदेश तुरन्त संस्थाध्यक्ष, छात्रावास के वार्डन सम्बद्ध विश्वविद्यालय नोडल अधिकारी को प्रसारित किया जाएगा। सम्बद्ध जिले के अधिकारियों यदि आवश्यकता हुई तो जिला अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक को दी जाएगी तथा वेबसाइट पर डाल दी जाएगी ताकि मीडिया तथा सामान्य जनता उसका विश्लेषण करे।

ग संस्थाध्यक्ष को एंटी रैगिंग हेल्पलाइन पर मिली सूचना पर त्वरित कार्रवाई इन विनियम के उपखण्ड (बी) के अनुसार करनी होगी।

घ छात्र अथवा किसी भी व्यक्ति को रैगिंग विरोधी हेल्पलाइन पर संदेश देने हेतु संस्था मोबाइल और फोन के बे-रोक-टोक प्रयोग की छात्रावास तथा परिसर, कक्षाएँ, संगोष्ठी कक्ष पुस्तकालय आदि के अतिरिक्त सभी स्थानों पर प्रयोग की अनुमति के अतिरिक्त सभी स्थानों पर प्रयोग की अनुमति देगा।

ङ रैगिंग विरोधी हेल्पलाइन तथा अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों, संस्थाध्यक्षों संकाय के सदस्यों, रैगिंग विरोधी समिति के सदस्यों तथा रैगिंग विरोधी दल, जिले के अधिकारियों, हॉस्टल के वार्डनों तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों, फोन नम्बर

तथा पते छात्रों को उपलब्ध कराए जाएँ ताकि आकस्मिकी में वे उनका प्रयोग कर सकें।

च आयोग छात्रों तथा उसके माता–पिता/अभिभावक द्वारा दिए गए शपथ पत्रों के आधार पर आंकड़ा रखेगा। यह आंकड़ा रैगिंग की शिकायतों तथा उस पर की गई कार्रवाई के रिकार्ड के रूप में कार्य करेगा।

छ आयोग इस आंकड़े को केन्द्र सरकार द्वारा नामित एवं गैर सरकारी संघटन को उपलब्ध कराएगा। इससे आम जनता में विश्वास बढ़ेगा इन विनियम के अनुपालन न करने की सूचना भी आयोग केन्द्र सरकार द्वारा अधिकृत समितियों को उपलब्ध कराएगा।

8.2, **आयोग नियम के अनुसार निम्नलिखित कदम उठाएगा–**

क आयोग संस्था हेतु यह आवश्यक करेगा कि वह अपनी विवरणिका में केन्द्र सरकार के निर्देश अथवा राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति के रैगिंग निषेध सम्बन्धी निर्देश और उसके परिणाम समाहित करें । यदि वे ऐसा नहीं करते तो यह माना जाएगा कि वे शिक्षा का स्तर गिर रहे है। तथा इसके लिए उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी।

ख आयोग यह प्रमाणित करेगा कि इन विनियमों के अनुसार छात्रों तथा उनके माता–पिता/अभिभावक से शपथ पत्र संस्था द्वारा प्राप्त किया जा रहा है।

ग आयोग द्वारा संस्था को दी जा रही किसी प्रकार की विशेष अथवा सामान्य किसी प्रकार की आर्थिक सहायता अथवा अनुदान के युटिलाइजेशन प्रमाण पत्र में एक शर्त यह लगाई जाएगी कि संस्था द्वारा रैगिंग निषेध सम्बन्धी विनियम एवं उपायों का अनुपालन किया जा रहा है।

घ रैगिंग की किसी भी घटना का संस्था के रैंक अथवा एन.ए.ए.सी. अथवा किसी अन्य सक्षम एजेंसी द्वारा दी जानेवाले रैंकिंग और ग्रेडिंग पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है।

ड़ आयोग उन संस्थाओं को अतिरिक्त अनुदान दे सकता है अथवा अधिनियम खण्ड 12 बी के लिए अर्ह मान सकता है। जहाँ रैगिंग की घटनाएँ नहीं होंगी।

च जहाँ रैगिंग की घटनाएं नहीं होंगी। आयोग रैगिंग रोकने के लिए एक इंटर

कौंसिल कमेटी बनाएगा जिसमें की भिन्न परिषदों के प्रतिनिधि होंगे। गैर सरकारी एजेंसी आयोग द्वारा रखे जा रहे आंकड़े को देखने के लिए उपखंड (जी) अधिनियम 8.1 के और इस प्रकार के निकाय उच्चतर शिक्षा में रैगिंग विरोधी उपारयों को दखेने तथा सहयोग देने हेतु तथा समय--समय पर संस्तुतियाँ देने हेतु और प्रत्येक वर्ष के छः महीने में इसकी कम से कम एक बैठक होगी। आयोग एक रैगिंग विरोधी सेल आयोग में बनाएगा। जो रैगिंग से सम्बन्धित सूचनाएँ एकत्र करने तथा उसपर दृष्टि रखने में सचिव की सहायता करेगा। राज्य स्तरीय दृष्टि रखने वाले सेल को ताकि रैगिंग को रोकने के उपायों पर सुचारू रूप से कार्य हो सके। यह सेल गैर सरकारी संघटन जो रैगिंग रोकने से सम्बन्धित होंगे, को आंकड़े देख रेख में सहायता देगा। इसकी संरचना अधिनियम 8.1 के खण्ड (जी) के अधीन की जाएगी।

9 रैगिंग की घटनाओं पर प्रशासनिक कार्रवाई–

9.1 किसी छात्र को रैगिंग का दोषी पाए जाने पर संस्था द्वारा निम्नलिखित विधि अनुसार दण्ड दिया जाएगा।

क रैगिंग विरोधी समिति उचित दण्ड के सम्बन्ध में उचित निर्णय लेगी अथवा रैगिंग कीं घटना के स्वरूप एवं गम्भीरता को देखते हुए रैगिंग विरोधी दल दण्ड हेतु अपनी संस्तुति देगा।

ख रैगिंग विरोधी समिति रैगिंग विरोधी दल द्वारा निर्धारित किए गए अपराध के स्वरूप और गम्भीरता को देखते हुए निम्नलिखित में को कोई एक अथवा अनेक दण्ड देगी।

I. कक्षा में उपस्थित होने तथा शैक्षिक अधिकारियों से निलम्बन

II. छात्रवृत्ति/छात्र अध्येतावृत्ति तथा अन्य लाभों को रोकना/वंचित करना

III. किसी टैस्ट/परीक्षा अथवा अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया में उपस्थित होने से वंचित करना

IV. परीक्षाफल रोकना

V. किसी प्रादेशिक, राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मीट, खेल, युवा महोत्सव आदि में संस्था का प्रतिनिधित्व करने से वंचित करना।

VI. छात्रावास से निष्कासित करना

VII. प्रवेश रद्द करना

VIII. संस्था से 04 सत्रों तक के लिए लिए निष्कासन करना।

IX. संस्था से निष्कासित और परिणाम रूवरूप किसी भी संस्था में निश्चित अवधि तक निष्कासन करना। जब रैगिंग करने अथवा रैगिंग करने के लिए भड़काने वाले व्यक्तियों की पहचान न हो सके संस्था सामूहिक दण्ड का आश्रय ले।

ग रैगिंग विरोधी समिति द्वारा दिए गए दण्ड के विरुद्ध अपील (प्रार्थना) निम्नलिखित से की जाएगी।

I. किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्था होने पर कुलपति से।

II. विश्वविद्यालय का आदेश होने पर कुलाधिपति से

III. संसद के अधिनियम के अनुसार निर्मित राष्ट्रीय महत्व की संस्था होने पर उसके चेयनमेन अथवा चांसलर अथवा स्थिति के अनुसार

9.2 यदि किसी विश्वविद्यालय के अधीन/सम्बद्ध कोई संस्था (जो उसके विधान मं, सम्बद्ध अथवा उसके द्वारा मान्यता प्राप्त हो) इनमें से किसी नियम विनियम के अनुपालन में असफल रहती है तथा रैगिंग को प्रभावशाली ढंग से रोकने में असफल रहता है तथा विश्वविद्यालय उस पर निम्नलिखित में से कोई एक अथवा किसी समूहकार दण्ड लगा सकता है–

I. सम्बद्धता/रेकगजिशन या उसे दिए गए अन्य विशेष अधिकार वापस लेना

II. इस प्रकार की संस्था को चल रहे किसी शैक्षिक प्रोग्राम में डिग्री अथवा डिप्लोमा में भाग लेने से रोकना।

III. विश्वविद्यालय द्वारा उसे दिए जा रहे अनुदान को वापस लेना, यदि कोई हो।

IV. विश्वविद्यालय द्वारा संस्था के माध्यम से दिए जा रहे किसी अनुदान को रोकना

V. विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में आनेवाला कोई अन्य दण्ड

9.3 जहाँ नियुक्ति देने वाले अधिकारी का विचार है कि संस्था को किसी कर्मचारी द्वारा रैगिंग की सूचना देने में ढील बरती गई है। रैगिंग की सूचना देने में त्वरित कार्रवाई नहीं की है। रैगिंग की घटना अथवा घटनाएँ रोकने के लिए नहीं की है। इन विनियम के अनुसार आवश्यक कार्रवाई नही की है। रैगिंग की उस अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

यदि इस प्रकार की ढील संस्थाध्यक्ष के स्तर पर हुई है तो संस्थाध्यक्ष की नियुक्ति करनेवाले अधिकारी द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी।

9.4 कोई भी संस्था जो रैगिंग रोकने इन विनियम के अनुसार कार्रवाई नही करेगा अथवा दोषियों को दण्डित नहीं करता तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उसके विरुद्ध निम्नलिखित में से कोई एक अथवा अनेक कार्रवाई करेगा।

I. अधिनियम के खण्ड 12 बी के अन्तर्गत दिए जानेवाले अनुदान को रोकना।

II. दिया जा रहा कोइ अनुदान वापस लेना।

III. आयोग द्वारा दी जानेवाली सामान्य अथवा किसी विशेष आसिस्टेंस प्रोग्राम हेतु संस्था को अयोग घोषित करना।

IV. सामान्य जनता अभ्यर्थियों को समाचार पत्र, मीडिया, आयोग की वैबसाइट आदि द्वारा यह बताना कि संस्था में लघुतम शैक्षिक स्तर उपलब्ध नहीं है।

V. इसी प्रकार की अन्य कार्रवाई करना तथा इसी प्रकार से संस्था को तब तक दंडित करना जब तक कि वह रैगिंग रोकने के लक्ष्य को प्राप्त न कर ले

अयोग द्वारा किसी संस्थान के विरुद्ध इस अधिनियम के अनुसार की गई कार्रवाई में सभी समितियाँ सहयोग देंगी।

(डॉ. आर. के. चौहान)
सचिव

सेवा में,

सहायक नियंत्रक
प्रकाशन प्रभाग, भारत सरकार
शहरी विकास तथा गरीबी निवारण मंत्रालय
सिविल लाईन, दिल्ली–110054

CURBING THE MENACE OF RAGGING IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS (SECOND AMENDMENT) REGULATION, 2013

UNDERTAKING BY THE STUDENTS & PARENT/GUARDIAN

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 101] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 29, 2014/ चैत्र 8, 1936
No. 101] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 29, 2014/CHAITRA 8, 1936

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 दिसम्बर, 2013

मि.सं. 15–3/2013 (ए.आर.सी.) पार्ट–III.–विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, (1956) (3–1956) की धारा (ग) के उप–अनुच्छेद (I) के अनुच्छेद 26 में प्रदत्त अधिकारों के क्रियान्वयन के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतद्द्वारा निम्न विनियम सृजन करता है, नामत :–

(1) यह विनियम "उच्चतर शैक्षिक संस्थानों" में रैगिंग के जोखिम के निराकरण (द्वितीय संशोधन) विनियम 2013 कहलायेंगे"।

(2) इन विनियमों के अनुलग्नकों–I एवं II के अंतर्गत रैगिंग के जोखिम पर नियंत्रण के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2009 (जो आगे से प्रमुख विनियम के रूप में जाने जाएँगे) इनमें सम्मिलित निम्न वाक्यों का विलोपन किया जाएगा:–

"सत्यनिष्ठापूर्वक पुष्टि की गई एवं इस पत्र की विषयवस्तु को पढ़कर इस (दिन) ..... (माह)..... (वर्ष) को मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया गया।

शपथ आयुक्त"

उपमन्यु बसु,सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./113/13]

पाद टिप्पणी:– प्रमुख विनियमों को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 27 दिनांक 07.07.2009 में प्रकाशित किया गया था।

अनुलग्नक–I

छात्र का आश्वासन

1. मैं ..... (प्रवेश/पंजकरण/नामांकन संख्या के साथ ही छात्र का पूरा नाम) सुपुत्र/सुपुत्री/..... श्री/श्रीमती/सुश्री ..... जिसे ..... में (संस्थान का नाम) प्रवेश दिया गया है, उसने उच्च शैक्षिक संस्थानों, में 2009, के जोखिम पर नियंत्रण संबंधी यूजीसी विनियमों की प्रति प्राप्त की है (जो इसके आगे से विनियम कहलायेंगे) तथा इन विनियमों में समाविष्ट प्रावधानों को ध्यानपूर्वक पढ़ कर पूरी तरह से समझ लिया है।

2. मैंने, विशेष रूप से इन विनियमों की धारा 3 को ध्यानपूर्वक पढ़ा है तथा मुझे इस बात का संज्ञान है कि रैगिंग में कौन सी बातें सम्मिलिति हैं।

3. मैंने विनियमों की धारा 7 एवं 9.1 को भी विशेष रूप से पढ़ा है तथा मैं उस दण्डात्मक एवं प्रशासनिक कार्रवाई के विषय में पूरी तरह से सचेत हूँ जो मेरे विरूद्ध लागू की जा सकती है यदि मैं रैगिंग को बढ़ावा देने के लिए दोषी पाया जाता हूँ अथवा रैगिंग को सक्रिय अथवा छिपे तौर से प्रोत्साहित करने अथवा इस विषय में षड्यन्त्र करने का दोषी पाया जाता हूँ।

4. मैं एतद्द्वारा सत्यनिष्ठ रूप से प्रमाणित करता/करती हूँ एवं आश्वासन देता/देती हूँ कि.....

(क) मैं ऐसे किसी व्यवहार अथवा कृत्य में संलिप्त नहीं होऊँगा/होऊँगी जिसे इन विनियमों की धारा 3 के अंतर्गत रैगिंग के रूप में माना जा सकता है।

(ख) मैं ऐसे किसी आचरण अथवा अनाचरण के काम में न तो भाग लूँगा/लूँगी न ही उसके षड्यन्त्र में अथवा उसके प्रोत्साहन में शामिल होऊँगा जिस कृत्य को इन विनियमों की धारा 3 के अंतर्गत रैगिंग के रूप में माना गया है।

5. मैं, एतद्द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि यदि मैं दोषी पाया जाता हूँ तो इन विनियमों की धारा 9.1 के अनुसार इनसे बिना पूर्वाग्रह के मैं दण्ड के लिए तथा ऐसी दण्डात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हूँ जो कि अन्य किसी आपराधिक मामले के प्रति किसी चालू दण्डात्मक अथवा अन्य किसी कानून के अनुसार मेरे विरूद्ध की जा सकती है।

6. मैं घोषित करता/करती हूँ कि इस देश के किसी भी संस्थान ने, मुझे रैगिंग के षड्यन्त्र में अथवा इसे प्रोत्साहित करने, इसको भड़काने में अथवा इसमें भाग लेने के मामले में दोषी पाने के लिए ना तो निष्कासित किया है ना ही प्रवेश से बाधित किया है–और मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि यदि की गई यह घोषणा असत्य पाई जाती है तो मुझे पूरी जानकारी है कि मेरा प्रवेश निरस्त करने का उत्तरदायित्व मुझ पर होगा।

घोषित किया गया ..... दिन..... माह ..... वर्ष

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि यह वचनबद्धता मेरे संज्ञान सर्वांगीण रूप से सत्य है तथा इसका कोई भी अंश असत्य नहीं है तथा इसमें कथित कोई भी बात ना तो छिपाई गई और ना ही अयर्थाथ कही गई है।

सत्यापित (स्थान) ..... दिन ..... माह ..... वर्ष.....

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम:

अनुलग्नक–II

माता–पिता/अभिभावक द्वारा दी गई प्रतिबद्धता

1. श्री/श्रीमती/सुश्री ..... (माता–पिता/अभिभावक का पूरा नाम छात्र का पूरा नाम, उसके प्रवेश/पंजीकरण/नामांकन संख्या सहित) के पिता–माता/अभिभावक, जिसके छात्र को ..... (संस्थान का नाम) में प्रवेश दिया गया है, इसने उच्च शैक्षिक संस्थानों, 2009, में रैगिंग के जोखिम पर नियन्त्रण लगाने से संबद्ध यूजीसी विनियमों (जो आगे से विनियम के नाम से कहलायेंगे) को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है तथा इन विनियमों में समाविष्ट प्रावधानों को पूरी तरह समझ लिया है।

2. मैंने, विशिष्ट रूप से इन विनियमों का अवलोकन किया है तथा मुझे इस बात की जानकारी है कि रैगिंग में क्या बात शामिल है।

3. मैंने विनियमों की धारा 7 एवं 9.1 का भी विशेष रूप से अध्ययन किया है तथा मैं पूरी तरह से जागरूक हूँ कि यदि मेरी संतान रैगिंग की अथवा रैगिंग में सहायक होने की सक्रिय अथवा छिपे तौर से दोषी पाया/पाई जाती है अथवा रैगिंग को बढ़ावा देने के षडयन्त्र का एक हिस्सा होता/होती है तो उस स्थिति में उसके विरूद्ध जिस दण्डात्मक एवं प्रशासनिक कार्रवाई का वह भागीदार होगा/होगी, वह मेरे संज्ञान में है।

4. मैं एतद्द्वारा सत्यनिष्ठ रूप से प्रमाणित करता/करती हूँ एवं आश्वासन देता/देती हूँ कि.....

(क) मेरी संतान ऐसे किसी व्यवहार अथवा कृत्य में संलिप्त नहीं होगी जिसे विनियमों की धारा 3 के अंतर्गत रैगिंग माना गया है।

(ख) मेरी संतान जान बूझकर अथवा भूलचूक से ऐसे किसी कृत्य में न तो संलिप्त होगी अथवा न ही उसमें सहायक होगी ना ही उसे प्रोत्साहित करेगी जिसे इन विनियमों की धारा 3 के अंतर्गत रैगिंग के रूप में माना गया है।

5. एतद्द्वारा मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि यदि मेरी संतान रैगिंग की दोषी पाई जाती/पाया जाता है तो वह इन विनियमों की धारा 9.1 के अनुसार दण्ड की भागीदार होगा/होगी जो कि किसी भी अन्य आपराधिक कृत्य के पूर्वाग्रह के बिना होगा–तथा जो दण्ड मेरी संतान के विरूद्ध किसी भी दण्ड संबंधी कानून के अथवा वर्तमान में लागू किसी भी अन्य कानून के अनुसार होगा।

6. एतद्द्वारा मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि यदि मेरी संतान इस देश में विद्यमान किसी भी संस्थान द्वारा रैगिंग की दोषी अथवा उसमें सहायक होने कि अथवा षडयन्त्र का एक हिस्से के रूप से दोषी होने के कारण अथवा उसे प्रोत्साहित करने के दोष के कारण निष्कासित नहीं हुई है/हुआ है तथा मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है, तो मेरी संतान को दिया गया प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

घोषित किया गया ..... दिन ..... माह ..... वर्ष .....

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नामः

पताः

दूरभाष सं./मो. नं.:

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि यह वचनबद्धता मेरे संज्ञान में सर्वांगीण रूप से सत्य है तथा इसका कोई भी अंश असत्य नहीं है तथा इसमें कथित कोई भी बात ना तो छिपाई गई है और ना ही अयर्थाथ कही गई है।

सत्यापित (स्थान) ..... दिन ..... माह ..... वर्ष .....

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नामः

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th December, 2013

No. F. 15-3/2013 (ARC) Pt. III.—In exercise of powers conferred under clause (g) of sub-section (1) of section 26 of the University Grants Commission Act 1956 (3 of 1956), the University Grants Commission hereby makes the following regulations, namely:-

(1) These regulations may be called the "curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions (second Amendment) Regulations, 2013".

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter referred to as the Principal regulations), in the Annexure-I and II of the regulations, the sentences containing the following shall be deleted:

"Solemnly affirmed and signed in my presence on this (day)of (month), (year) after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER"

UPAMANYU BASU, Secy.

[ADVT. III/4/Exty./113/13]

Foot Note: The principal Regulations were published in the Gazette of India, vide notification number 27 dated 04.07.2009.

ANNEXURE-I

UNDERTAKING BY THE STUDENT

I, (full name of student with admission/registration/enrolment number) s/o d/o Mr./Mrs./Ms. , having been admitted to (name of the institution) , have received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter called the "Regulations") carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.

(2) I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.

(3) I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.

(4) I hereby solemnly aver and undertake that

(a) I will not indulge in any behaviour or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

(b) I will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

(5) I hereby affirm that, if found guilty of ragging, I am liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law or any law for the time being in force.

(6) I hereby declare that I have not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, I am aware that my admission is liable to be cancelled.

Declared this_____day of_____ month of_____ year.

_____

Signature of deponent
Name:

VERIFICATION

Verified that the contents of this undertaking are true to the best of my knowledge and no part of the undertaking is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at (place) on this the (day) of (month), (year).

_____

Signature of deponent
Name:

ANNEXURE-II

UNDERTAKING BY PARENT/GUARDIAN

I, Mr./Mrs./Ms. _____(full name of parent/guardian) father/mother/guardian of, (full name of student with admission / registration/enrolment number)_____, having been admitted to____ (name of the Institution)_____, have received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter called the "Regulations"), carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations."

(2) I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.

(3) I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against my ward in case he/she is found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.

(4) I hereby solemnly aver and undertake that

(a) My ward will not indulge in any behaviour or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
(b) My ward will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

(5) I hereby affirm that, if found guilty of ragging, my ward is liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against my ward under any penal law or any law for the time being in force.

(6) I hereby declare that my ward has not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, the admission of my ward is liable to be cancelled.

Declared this_____day of_____ month of_____ year.

Signature of deponent
Name:
Address:
Telephone/Mobile No.:

VERIFICATION

Verified that the contents of this undertaking are true to the best of my knowledge and no part of the undertaking is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at (Place) on this the (day) of (month) ,(year) .

Signature of deponent
Name:

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Step by Step Guide On

How to Fill An Online Anti Ragging Undertaking on https://antiragging.in

Click here to enter the form.

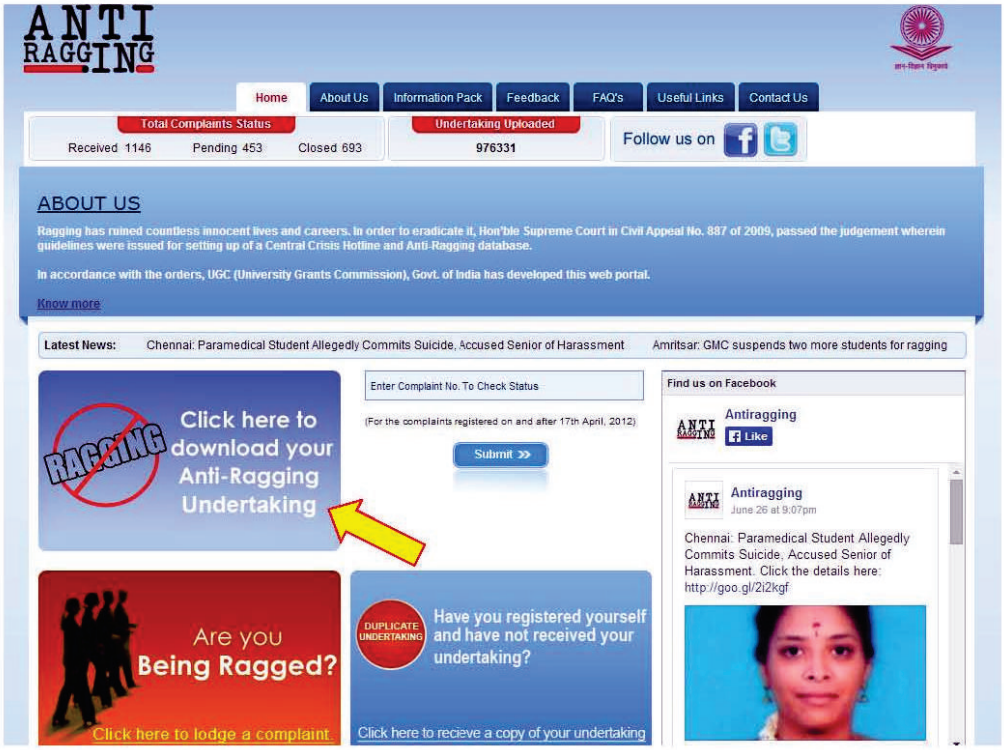

Click on Next button.

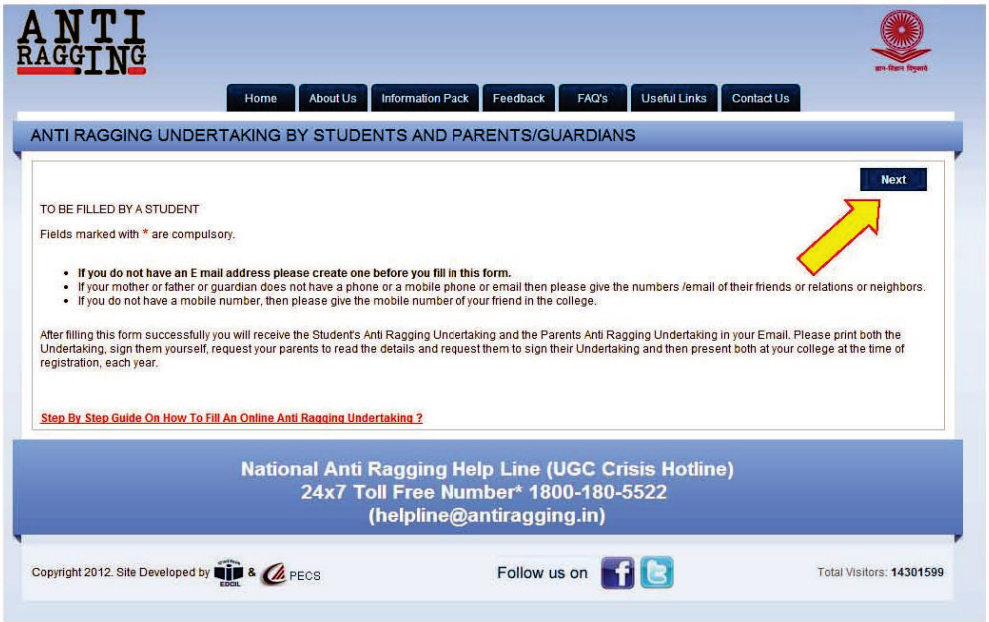

Fill the Personal details here:

Fill the Parent or Guardian details here:

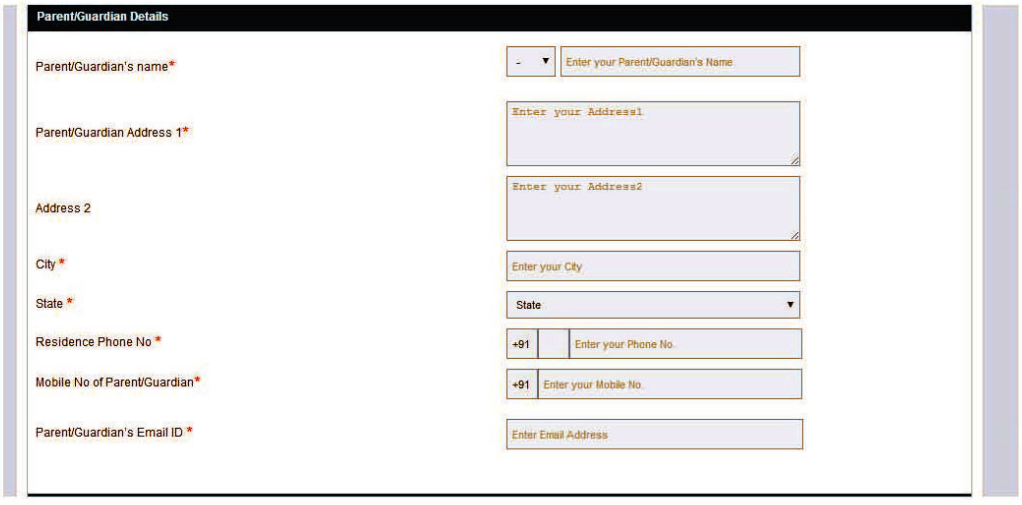

Fill the College details here:

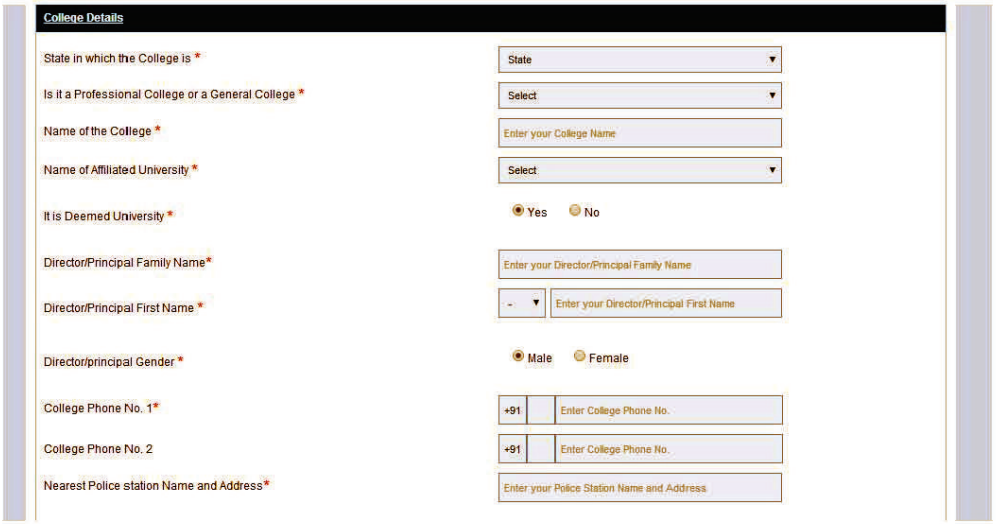

Fill the Course details here:

After filled all required fields, you need to click on Next button.

Note: - In the "Year of Study" you have six options:-

- If you select 1, then you don't need to fill the Confidential Survey.
- If you select 2,3,4,5 or Other you will have to fill the Confidential Survey.

You need to check all the checkboxes then click on Submit Button.

Thereafter, you need to click on Submit button.

This pop-up confirms that you have on line registered successfully and you have to fill the Confidential Survey also. Click on OK button, this will redirect on Confidential Survey form.

This is Confidential Survey. Please select one option for each question.

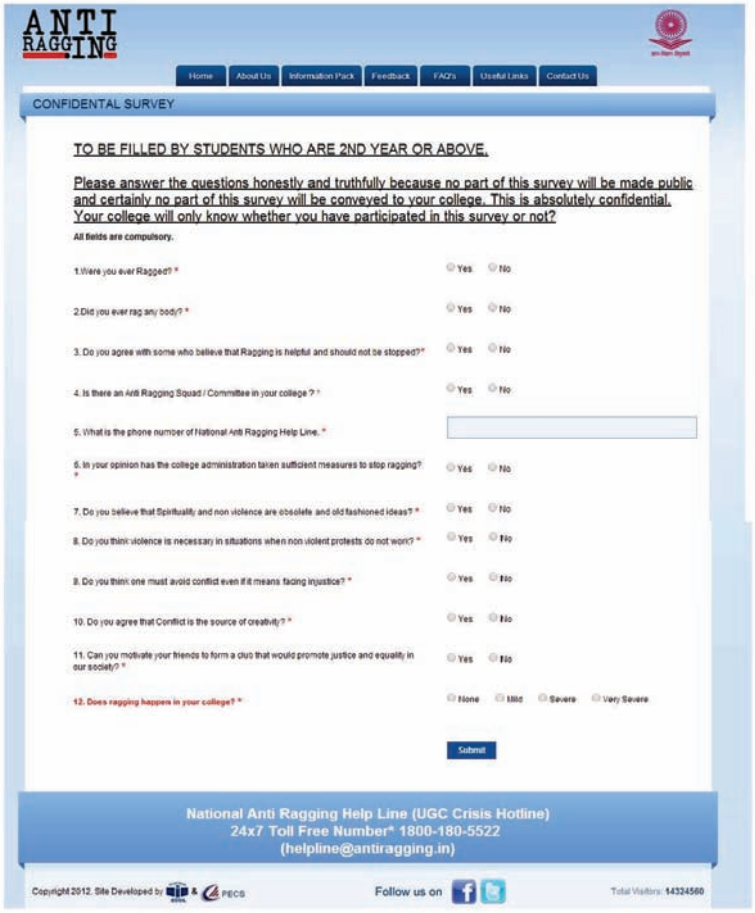

This pop-up confirms that you have successfully submitted the form. Click ok button this will return the homepage of Anti-Ragging web portal (https://antiragging.in)

NOTIFICATION

MAHARASHTRA PROHIBITION of RAGGING ACT, 1999

THE RULES OF PROHIBITING RAGGING

HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT
Mantralaya Annex, Mumbai 400 032, dated the 19th May 1999
NOTIFICATION

MAHARASHTRA PROHIBITION OF RAGGING ACT, 1999.

section {2} of section 1 of the Maharashtra Prohibition of Ragging act, 1999 {Man. XXXIII of 1999), the Government of Maharashtra hereby appoints the 1 day of June 1999 to be the date on which the said Act shall come into force.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

V.P. Raja,
Secretary to Government

In pursuance of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the following translation in English of the Maharashtra Prohibition of Ragging Act, 1999 (Mah, XXXIII of 1999), is hereby published under the authority of the Governor.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

PRATIMAUMARJI,
Secretary to Government,
Law and Judiciary Department.

MAHARAHSTRA ACT NO. No. XXXIII OF 1999.
(First published, after having received the assent of the Governor in the "Maharashtra Government Gazette", on the 15 May 1999.)

An Act to prohibit ragging in educational institutions in the State of Maharashtra

WHEREAS it is expedient to-enact a special law to prohibit ragging in educational institutions in the State of Maharashtra. It is hereby enacted in the Fiftieth Year ofthe Republic of India as follows:

(1) Short title and commencement

- This Act may be called the Maharashtra Prohibition of Ragging Act, 1999.
- It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2) Definitons

1. "educational institution" means and includes a college, or other institution by whatever name called, carrying on the activity or imparting education therein (either exclusively or among other activities); and includes an orphanage or a boarding home or hostel or a tutorial institution or any other premises attached thereto;
2. "head of the educational institution" means the Vice-Chancellor of the University, dean of Medical Faculty, Director of the Institution or the Principal, headmaster or the person responsible for the management of the educational institution;
3. "ragging" means display of disorderly conduct, doing of any act which causes or is likely to cause physical psychological harm or raise apprehension or fear or shame or embarrassment to a student in any educational institution and includes
   (i) teasing, abusing, threatening or playing practical jokes on, or causing hurt to, such student; or
   (ii) asking a student to do any act or perform something which such student will not, in the ordinary course, willingly, do.

3) Prohibition of ragging
Ragging within or outside of any educational institution is prohibited.

(4) Penalty for ragging
Whoever directly or indirectly commits, participates in, abets or propagates ragging within or outside any education institution shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to two years and shall also be liable to a fine which may extend to ten thousand rupees.

(5) Dismissal of student(5) Dismissal of student
Any student convicted of an offence under section 4 shall be dismissed from the educational institution and such student shall not be admitted in any other educational institution for a period of five years from the date of order of such dismissal.

(6) Suspension of student

1. Whenever any student or, as the case may be, the parent or guardian, or a teacher of an educational institution complains, in writing, of ragging to the head of the educational institution, the head of that educational institution shall, without prejudice to the foregoing provisions, within seven days of the receipt of the complaint, enquire into the matter mentioned in the complaint and if; prima facie, it is found true, suspend the student who is accused of the offence, and shall, immediately forward the complaint to the police station having jurisdiction over the area in which the educational institution is situated, for flirter action.
2. Where, on enquiry by the head of the educational institution, it is proved that there is no substance, prima facie, in the complaint received under sub-section (1), he shall intimate the fact, in writing, to the complainant.
3. The decision of the head of the educational institution that the student has indulged in ragging under sub-section (1), shall be final

(7) Deemed abetment
If the head of the educational institution fails or neglects to take action in the manner specified in section 6 when a complaint of ragging is made, such person shall be deemed to have abetted the offence of ragging arid shall, on conviction, be punished as provided for in section 4. Power to make rules

(8) (1) The State Government may, by notification in the Official G, zette, amend for carrying out all or any of the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, before each House of the State Legislature, while it is in session for total period of thirty days, which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, arid if; before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, both houses agree in making any modification in the rules or both Houses agree that the rule should not be made, and notif- such decision in the Official Gazette, the rule shall from the date of publication of such notification, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done or omitted to be done under that rule.

IMPORTANT CIRCULARS

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
Bahadurshah Zafar Marg
New Delhi-110002

No. F. 1-127/2011 (Anti Ragging)

PUBLIC NOTICE

CURBING THE MENACE OF RAGGING IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

It is brought to the notice of the Institutions, students and other various stakeholders that ragging is a criminal offence and UGC has framed regulations, on curbing the menace of ragging in higher educational institution, in order to prohibit, prevent and eliminate the scourge of ragging. The regulations have been notified vide No. F. 1-16/2009 (CPP-II) dated 21.10.2009 and are available on UGC website www.ugc.ac.in.

The above mentioned regulations are mandatory and shall apply to all Universities established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State/Union Territory Act and all Institutions recognized by or affiliated to such Universities and all Institutions deemed to be Universities under Section (3) of the UGC Act, 1956 with effect from 4th July, 2009 i.e. the date of its Publication in the official Gazette. **All institutions are required to take necessary steps for its implementation in toto including the monitoring mechanism as per provisions provided in the above regulation and ensure its strict compliance.** The following preventive measures for Anti-Ragging should also be strictly followed:-

1) The Institutions may erect suitable hoardings/bill boards/banners in prominent places within the campus to exhort the students to prevent or not to indulge in ragging and also indicating therein the names of the officials and their telephone numbers to be contacted in case of ragging.
2) All Educational Institutions should form an Anti-Ragging-Committee and squads and dedicated cadre of wardens and professional counselors to ensure that the directions of Hon'ble Supreme Court of India and Justice Raghavan Committee recommendations are followed without exception.

3) An affidavit must be obtained from every Student, Parent/Guardian separately as per clause (m & n) of Regulation 6.2.
4) The Institution may also undertake other forms of campaign as it may consider appropriate for prevention of ragging.
5) UGC has uploaded a film on anti-ragging on its website. All universities and colleges are requested to download the same and give wide publicity amongst the students, before the start of the academic session. Besides, this may be constantly monitored during the entire period of the academic session.

Any violation of UGC regulations as cited above or if any Institution fails to take adequate steps to prevent ragging or act in accordance with these regulations or fails to punish perpetrators of incidents of ragging suitably, UGC shall call for punitive action against erring institutions.

Students in distress owing to ragging related incidents can access the toll free helpline 1800-180-5522

SECRETARY

PUBLIC NOTICE

CURBING THE MENACE OF RAGGING IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

It is brought to the notice of the Public that ragging is a criminal offence and that UGC has framed UGC Regulations on curbing the menace of ragging in Higher Educational Institutions, 2009, in order to prohibit, prevent and eliminate the scourge of ragging in Indian Universities/Colleges/Institutions.

The above regulations are mandatory and all Intuitions should take necessary steps for its implementation under intimation to the UGC.

Students in distress owing to ragging related incidents can access the Toll Free Helpline 1800-180-5522 or contact Ed. CIL (India) Limited, Ed. CIL House, 18A, Sector-16A, Noida-201 301, UP.

Sd/-
Secretary
University Grants Commission
New Delhi

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
BAHADURSHAH ZAFAR MARG
NEW DELHI

No. F. 1-21/2009 (Anti Ragging) March, 2012

NOTICE

In pursuance to the Judgment of the Hon'ble Supreme Court of India dated 08.05.2009 in Civil Appeal No. 887/2009, the University Grants Commission has framed "UGC Regulations on curbing the menace of ragging in higher educational institutions, 2009" which have been notified on 4th July, 2009 in the Gazette of India. These regulations are mandatory for all Universities/Institutions. The UGC has made it mandatory for all students/parents to submit anti ragging related affidavits to the institutions at the time of admission. **Now it is brought to the notice of all Universities, Institutions, Students and Parents that these affidavits can be downloaded from the web site of UGC and or related other web sites.**

JS (ARC)

23236351, 23232701, 23237721, 23234116

UGC Website : www.ugc.ac.in

ज्ञान–विज्ञान विमुक्तये

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह जफर मार्ग
नई दिल्ली–110002
University Grants Commission
Bahadurshah Zafar Marg
New Delhi-110002

No. F. 15-3/2012 (ARC) pt.III

May, 2013

Mr. S. K. Shah
Asstt. Controller
Government of India
Department of Publication
Ministry of Urban Development
Civil Lines,
Delhi-110 054

28 MAY 2013

Subject: Request for publication of 2nd amendments in UGC regulations on curbing the menace of ragging in higher educational institutions-regarding.

Sir,

Please find enclosed two copies each of the notification (English & Hindi version) of the 2nd amendments in UGC regulations on curbing the menace of ragging in higher educational institutions.

You are requested, to kindly publish it in the Gazette of India and send a copy of the notification after publication to the UGC. The cost involved in the publication would be borne by the UGC for which pre-receipted bill may be sent to the Commission with the detail of e-payment.

Yours faithfully,

(Madhu Bala Khanna)
Under Secretary

Encl: As above
Copy to:

1. Prof. Raj Kachroo, Aman Movement for Eradication of Ragging, 689, Sector 23, Gurgaon, Haryana.
2. Sh. Sahdev Singh, Under Secretary, Ministry of Human Resource Development (Deptt. of Higher Education) New Delhi-110 001.

MBKhanna

(Madhu Bala Khanna)
Under Secretary

To be published in the Gazette of India Part- III

University Grants Commission

Notification

May, 2013

In exercise of powers conferred under clause (g) of sub- section (i) of section 26 of the University Grants Commission Act 1956 (3 of 1956), the University Grants Commission here by makes the following regulations, namely:-

(1) These regulations may be called the "Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions (second Amendment) Regulations, 2013."

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter referred to as the Principal regulations), in the Annexure- I and II of the regulations, the sentences containing the following shall be deleted:

"Solemnly affirmed and signed in my presence on this (day) of (month), (year) after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER"

Foot Note: The principal Regulations were published in the Gazette of India, vide notification number 27 dated 04.07.2009.

(Dr. Akhilesh Gupta)
Secretary

भारत के राजपत्र में प्रकाशन हेतु खण्ड–III

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

मई, 2013

यूजीसी अधिनियम, 1956 (3:1956) के अनुभाग 26 के उप–अनुच्छेद (आई) की धारा (जी) के अनुसार प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निम्न विनियम सृजित करता है:

(1) ये विनियम "उच्च शैक्षिक संस्थानों में रैगिंग के जोखिम का निराकरण–(द्वितीय संशोधन) विनियम 2013" कहलायेंगे।

(2) सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से इन्हें लागू माना जाएगा।

2. उच्च शैक्षिक संस्थानों में रैगिंग के जोखिम का निराकरण, 2009 के यूजीसी विनियम (इसके आगे मुख्य विनियम के रूप में जाने जायेंगे) के अनुलग्नक–I एवं II के वाक्य जिनमें निम्न सम्मिलित हैं– उनका विलोपन किया जायेगा।

मैं, इस पत्र की सामग्री को पूरी तरह पढ़ लेने के पश्चात निष्ठापूर्वक पुष्टि करता हूँ कि मेरी उपस्थिति में इस..... (दिवस)..... (माह)..... (वर्ष) को हस्ताक्षरित किया गया है।

शपथ आयुक्त

पाद टिप्पणी: ये मुख्य विनियम, भारत के राजपत्र में दिनाँक 04.07.2009 की अधिसूचना सं. 27 को प्रकाशित किये गए।

अखिलेश गुप्ता

(डॉ0 अखिलेश गुप्ता)
सचिव

मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे रॅगिंग प्रतिबंध करण्यासंदर्भात दिलेल्या निर्णयाची अमंलबजावणी करण्याबाबत

महाराष्ट्र शासन

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग

शासन परिपत्रक क्र. याचिका २०१०प्र/.क्र.३२८/विशि-३

मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०००३२.

दिनांक: ०४ जून, २०१५.

<u>वाचा:-</u> १.केरळ विद्यापीठ विरूध्द कौन्सिल,प्रिन्सिपॉल्स,कॉलेजेस,केरळा ॲन्ड इतर या स्पेशल लिव्ह अपिल (Civil) क्रमांक २४२९५/२००४ मध्ये मा.सर्वोच्च न्यालयाने दिलेले दिनांक १६ मे २००७ चे अंतरिम आदेश

२.रॅगिंग प्रतिबंध संदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दि.१८ मे २००७ रोजी दिलेले निर्देश

३.शासन परिपत्रक क्रं. संकिर्ण -२००५/(२३८/०५)/विशि-१, दि.१८.०७.२००७

४.मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे सी.ए.क्रंमांक ८८७/२००९ मधील आदेश दि.२२.०६.२००९

५.मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे जनहित याचिका क्रं.१७२/२०१० मधील आदेश दि.२७.०२.२०१५

परिपत्रक-:

शालेय स्तरावरून महाविद्यालयात प्रवेश घेणा-या नवीन विद्यार्थ्यांचे , विशेषत: अन्य गावातून आलेल्या विद्यार्थ्यांचे त्यांचेपेक्षा वरील वर्गातील विद्यार्थ्याकडून होत असलेल्या रॅगिंगमुळे मानसिक स्वास्थ खराब होण्याच्या वारंवार घटना घडतात. अशा घटनांमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान तर होतेच परंतु आत्महत्येसारख्या घटनाही घडू शकतात.

वरील बाबींचा सर्वकष विचार करून मा.सर्वोच्च न्यायालयाने संदर्भ क्रं.२ अन्वये दिलेल्या सूचनांची कडक अमंलबजावणी करण्याबाबत शासन परिपत्रक क्रं. संकिर्ण -२००५/(२३८/०५)/विशि-१, दि.१८.०७.२००७ अन्वये सर्व संबंधित विभाग, संचालक, सहसंचालक, सर्व विद्यापीठाचे कुलगुरू,कुलसचिव,शालेय शिक्षण विभाग,वैद्यकीय शिक्षण विभाग,कृषी शिक्षण विभाग यांना सूचना देण्यात आल्या होत्या.

या परिपत्रकाव्दारे सर्व संबंधितांना कळविण्यात येते की, रॅगिंग प्रतिबंधाची योग्य अमंलबजावणी होण्याच्या दृष्टीकोनातून खालील सूचनांची काटेकोरपणे अमंलबजावणी करावी.

१. रॅगिंग सारख्या गुन्ह्याची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून देण्यात येणारी शिक्षा कडक असावी, जेणे करून इतरांना दहशत बसेल.

२. रॅगिंगच्या प्रत्येक घटनेमध्ये संस्था स्तरावर करण्यात आलेली कार्यवाई जर संबंधित विद्यार्थ्याला (Victim) किंवा संस्थेच्या प्रमुखाला समाधानकारक वाटत नसेल तर

कोणताही अपवाद न करता संस्थेच्या प्रधिका-यांनी स्थानिक पोलिसांकडे F.I.R. दाखल करावा.बळी पडलेल्या विद्यार्थ्याच्या पालकांना पोलिसांमध्ये परस्पर F.I.R. दाखल करावायाचा असला तरीही संस्थेच्या प्राधिका-यांनी F.I.R. दाखल करणे आवश्यक राहील.

३. शैक्षणिक संस्थेकडून प्रवेशासाठी छापलेल्या पुस्तिकेमध्ये (Prospectus) असे स्पष्टपणे नमूद करावे की, प्रवेशासाठी येणारा विद्यार्थी यापूर्वी रॅगिंग करण्यामध्ये गुंतलेला असेल तर त्याला प्रवेश नाकारण्यात येईल वा प्रवेश दिल्यानंतरही असे निदर्शनास आले की, सदर विद्यार्थी रॅगिंग करण्यामध्ये गुंतलेला होता तर त्याला निष्काशित करण्यात येईल.

४. संबंधित संस्थेचे प्रधिकारी आणि कार्यकर्ते यांची रॅगिंगला प्रतिबंध करण्याची सामुदायिक जबाबदारी राहील. शैक्षणिक संस्थेने रॅगिंगला प्रतिबंध करण्याची परिणामकारक उपाययोजना केली किंवा नाही याची शासनाला तपासणी करता येईल आणि जर यामध्ये त्यांना योग्य ती कार्यवाही केली नसेल तर शासनाकडून अनुदान नाकारण्यासारखी कारवाई केली जावू शकेल.

५. शैक्षणिक संस्थांनी रॅगिंगला प्रतिबंध समित्या आणि पथके तातडीने स्थापन करतील.मा.सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने अमंलबजावणी केली आहे की नाही, हे पाहण्याचे काम सदर समित्या आणि पथकाचे राहील. मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदेशाप्रमाणे शिफारशीची अमंलबजावणी होत नसेल तर समित्यांनी ही बाब मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्दशनास आणण्यात यावी .

६. महाविद्यालय/ शैक्षणिक संस्थेत/वसतिगृह प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्राचार्य/गृहप्रमुख/संचालक हे नव्या व जुन्या विद्यार्थ्याची सभा घेऊन रॅगिंगला प्रतिबंधाबाबत दिशा निर्देश द्यावेत व कडक शिक्षेबाबत पुर्व कल्पना विद्यार्थ्याना द्यावी.

७. वसतिगृहात नव्या व जुन्या विद्यार्थ्याची राहण्याची व्यवस्था वेगवेगळया इमारतीत असावी. तसे शक्य नसल्यास, वसतिगृह प्रमुखाने रॅगिंगला प्रतिबंधाबाबत विशेष दक्षता घ्यावी.

८. रॅगिंग तक्रार रजिस्टर प्रत्येक महाविद्यालय/ संस्था/वसतिगृहात ठेवण्यात यावे.

९. महाविद्यालय/ संस्था/वसतिगृहा मध्ये रॅगिंगला प्रतिबंधत्मक माहिती देणारा फलक असावा. ज्यामध्ये शिक्षेचे स्वरूप, होऊ शकणारी कडक कारवाई, अँटी रॅगिंग समितीच्या पदाधिका-यांची नावे भ्रमणध्वनी क्रमांक नमूद आसावा.

तरी सर्व संबंधिताना कळविण्यात येते की, मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची तातडीने अमंलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने सदर परिपत्रक व मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्था यांच्या निदर्शनास आणावे.

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०६०५१११११५७७०८ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

Siddharth Rambhau Kharat

Digitally signed by Siddharth Rambhau Kharat
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Deputy Secretary, postalCode=400032, st=Maharashtra, cn=Siddharth Rambhau Kharat
Date: 2015.06.08 14:49:16 +05'30'

(सिध्दार्थ खरात)

उपसचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रति,

१. संचालक (उच्च शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य पुणे.
२. सर्व विभागीय सहसंचालक(उच्च शिक्षण).
३. कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठ.
४. गृहविभाग, मंत्रालय,मुंबई
५. शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय,मुंबई
६. संचालक, (तंत्र शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई
७. सर्व शासकीय तंत्र शिक्षण महाविद्यालये व संस्था संचालक,तंत्र शिक्षण महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांचे मार्फत)
८. सर्व विभागीय सहसंचालक तंत्र शिक्षण
९. वैद्यकीय शिक्षण विभाग, मंत्रालय,मुंबई
१०. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण अणि संशोधन महाराष्ट्र राज्य,मुंबई-०९
११. कृषि व प.दु.म. विभाग, मंत्रालय,मुंबई
१२. निवड नस्ती (विशि-१)

मा.सर्वोच्च न्यायालयाने रॅगिंग प्रतिबंध करण्यासंदर्भात दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याबाबत...

महाराष्ट्र शासन
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग
परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण २००५/(२३८/०५)/विशि-१
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२.
दिनांक : १८ जुलै, २००७

परिपत्रक :

केरळा विद्यापीठ विरुध्द कौन्सिल, प्रिन्सिपॉल्स, कॉलेजेस, केरळा ॲन्ड इतर या स्पेशल लिव्ह ॲपिल (Civil) क्रमांक २४२९५/२००४ मध्ये मा.सर्वोच्च न्यायालाने दिनांक १६ मे, २००७ रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशाच्या अनुषंगाने, शैक्षणिक संस्थांमधुन रॅगिंग होऊ नये म्हणुन काही तातडीच्या उपाययोजना कराव्याच्या आहेत.

२. रॅगिंग प्रतिबंध संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक २७ नोव्हेंबर, २००६ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार केंद्र शासनाच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने डॉ.आर.के.राघवन, माजी संचालक, सी.बी.आय. यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत केली होती. सदर समितीने दिनांक ७ मे, २००७ रोजी आपला अहवाल मा. सर्वोच्च न्यायालयास सादर केला. सदर विचारात घेऊन मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक १८ मे, २००७ रोजी विविध प्राधिकरणांना निदेश दिले. मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशाची प्रत सोबत जोडली आहे. मा.सर्वोच्च न्यायालयाने समितीच्या अहवालातील खालील शिफारशींची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निदेश दिलेले आहेत.

१) रॅगिंग सारख्या गुन्ह्याची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणुन देण्यात येणारी शिक्षा ही कडक असावी, जेणे करुन इतरांना वेसण बसेल.

२) रॅगिंगच्या प्रत्येक घटनेमध्ये संस्था स्तरावर करण्यात आलेली कारवाई जर संबंधीत विद्यार्थ्याला (Victim) किंवा त्याच्या पालकाला किंवा संस्थेच्या प्रमुखाला समाधानकारक वाटत नसेल तर कोणताही अपवाद न करता संस्थेच्या प्राधिका-यांनी स्थानिक पोलिसांकडे F.I.R. दाखल करावा. बळी पडलेल्या विद्यार्थ्याच्या पालकांना पोलिसांमध्ये परस्पर F.I.R. दाखल करावयाचा असला, तरीही संस्थेच्या प्राधिका-यांनी F.I.R. दाखल करणे आवश्यक राहील.

३) शैक्षणिक संस्थेकडुन प्रवेशासाठी छापलेल्या पुस्तिकेमध्ये (Prospectus) असे स्पष्टपणे नमूद करावे की, प्रवेशासाठी येणारा विद्यार्थी यापुढे रॅगिंग करण्यामध्ये गुंतलेला असेल तर त्याला प्रवेश नाकारण्यात येईल किंवा प्रवेश दिल्यानंतरही असे निदर्शनास आले की, सदर विद्यार्थी रॅगिंग करण्यामध्ये गुंतलेला होता तर त्याला निष्कासित करण्यात येईल.

४) संबंधीत संस्थेचे प्राधिकारी आणि कार्यकर्ते यांची रॅगिंगला प्रतिबंध करण्याची सामुदायिक जबाबदारी राहील. शैक्षणिक संस्थेने रॅगिंगला प्रतिबंध करण्यासाठी परिणामकारक उपाययोजना केली किंवा नाही याची शासनाला तपासणी करता येईल आणि जर यामध्ये त्यांनी योग्य ती कार्यवाही केली नसेल तर राज्य शासनाकडून अनुदान नाकारण्यासारखी कारवाई केली जावू शकेल.

५) शैक्षणिक संस्थांनी रॅगिंग प्रतिबंध समित्या आणि पथके तातडीने स्थापन करावीत. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने अंमलबजावणी करण्यासाठी निर्देश दिलेल्या वरील शिफारशींची अंमलबजावणी केली आहे की नाही, हे पाहण्याचे काम सदर समित्या आणि पथकाचे राहील. मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे शिफारशींची अंमलबजावणी होत नसेल तर समित्यांनी ही बाब मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात यावी.

३. तरी सर्व संबंधीतांना कळविण्यात येते की, मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने सदर परिपत्रक व मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्व महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्था यांच्या निदर्शनास आणावे.

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेताक क्र.२००७०७१८१७३००५००१ असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(ज.म.अंबादे)
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

प्रति,

१) शिक्षण संचालक (उच्च शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे
२) सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण
३) सर्व विद्यापीठाचे कुलसचिव,
४) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई
५) शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय , मुंबई
६) शिक्षण संचालक,महाराष्ट्र राज्य, पुणे
७) वैद्यकिय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई
८) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
९) कृषी व प.दु.म. विभाग, मंत्रालय,मुंबई
१०) निवड नस्ती, (विशि-१)

लक्षवेधी - डॉ. व्ही. आर.
गायकवाड, पुणे - १

शैक्षणिक संस्थांमध्ये रॅगिंगच्या घटना घडू नयेत यासाठी महाविद्यालयातर्फे विद्यार्थ्यांसाठी समुपदेशाचे कार्यक्रम आयोजित करणेबाबत-----

महाराष्ट्र शासन
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,
शासन परिपत्रक, क्रमांक: विसाआ१००४/ (३९/०४)/ मशि-५,
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२,
दिनांक: ६ ऑक्टोबर, २००४.

शासन परिपत्रक :- सन २००३च्या हिवाळी अधिवेशनात श्री. शिवराम दळवी, विधान सभा सदस्य व इतर यांनी पुण्यातील आय.एल.एस. विधी महाविद्यालयात घडलेल्या रॅगिंगच्या घटना या विषयी तारांकीत प्रश्न प्रस्तावित केला होता. या तारांकीत प्रश्नाच्या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेच्या वेळी मा. मंत्री उच्च शिक्षण यांनी भविष्यामध्ये अशा घटना घडू नयेत यासाठी महाविद्यालयातर्फे विद्यार्थ्यांसाठी समुपदेशाचे कार्यक्रम आयोजित केले जातील, असे आश्वासन दिले आहे.

२. राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठे व शैक्षणिक संस्थांमध्ये रॅगिंगच्या प्रकारांना प्रतिबंध करण्याच्या दृष्टीने शासनाने महाराष्ट्र रॅगिंग प्रतिबंध अधिनियम १९९९ लागू केला आहे. तथापि, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना या अधिनियमाची पुरेशी माहिती किंवा त्या विषयीच्या परिणामांचे गांभिर्य नसल्यामुळे अजूनही रॅगिंगच्या घटना घडत असल्याचे वारंवार निदर्शनास येत आहे. परिणामी विधीमंडळाच्या सभागृहांमध्ये या संदर्भात वेळोवेळी चर्चा उपस्थित होत असतात. त्यामुळे भविष्यात रॅगिंगच्या घटना घडू नयेत व्यापक स्वरुपात जाणिवपूर्वक प्रयत्न करणे अत्यंत गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमिवर राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयांनी महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना सदर अधिनियमाची माहिती व परिणामांचे गांभिर्य लक्षात आणून देण्यासाठी समुपदेशाचे व्यापक कार्यक्रम आयोजित करुन विद्यार्थ्यांमध्ये रॅगिंगचे प्रकार प्रतिबंधित करण्याच्या दृष्टीने विस्तृत स्वरुपात जागृती करावी.

३. या विषयी सर्व संबंधितांकडून अपेक्षित कार्यवाही होईल याबाबत संचालक (उच्च शिक्षण) तथा सर्व विभागीय सहसंचालक (उच्च शिक्षण) यांनी योग्य ती दक्षता घ्यावी.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,

(सही)
(सं. अ. घोरपडे)
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन.

प्रत,

(१) शिक्षण संचालक (उच्च शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
(२) सर्व विभागीय सहसंचालक (उच्च शिक्षण),
(३) शिक्षण संचालक (तंत्र शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई,
(४) शिक्षण संचालक (वैद्यकीय शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई,
(५) संचालक, कला, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई,
(६) संचालक, ग्रंथालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
(७) कुलसचिव, सर्व अकृषी / वैद्यकीय विद्यापीठे,
(८) प्राचार्य / संचालक सर्व संलग्नित महाविद्यालये व शैक्षणिक संस्था, (द्वारा संबंधित विद्यापीठे),
(९) सर्व उपसचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,
(१०) सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
(११) निवड नस्ती मशि-५, विशि-२, समन्वय.

Savitribai Phule Pune University

Monitoring Cell on Ragging

Name	Designation	Address	Phone No.
The Registrar, Savitribai Phule Pune University	Chairman	Savitribai Phule Pune University	020-25601183
The Head of Departement (University Campus)	Member	HOD Dep. of Botany Savitribai Phule Pune University	020-25601438
The Head of Departement (University Campus)	Member	HOD Dep. of Physics Savitribai Phule Pune University	020-25601408
The Principal	Member	ABMSP Shri Shahu Mandir Mahavidyalaya Arts and Commerce, Near Parvati Ramana, Pune - 411 009.	020-24221424
The Principal	Member	Progressive Education Society's Modern College of Arts, Science and Commerce College, Ganeshkhind, Pune - 411 016.	020-25637967
The Chief Hostel Rector, University Campus Hostel	Member	Savitribai Phule Pune University	020-25601338
The Asst. Rector, University Ladies Hostel	Member	Savitribai Phule Pune University	020-25601325
The Programme Coordinator, N.S.S.	Member	Savitribai Phule Pune University	020-25601153
The Director, Board of Sports	Member	Savitribai Phule Pune University	020-25601142
The Dy. Registrar, Admission Section	Member	Savitribai Phule Pune University	020-25601260
The Director, Board of Students' Welfare	Member - Secretary	Savitribai Phule Pune University	020-25601160

FOR ANY DETAILS OR COMPLAINTS REGARDING RAGGING

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION **24 X 7 ANTI RAGGING HELPLINE**	**SAVITRIBAI PHULE PUNE UNIVERSITY**
Toll Free No. : 1800 - 180 - 5522 **E-mail :helpline@antiragging.in**	The Director, Board of Students' Welfare Savitribai Phule Pune University Ganeshkihind, Pune – 411 007. Office Phone No. :- 020-25601154 / 1160 Email: - bsw@unipune.ac.in

SAVITRIBAI PHULE PUNE UNIVERSITY
BOARD OF STUDENTS' WELFARE
Ganeshkhind, Pune 411 007

Join Hands to Make Your Campus RAGGING Free

National Anti-Ragging Helpline
24x7 Toll Free Number* 1800-180-5522
Email-helpline@antiragging.in
https://antiragging.in

FOR ANTI RAGGING Undertaking BY STUDENTS AND PARENTS/GUARDIANS - https://antiragging.in

For Any Details/Complaints :

Savitribai Phule Pune University
Anti-Ragging Monitoring Cell
Contact : 020-25601160, 25601154
Email : bsw@unipune.ac.in

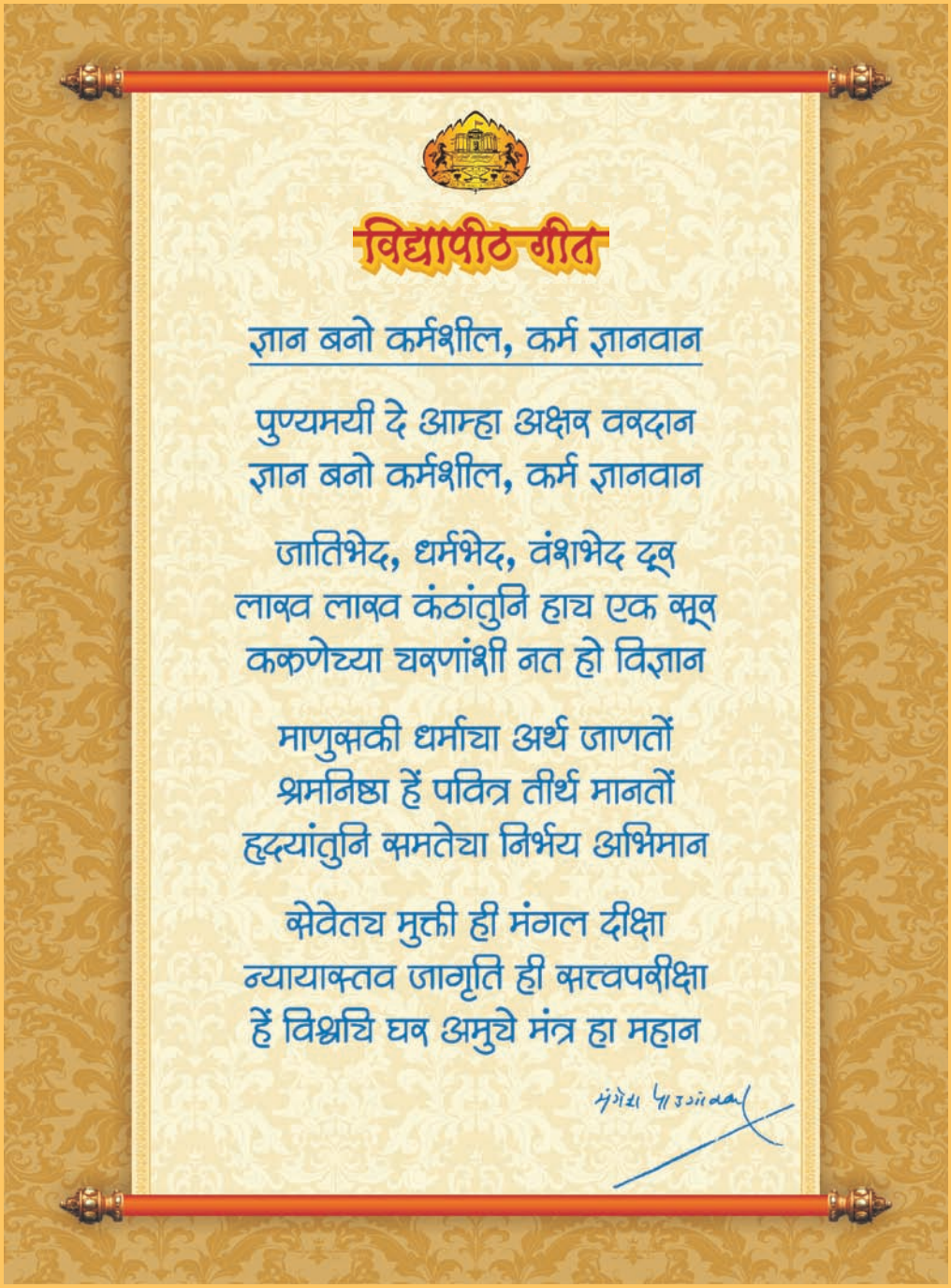

Published by:
Dr. Sanjaykumar Dalvi
Director,
Board of Students' Welfare
Savitribai Phule Pune University
(Formerly Universtiy of Pune)
Ganeshkhind,
Pune - 411007.

Printed at:
Savitribai Phule Pune University Press
Savitribai Phule Pune University
(Formerly Universtiy of Pune)
Ganeshkhind,
Pune - 411007.

KHADKI EDUCATION SOCIETY'S

Tikaram Jagannath

Arts, Commerce & Science College

Principal

Dr. Sanjay Chakane

M.Sc., M.B.A., Ph.D.

POLICY DOCUMENT ON GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM FOR EMPLOYEES AND STUDENTS

Tikaram Jagannath Arts, Commerce & Sc. College, Khadki is committed to providing a safe environment for all its employees, students and their parents / guardiansfree from discrimination on any ground and from harassment at work.

The aim of these rules is to create and maintain an effective, timely, fair and equitable grievance handling system for its employees, students and their parents / guardians.

Tikaram Jagannath Arts, Commerce & Sc. College, Khadki will operate a zero-tolerance policy for any form of harassment in the College campus, treat all incidents seriously and promptly investigate all allegations of harassment.

Any person found to have harassed or discriminated another will face disciplinary action, up to and including dismissal from employment.

The key operative principles:

a) To develop a culture of understanding, addressing and providing quick redress to any grievances and take steps to prevent recurrence of such incidents.

b) To set in place a grievance handling system that is student / employee focused.

c) To ensure that any grievance is resolved promptly, objectively and with sensitivity and in complete confidentiality as best as possible.

d) To ensure that the views of each complainant and respondent are respected and that any party to a grievance is neither discriminated against nor victimized.

e) To ensure that there is a consistent response to grievances.

All complaints of harassment or discrimination will be taken seriously and treated with respect and in confidence. No one will be victimised for making such a complaint.

Principal
Tikaram Jagannath College
Khadki, Pune-3.

491, Dr. Babasaheb Ambedkar Road, Khadki, Pune - 411 003.

(Affiliated to Savitribai Phule Pune University - ID / PU / PN / 0146 /1983)

Office : (020) 25811491 Principal : 9890171857 / 7020674545

Web Site : www.tjcollege.org E-mail : admin@tjcollege.org / schakane@gmail.com

KHADKI EDUCATION SOCIETY'S

Tikaram Jagannath
Arts, Commerce & Science College

Principal
Dr. Sanjay Chakane
M.Sc., M.B.A., Ph.D.

MECHANISM ON GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM FOR EMPLOYEES AND STUDENTS

Mechanism for Redressal of Grievance

1) Informal resolution before an issue becomes a formal grievance

2) Complainants will be encouraged to resolve concerns or problems directly with the person(s) / Department concerned through personal discussions / counseling.

3) Grievances of the faculty and staff shall, as far as possible, be resolved by their respective reporting authority.

4) Formal grievances shall be submitted in writing stating full material facts to the Grievance Handling Authority,

5) Formal complaint by the aggrieved person shall be submitted in writing to the Grievance Handling Authority.

6) The authority concerned will start the Redressed process

7)The designated authority may allow an opportunity to the complainant to formally present his / her case along with the relevant documents in support. The authority may also seek clarification from the complainant or call for further material facts having bearing on the matter. Such clarification may be sought by written or verbal request or by face-toface interview with the complainant.

8) The Authority concerned will then endeavour to resolve the grievance as soon as possible and convey the outcome / action taken to the complainant to authority.

9) Wherever required, the University will take preventive or corrective action in a reasonable time and advise the complainant of the same.

10) The concerned Appellate Authority will convey its decision.

11) The decision of the Appellate Authority will be final, and no further appeal will be entertained under any circumstances.

Tikaram Jagannath Arts, Com. & Science College KHADKI PUNE-3

Principal
Tikaram Jagannath College
Khadki, Pune-3.

491, Dr. Babasaheb Ambedkar Road, Khadki, Pune - 411 003.
(Affiliated to Savitribai Phule Pune University - ID / PU / PN / 0146 /1983)
☎ Office : (020) 25811491 Principal : 9890171857 / 7020674545
Web Site : www.tjcollege.org E-mail : admin@tjcollege.org / schakane@gmail.com

KHADKI EDUCATION SOCIETY'S

Tikaram Jagannath
Arts, Commerce & Science College

Principal

Dr. Sanjay Chakane
M.Sc., M.B.A., Ph.D.

INTERNAL COMPLAINT COMMITTEE

1.Prof.Arati Cholekar	Presiding Officer
2.Adv. Deshpande	Member
3.API.Sharda Walkoli (Khadki Police Station)	Member
4.Mrs.Sapna Chhajed	NGO, Member
5.Prof.Archana Taru	Faculty Member
6.Prof.kavita Chavan	Faculty Member
7.Mrs.Aruna Awate	Administrative Staff Member

Tikaram Jagannath Arts, Com. & Science College ★ KHADKI PUNE-3

for Rajendiraa
PRINCIPAL
Tikaram Jagannath Arts Commerce & Science College,Khadki,Pune-411003.

491, Dr. Babasaheb Ambedkar Road, Khadki, Pune - 411 003.
(Affiliated to Savitribai Phule Pune University - ID / PU / PN / 0146 /1983)
☎ Office : (020) 25811491 Principal : 9890171857 / 7020674545
Web Site : www.tjcollege.org E-mail : admin@tjcollege.org / schakane@gmail.com

Date :- 15/04/23

Khadki Education Society's

Tikaram Jagannath Arts, Commerce & Science College, Khadki Pune-03

Notice

To,
The Members of ICC,
All the members of Internal Complaint Committee of T.J.College are hereby informed that Annual Meeting of ICC is scheduled on 19/04/23 at meeting room next to Principles Office at 11.30 am

Prof.Arati Cholekar
Presiding Officer

INTERNAL COMPLAINT COMMITTEE

1. Prof.Arati Cholekar	Presiding Officer
2.Adv. Deshpande	Member
3.API.Sharda Walkoli (Khadki Police Station)	Member
4.Mrs.Sapna Chhajed	NGO, Member
5.Prof.Archana Taru	Faculty Member
6.Prof.kavita Chavan	Faculty Member
7.Mrs.Aruna Awate	Administrative Staff Member

Tikaram Jagannath Arts, Comm. & Science College KHADKI PUNE-3

Annual Report of the ICC meeting of T.J.College

The annual meeting of the ICC was held on the 19/04/23.following members of the committee were present. No complaint till date had been received and zero tolerance policy was followed in the campus.

INTERNAL COMPLAINT COMMITTEE

1.Prof.Arati Cholekar	Presiding Officer
2.Adv. Deshpande	Member
3.API.Sharda Walkoli (Khadki Police Station)	Member
4.Mrs.Sapna Chhajed	NGO, Member
5.Prof.Archana Taru	Faculty Member
6.Prof.kavita Chavan	Faculty Member
7.Mrs.Aruna Awate	Administrative Staff Member

Tikaram Jagannath Arts, Com. & Science College KHADKI PUNE-3

Notice of ICC Meeting of T. J. College Pune

Date : 1/09/2022

To,

The Members of ICC,

All the Members of Internal Complaints Committee of T. J. College are hereby informed that, Meeting of Internal complaints committee Under the Sexual Harassment of Women of Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and Rules, 2014 of T. J. College is scheduled on 7/09/2022 at Meeting Room next to Principal's office, T. J. College at 11.30 am.

Prof.. Arati Cholekar

Presiding officer

PRINCIPAL
Tikaram Jagannath Arts Commerce & Science College, Khadki Pune-411003.

Tikaram Jagannath Arts, Com. & Science College ★ KHADKI PUNE-3

Received the Notice of ICC meeting of T.J. College Scheduled on 7-09-2022 at meeting room, T.J. College Pune.

1. Prof. Archana Tam ASkaranje 1/09
2. Prof. Kavita Charan Kavit
3. Aruna Awate Awate
4. Adv. Deshpande
5. Mrs. Sapna Chhajed.

Tikaram Jagannath Arts, Com. & Science College ★ KHADKI PUNE-3

Proceedings of the ICC meeting of T.J. College Held on 7/9/2022 at meeting Room, Next to Principal's office T. J. College, Khadki Pune at 11.30 a.m.

Prof. Mrs. Arati S. Cholekar welcomed the members for today's meeting of ICC

Subject 1 - The mechanism of the grivance redressal is discussed. No other complaint is issued, zero tolerance situation must be followed in the campus.

Subject 2 - Any other subject with prior permission of the residing officer. Presiding officer of the meeting informed the members present for the meeting that, no additional subject has been ~~sepre~~ referenced to her for ~~additional subject has been~~ discussi under this agenda item & hence precidin officer directed that the meeting is concluded.

Tikaram Jagannath Arts, Com. & Science College KHADKI PUNE-3

Prof. Arati Cholekar (Presiding officer)

1) Prof. Archana Taru
2) Prof. Kavita Chavan
3) Aruna Awate

Date :- 17/01/23

Notice of ICC Meeting of T.J. College

To,

The members of ICC,

All the members of Internal Complaint Committee of T.J. College are hereby informed that meeting is scheduled on 20/01/23 at meeting room next to Principal's office, at 11.30 am.

Prof. Arati Cholekar
Presiding Officer

Tikaram Jagannath Arts, Com. & Science College
KHADKI PUNE-3

Received the notice of ICC Meeting of. T. J. College Scheduled on 20/01/23 at meeting room.

1. Kavita Chavan (faculty member) Kavita
2. Prof. Archana Taru (member) ASTaru
3. Aruna Awate Awate
4. API Sharda Walkoli
5. Sapna Chhajed.

Tikaram Jagannath Arts, Com. & Science College ★ KHADKI PUNE-3

Procedings of the ICC meeting of T.J. College Held on 20/01/2023 at meeting Room, Next to Principal's office, T.J. College, Khadki, Pune at 11.30 a.m.

Prof. Mrs. Arati S. Cholekar welcomed the members for today's meeting of ICC

Subject 1 :- The mechanism of grivance redressal is discussed. No other complaint is issued. Zero tolerance situation must be followed in the campus.

Subject - Any other subject with prior permission of residing officer, presiding officer of the meeting informed the members present ~~the~~ for the meeting that, no additional subject has been ~~issued~~ referenced to her for discussion under this agenda item & hence preciding officer directed that the meeting is concluded.

Tikaram Jagannath Arts, Com. & Science College ★ KHADKI PUNE-3

Prof. Arati Cholekar
(Presiding officer)

1) Prof. Archna Taru
2) Prof. Kavita Chavan
3) Aruna Awate -

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ
विद्यार्थी विकास मंडळ
महाविद्यालय तक्रार निवारण कक्ष - २०२२-२०२३

महाविद्यालयाचे नाव	:	Khadki Shikshan Sanstha Tikaram Jagannath Arts Commerce & Science College Addr: Elphiston Road Khadki Ta: Pune (corporation Area) Dist: Pune
महाविद्यालय स्थापना	:	1983
प्राचार्य	:	Sanjay Dnyaneshwar Chakane
प्राचार्य नियुक्ती	:	Permanent
संपर्क क्र.	:	9890171857

महाविद्यालय तक्रार निवारण कक्ष

अ.क्र	समितीचे सदस्य		पदाचे नाव	सदस्यांची नावे
१	प्राचार्य/संचालक	:	अध्यक्ष	Sanjay Dnyaneshwar Chakane
२	वरिष्ठ अध्यापक	:	सदस्य	Kamble Balasabeb Shrirang
३	वरिष्ठ अध्यापक	:	सदस्य	Taru Archana Sachin

G. Mahekar
Students Development Officer
Tikaram Jagannath Arts, Commerce and Science College
Khadki, Pune-411003.
विद्यार्थी विकास अधिकारी (S.D.O)
स्वाक्षरी

Tikaram Jagannath Arts, Com. & Science College KHADKI PUNE-3
महाविद्यालयाची
मोहोर

PRINCIPAL
Tikaram Jagannath Arts Commerce &
Science College,Khadki,Pune-411003.
प्राचार्य
स्वाक्षरी व मोहोर

PRINCIPAL
Tikaram Jagannath Arts Commerce &
Science College,Khadki,Pune-411003.

5.1.410

KHADKI EDUCATION SOCIETY'S

Tikaram Jagannath Arts, Commerce & Science College

Principal

Dr. Sanjay Chakane

M.Sc., M.B.A., Ph.D.

ANTI RAGGING COMMITTEE

1.Dr. Sanjay Chakane - Principal, Chairperson

2. Prof. Arun Shelar - Vice Principal, Coordinator

3. Prof. Archana Taru - Member

PRINCIPAL
Tikaram Jagannath Arts Commerce & Science College,Khadki,Pune-411003.

Tikaram Jagannath Arts, Com. & Science College KHADKI PUNE-3

491, Dr. Babasaheb Ambedkar Road, Khadki, Pune - 411 003.

(Affiliated to Savitribai Phule Pune University - ID / PU / PN / 0146 /1983)

☎ **Office :** (020) 25811491 **Principal :** 9890171857 / 7020674545

Web Site : www.tjcollege.org **E-mail :** admin@tjcollege.org / schakane@gmail.com

वि.कं.मं.नोंदणी क्रमांक :- PC023

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ
विद्यार्थी कल्याण मंडळ

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

Academic Year - 2022-2023 (Semester2)

Proforma for monitoring the directions of Hon'ble Supreme Court of India on measures against Ragging in educational institutions

Sr.No		
	Name of Institute / College	Khadki Shikshan Sanstha Tikaram Jagannath Arts Commerce & Science College Addr: Elphiston Road Khadki Tal: Pune (corporation Area) Dist: Pune Pincode: 411003
	Principal Name	Sanjay Dnyaneshwar Chakane
1	**Whether Anti ragging Squads were Constituted ?**	Yes
2	**Whether Anti ragging Committees were Constituted ?**	Yes
3	**Whether prospectus mention possible actions against Ragging ?**	Yes-YES
4	**Whether names,telephone nos. of authorities to be contacted have been publicized / made available to Freshers?**	
5	**Whether students are allowed free access to phone (cell & Landline) in hostel(s) for timely reporting?**	
6	**Whether Seniors counseled?**	Yes
7	**Whether Freshers counseled?**	
8	**Whether oriantation courses for freshers counseled?**	
9	**Anti Ragging Squads -**	
	9 (a) Date of Formation	15/07/2022
	9 (b) No.of Members	5
	9 (c) Names of Members	1.Prof. Arun Shelar
	9 (d) No . of raids	0
	9 (e) Frequency of ralds	00
	9 (f) Surprise raids	00
	9 (g) Others Measures taken by the squad	00
	9 (h) No.of cases detected	00
	9 (i) Action taken as follow up	00
10	**Anti Ragging Committee -**	
	10 (a) Date of Formation	15/07/2022
	10 (b) No.of Members	5
	10 (c) Names of Members	1.Prof. Arun Shelar
	10 (d) No . of raids	0
	10 (e) Frequency of raids	00
	10 (f) Surprise raids	00

Tikaram Jagannath Arts, Com. & Science College ★ KHADKI PUNE-3

वि.कं.मं.नोंदणी क्रमांक :- PC023

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ
विद्यार्थी कल्याण मंडळ

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

Academic Year - 2022-2023 (Semester2)

	10 (g) Others Measures taken by the squad	00
	10 (h) No.of cases detected	00
	10 (i) Action taken as follow up	00
11	Inquiry(ies) Conducted ?	00
12	Panishment meted out ?	
	12 (a) Suspension	No
	12 (b) Rustication	No
	12 (c) Expulsion	No
13	No. of F.I.R.(s) lodged by institution with details	00
14	As per UGC norms online undertaking forms submitted from students,Mention students count	Yes 00

Signature and Stamp
Principal/Director
Tikaram Jagannath Arts Commerce & Science College,Khadki,Pune-411003.

Tikaram Jagannath Arts, Com. & Science College ★ KHADKI PUNE-3

Khadki Education Society's
Tikaram Jagannath Arts, Commerce & Science College, Khadki Pune-03

Notice Date:- 26/04/23

Subject :-Anti Ragging Committee

This is to inform you that there will be a Anti Ragging Committee meeting on 28/04/23 @ 11.00am. You are requested to be in the meeting at least 5 minutes earlier to the scheduled time

Venue :- Conference Hall

PRINCIPAL
Tikaram Jagannath Arts Commerce & Science College,Khadki,Pune-411003.

1) Prof. Gauri Matekar (SDO) Gauri

2) Prof. Arun Shelar.

3) Archana Tanu 26/04

Tikaram Jagannath Arts, Com. & Science College KHADKI PUNE-3

K.E.S.

Tikaram Jagannath Arts ,Commerce & Science College Khadki ,Pune 03

Anti-Ragging Committee 2022-2023

Annual Meeting Report Dated 28/04/2023.

The annual meeting of Anti-Ragging Committee was held on 28/04/23. The following members of the committee were present. No complaint had been received and zero tolerance policy was followed in the campus.

PRINCIPAL
Tikaram Jagannath Arts Commerce & Science College,Khadki,Pune-411003.

1) प्रा. गौरी माटेकर

2) प्रा. अरुणा शेलार

3) Archana Tanu

Tikaram Jagannath Arts, Com. & Science College ★ KHADKI PUNE-3

K.E.S

Tikaram Jagannath Arts,Commerce And Science College Pune-03

Academic Year 2022-23

Anti Ragging Committee

दि. 23/06/2022

सभेची सूचना

अॅन्टी रॅगिंग कमिटीतील सर्व सदस्यांची सभा दि. 28/06/2022 रोजी सकाळी 10:00 वाजता आयोजित करण्यात आली आहे. तरी सर्व सदस्यांनी वेळेवर उपस्थित राहावे.

प्रा. गौरी माटेकर
S.W.O

डॉ. संजय चाकणे
प्राचार्य.
PRINCIPAL
Tikaram Jagannath Arts Commerce & Science College,Khadki,Pune-411003.

सभेचे विषय :-

१. प्रवेश अर्ज भरतेवेळी विद्यार्थ्यांकडून Anti-Ragging form भरून घेणे.

२. विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयाची शिस्त व नियम याबाबत चर्चा करणे.

समिती सदस्य :- अर्चना तारू

Tikaram Jagannath Arts, Com. & Science College KHADKI PUNE-3

K.E.S

Tikaram Jagannath Arts,Commerce And Science College Pune-03

Academic Year 2022-23

Anti Ragging Committee

दि. २६/०६/२०२२

आज शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मधील नव्याने प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून Anti-Ragging चे forms भरून घेण्याबाबत सभा घेण्यात आली.

सभेमधील विषय पुढीलप्रमाणे :-

1) नव्याने प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून Anti-Ragging चे form भरून घेण्यात यावेत.

2) महाविद्यालयात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्नशील राहावे.

3) विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयाच्या Campus मध्ये ओळखपत्र सक्तीचे व अनिवार्य करण्यात यावे.

प्रा. गौरी मारटेकर
SWO

डॉ. संजय चाकणे
PRINCIPAL
Tikaram Jagannath Arts Commerce & Science College,Khadki,Pune-411003,

या सभेला खालील समिती सदस्य उपस्थित होते.

(1)

(2) अर्चना तारु Asfaranje

Tikaram Jagannath Arts, Com College KHADKI PUNE-3

वि.कं.मं.नोंदणी क्रमांक :- PC023

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ
विद्यार्थी कल्याण मंडळ

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

Academic Year - 2022-2023 (Semester1)

Proforma for monitoring the directions of Hon'ble Supreme Court of India on measures against Ragging in educational institutions

Sr.No		
	Name of Institute / College	Khadki Shikshan Sanstha Tikaram Jagannath Arts Commerce & Science College Addr: Elphiston Road Khadki Tal: Pune (corporation Area) Dist: Pune Pincode: 411003
	Principal Name	Sanjay Dnyaneshwar Chakane
1	Whether Anti ragging Squads were Constituted ?	Yes
2	Whether Anti ragging Committees were Constituted ?	Yes
3	Whether prospectus mention possible actions against Ragging ?	Yes-UGC Act
4	Whether names,telephone nos. of authorities to be contacted have been publicized / made available to Freshers?	
5	Whether students are allowed free access to phone (cell & Landline) in hostel(s) for timely reporting?	
6	Whether Seniors counseled?	Yes
7	Whether Freshers counseled?	
8	Whether oriantation courses for freshers counseled?	
9	Anti Ragging Squads -	
	9 (a) Date of Formation	15/07/2022
	9 (b) No.of Members	5
	9 (c) Names of Members	1.Prof. Arun Shelar
	9 (d) No . of raids	0
	9 (e) Frequency of raids	00
	9 (f) Surprise raids	00
	9 (g) Others Measures taken by the squad	00
	9 (h) No.of cases detected	00
	9 (i) Action taken as follow up	00
10	Anti Ragging Committee -	
	10 (a) Date of Formation	15/07/2022
	10 (b) No.of Members	5
	10 (c) Names of Members	1.Prof. Arun Shelar
	10 (d) No . of raids	0
	10 (e) Frequency of raids	00
	10 (f) Surprise raids	00

Tikaram Jagannath Arts, Comm. & Science College ★ KHADKI PUNE 03

KHADKI EDUCATION SOCIETY'S

Tikaram Jagannath
Arts, Commerce & Science College

Principal

Dr. Sanjay Chakane
M.Sc., M.B.A., Ph.D.

STUDENTS' GRIEVANCE REDRESSAL CELL

1.Dr. Sanjay Chakane - Principal, Chairperson

2.Dr. Arjun Musmade - Coordinator

3.Prof. Kamble Balasaheb Shrirang - Member

4.Prof. Archana Taru - Member

Tikaram Jagannath Arts, Com. & Science College KHADKI PUNE

PRINCIPAL
Tikaram Jagannath Arts Commerce & Science College,Khadki,Pune-411003.

EAL2200183

वि.वि.मं.नोंदणी क्रमांक :- PC023

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ
विद्यार्थी विकास मंडळ

महाविद्यालयाचे नाव व पत्ता	:	खडकी शिक्षण संस्था टिकाराम जगन्नाथ कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय पत्ता: एलफिस्टन रोड खडकी ता.: पुणे (महानगर पालिका हद्द) जि: पुणे पिनकोड: 411003			
महाविद्यालय स्थापना	:	1983	महाविद्यालय अनुदानाचा प्रकार	:	अनुदानीत
प्राचार्य	:	संजय ज्ञानेश्वर चकणे	प्राचार्य नियुक्ती	:	कायम
विद्यार्थी विकास अधिकारी	:	जाधव गौरी गंगाधर	नेमणूक मान्यता	:	होय
महाविद्यालयातील एकूण सहभागी विद्यार्थी संख्या	:	0	महाविद्यालयातील शिक्षकांची संख्या	:	45
मागील शैक्षणिक वर्षात कमवा व शिका योजना राबविली होती का?	:	नाही			

		प्रवर्ग								
मुले	मुली	खुला	अनुसूचीत जाती	अनुसूचीत जमाती	भटक्या व विमुक्त जाती	विशेष मागासवर्ग	अल्पसंख्यांक	निराधार	विशेष विद्यार्थी	सहभागी एकूण विद्यार्थी
मुले	मुली	0	0	0	0	0	0	0	0	0

मागील शैक्षणिक वर्षासाठी विद्यापीठाकडून प्राप्त झालेली रक्कम	:	रु.	0	अक्षरी रु	

पदवी स्तर एकूण विद्यार्थी									
खुला	अनुसूचीत जाती	अनुसूचीत जमाती	भटक्या व विमुक्त जाती	इतर मागास वर्ग	विशेष मागासवर्ग	अल्पसंख्यांक	निराधार	विशेष विद्यार्थी	सहभागी एकूण विद्यार्थी
1340	660	132	156	325	24	0	0	3	2640

पदव्युत्तर स्तर एकूण विद्यार्थी									
खुला	अनुसूचीत जाती	अनुसूचीत जमाती	भटक्या व विमुक्त जाती	इतर मागास वर्ग	विशेष मागासवर्ग	अल्पसंख्यांक	निराधार	विशेष विद्यार्थी	सहभागी एकूण विद्यार्थी
120	72	18	9	9	2	0	0	0	230

महाविद्यालयाचा परिसर					
ग्रंथालय	:	होय	शेती	:	नाही
उद्यान	:	होय	परिसर स्वच्छता	:	होय
प्रयोगशाळा	:	होय	कार्यालय	:	होय
इतर	:	होय	क्रीडांगण	:	होय
भांडार	:	नाही	हॉस्टेल	:	नाही
भोजनशाळा	:	नाही	सोलर पॅनल	:	नाही

विद्यार्थी तक्रार निवारण कक्ष

अ.क्र	समितीचे सदस्य		पदाचे नाव	सदस्यांची नावे
१	प्राचार्य/संचालक	:	अध्यक्ष	Sanjay Dnyaneshwar Chakane
२	वरिष्ठ अध्यापक	:	सदस्य	Kamble Balasabeb Shrirang
३	वरिष्ठ अध्यापक	:	सदस्य	Taru Archana Sachin

120

विद्यार्थी तक्रार निवारण समिती

शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३

सूचना

दि० 10/02/23

विद्यार्थी तक्रार निवारण समितीची सभा दि.13/02/23 रोजी ठिक सकाळी ११:०० वाजता आयोजित केली आहे. या सभेस खालील सदस्यांनी प्राचार्य कार्यालयात उपस्थित राहावे.

शिक्षक समिती

PRINCIPAL
Tikaram Jagannath Arts Commerce & Science College,Khadki,Pune-411003.

डॉ. अर्जुन मुसमाडे 13/02/23

अर्चना तारू

Tikaram Jagannath Arts, Com. & Science College * KHADKI PUNE-3

विद्यार्थी तक्रार निवारण समिती

शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३

विद्यार्थी तक्रार निवारण समितीची सभा दि. १९ ऑगस्ट २२ रोजी सकाळी ११:०० वाजता आयोजित करण्यात आली होती. या सभेत खालील सभासद उपस्थित होते.

1. प्रा. डॉ. संजय चाकणे — अध्यक्ष
2. प्रा. बाळासाहेब कोबळे — सदस्य
3. अर्चना तारू — सदस्य
4. डॉ. अर्जुन मुसमाडे — सदस्य

PRINCIPAL
Tikaram Jagannath Arts Commerce & Science College,Khadki,Pune-411003

सभेमधील विषय पुढीलप्रमाणे:

या सभेमध्ये विद्यार्थ्यांशी संबंधित कुठलीही तक्रार नसल्यामुळे पुढील सत्रात होणाऱ्या सभेचे नियोजन करण्यात आले. या सभेस वरील सर्व सदस्य उपस्थित होते.

Tikaram Jagannath Arts, Com. & Science College KHADKI PUNE-3

विद्यार्थी तक्रार निवारण समिती

शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३

दि. १७/०८/२०२२

सूचना

विद्यार्थी तक्रार निवारण समितीची सभा दि.१९ ऑगस्ट रोजी ठिक सकाळी ११:०० वाजता आयोजित केली आहे. या सभेस खालील सदस्यांनी प्राचार्य कार्यालयात उपस्थित राहावे.

शिक्षक समिती

PRINCIPAL
Tikaram Jagannath Arts Commerce & Science College,Khadki,Pune-411003.

19/8/2022

अर्चना तारळ

Karanje

Tikaram Jagannath Arts, Com. & Science College * KHADKI PUNE-3

विद्यार्थी तक्रार निवारण समिती

शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३

विद्यार्थी तक्रार निवारण समितीची सभा दि. १३/०२/२३ रोजी सकाळी ११:०० वाजता आयोजित करण्यात आली होती. या सभेत खालील सभासद उपस्थित होते.

1. प्रा० डॉ० संजय चाकणे अध्यक्ष
2. प्रा. बाळासाहेब कोकणे सदस्य
3. अर्चना ताठे सदस्य
4. डॉ. अर्जुन मुसमाडे सदस्य

13/02/23

सभेमधील विषय पुढीलप्रमाणे:

या सभेमध्ये विद्यार्थ्यांशी संबंधित कोणतीही तक्रार नसल्या कारणाने सभा स्थगित करण्यात आली.

या सभेसाठी वरील सर्व समिती सदस्य उपस्थित होते.

Tikaram Jagannath Arts, Com. & Science College ★ KHADKI PUNE-3

K.E.S

Tikaram Jagannath Arts,Commerce And Science College Pune-03

Academic Year 2022-23

Anti Ragging Committee

दि० 02/09/2023

सभेची सूचना

ॲन्टी रॅगिंग कमिटीतील सर्व सदस्यांची सभा दि. ०३/०९/2023 रोजी सकाळी १०.०० वाजता आयोजित करण्यात आली आहे. तरी सर्व सदस्यांनी वेळेवर उपस्थित रहावे.

प्रा. गौरी माटेकर
इ.ध.०

डॉ. संजय चाकणे
प्राचार्य

PRINCIPAL
Tikaram Jagannath Arts Commerce & Science College,Khadki,Pune-411003.

सभेचे विषय :

१. वार्षिक सर्व साधारण सभा

अर्चना तारु

Tikaram Jagannath Arts, Com. & Science College KHADKI PUNE-3

K.E.S

Tikaram Jagannath Arts,Commerce And Science College Pune-03

Academic Year 2022-23

Anti Ragging Committee

दि. 09/09/2023

आज दि. 09/09/2023 रोजी ॲन्टीरॅगिंग कमिटीतील सर्व सदस्यांची सभा घेण्यात आली.

सभेमधील विषय पुढीलप्रमाणे:

१. सर्व वर्गातील विद्यार्थ्यांकडून विषय शिक्षकांनी माहिती गोळी (अनौपचारिक पद्धतीने) केली. कुठल्याही प्रकारे

रॅगिंगची घटना किंवा तक्रार आली नाही.

प्रा. गौरी मोटेकर
S.W.O

डॉ. संजय चाकणे
PRINCIPAL
Tikaram Jagannath Arts Commerce & Science College,Khadki,Pune-411003.

या सभेला खालील समिती सदस्य उपस्थित होते.

अर्चना तारू

Tikaram Jagannath Arts, Com. & Science College KHADKI PUNE-3

Khadki Education Society's
Tikaram Jagannath Arts, Commerce & Science College, Khadki Pune-03

Notice Date:- 10/04/2023

Subject :-Student Grievance Redressal Cell

This is to inform you that there will be a Grievance Redressal Cell meeting on 12/04/2023@11.00am You are requested to be in the meeting at least 5 minutes earlier to the scheduled time

venue :- Conference Hall

1) Dr. Arjun Musmade 10/04/2023

2) Prof. Balasaheb Kamble

3) Archana Tanu

PRINCIPAL
Tikaram Jagannath Arts Commerce & Science College,Khadki,Pune-411003.

Tikaram Jagannath Arts, Com. & Science College ★ KHADKI PUNE-3

Khadki Education Society's
Tikaram Jagannath Arts, Commerce & Science College, Khadki Pune-03

Subject :-Annual Meeting Of Student Grievance Redressal Cell

Annual meeting Report Dated 12/4/2023

The annual meeting of student Grievance Redressal cell was held on 12/4/2023. The following members of the committee were present. No complaint had been received & zero tolerance policy was followed in the campus.

Dr. Sanjay Chakane.
PRINCIPAL
Tikaram Jagannath Arts Commerce & Science College,Khadki,Pune-411003.

1) Dr. Arjun Musmade
2) Prof. Balasaheb Kamble
3) Archana Tam

Tikaram Jagannath Arts, Com. & Science College ★ KHADKI PUNE-3

वि.क.मं.नोंदणी क्रमांक :- PC023

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ
विद्यार्थी कल्याण मंडळ

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

Academic Year - 2022-2023 (Semester1)

Proforma for monitoring the directions of Hon'ble Supreme Court of India on measures against Ragging in educational Institutions

Sr.No		
	Name of Institute / College	Khadki Shikshan Sanstha Tikaram Jagannath Arts Commerce & Science College Addr: Elphiston Road Khadki Tal: Pune (corporation Area) Dist: Pune Pincode: 411003
	Principal Name	Sanjay Dnyaneshwar Chakane
1	Whether Anti ragging Squads were Constituted ?	Yes
2	Whether Anti ragging Committees were Constituted ?	Yes
3	Whether prospectus mention possible actions against Ragging ?	Yes-UGC Act
4	Whether names,telephone nos. of authorities to be contacted have been publicized / made available to Freshers?	
	Whether students are allowed free access to phone (cell & Landline) in hostels for timely reporting?	
6	Whether Seniors counseled?	Yes
7	Whether Freshers counseled?	
8	Whether oriantation courses for freshers counseled?	
9	Anti Ragging Squads -	
	9 (a) Date of Formation	15/07/2022
	9 (b) No.of Members	5
	9 (c) Names of Members	1.Prof. Arun Shelar
	9 (d) No . of raids	0
	9 (e) Frequency of raids	00
	9 (f) Surprise raids	00
	9 (g) Others Measures taken by the squad	00
	9 (h) No.of cases detected	00
	9 (i) Action taken as follow up	00
10	Anti Ragging Committee -	
	10 (a) Date of Formation	15/07/2022
	10 (b) No.of Members	5
	10 (c) Names of Members	1.Prof. Arun Shelar
	10 (d) No . of raids	0
	10 (e) Frequency of raids	00
	10 (f) Surprise raids	00

वि.कं.मं.नोंदणी क्रमांक :- PC023

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ
विद्यार्थी कल्याण मंडळ

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

Academic Year - 2022-2023 (Semester2)

Proforma for monitoring the directions of Hon'ble Supreme Court of India on measures against Ragging in educational institutions

Sr.No		
	Name of Institute / College	Khadki Shikshan Sanstha Tikaram Jagannath Arts Commerce & Science College Addr: Elphiston Road Khadki Tal: Pune (corporation Area) Dist: Pune Pincode: 411003
	Principal Name	Sanjay Dnyaneshwar Chakane
1	Whether Anti ragging Squads were Constituted ?	Yes
2	Whether Anti ragging Committees were Constituted ?	Yes
3	Whether prospectus mention possible actions against Ragging ?	Yes-YES
4	Whether names,telephone nos. of authorities to be contacted have been publicized / made available to Freshers?	
5	Whether students are allowed free access to phone (cell & Landline) in hostel(s) for timely reporting?	
6	Whether Seniors counseled?	Yes
7	Whether Freshers counseled?	
8	Whether oriantation courses for freshers counseled?	
9	Anti Ragging Squads -	
	9 (a) Date of Formation	15/07/2022
	9 (b) No.of Members	5
	9 (c) Names of Members	1.Prof. Arun Shelar
	9 (d) No . of raids	0
	9 (e) Frequency of raids	00
	9 (f) Surprise raids	00
	9 (g) Others Measures taken by the squad	00
	9 (h) No.of cases detected	00
	9 (i) Action taken as follow up	00
10	Anti Ragging Committee -	
	10 (a) Date of Formation	15/07/2022
	10 (b) No.of Members	5
	10 (c) Names of Members	1.Prof. Arun Shelar
	10 (d) No . of raids	0
	10 (e) Frequency of raids	00
	10 (f) Surprise raids	00

वि.कं.मं.नोंदणी क्रमांक :- PC023

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ
विद्यार्थी कल्याण मंडळ

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

Academic Year - 2022-2023 (Semester2)

	10 (g) Others Measures taken by the squad	00
	10 (h) No.of cases detected	00
	10 (i) Action taken as follow up	00
11	Inquiry(ies) Conducted ?	00
12	Panishment meted out ?	
	12 (a) Suspension	No
	12 (b) Rustication	No
	12 (c) Expulsion	No
13	No. of F.I.R.(s) lodged by institution with details	00
14	As per UGC norms online undertaking forms submitted from students,Mention students count	Yes 00

Tikaram Jagannath Arts, Com. & Science College KHADKI PUNE-3

Signature and Stamp
Principal/Director

PRINCIPAL
Tikaram Jagannath Arts Commerce &
Science College,Khadki,Pune-411003.